चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

03 जून–09 जून 2013

मूल्य 5 रुपये

यह सरकार झूठी है

पेज : 3

जन विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकें

पेज : 4

श्रमिक, शोषण और सरकार?

पेज : 7

साई की महिमा

पेज : 12

संविधान और जनता का धोखा

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ. लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि बिना जनता को विश्वास में लिए और बिना संसद में संविधान संशोधन लाए, देश का संविधान बदल दिया गया. ऐसा क्यों किया गया? क्यों देश के लोगों से राय लिए बिना ही यह बदल दिया गया? सच तो यह है कि जिन संविधान सभा के सदस्यों ने यह न्यायपूर्ण फ़ैसला किया, उन्होंने न केवल देश के साथ एक बड़ा धोखा किया है, बल्कि संविधान और जनता के साथ भी खिलवाड़ किया है. क्या है संविधान का सच?

संतोष भारतीय

संविधान निर्माताओं ने क्या संविधान सभा के सदस्य के नाते एक चेहरा रखा और संविधान सभा के अलावा प्रोविज़नल पार्लियामेंट (अंतरिम संसद) के सदस्य के नाते दूसरा चेहरा रखा? यह एक सवाल है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा. पर जब घटनाक्रम को सिलसिलेवार देखते हैं, तब लगता है कि ऐसा ज़रूर हुआ है. संविधान सभा की कुर्सी न्याय की कुर्सी थी, जिस पर बैठकर संविधान सभा के सदस्यों ने न्यायपूर्ण फ़ैसला किया. पर अफ़सोस! जब वही लोग अंतरिम संसद के सदस्य के नाते काम करने लगे, तो यह कहने में कोई परहेज़ ही नहीं कि उन्होंने देश के साथ एक बड़ा धोखा किया है. दरअसल, यही दो चेहरे हमारा संविधान बनाने और संविधान सभा द्वारा अंतिरम संसद के रूप में कार्य करने के दौरान हमें देखने को मिलते हैं.

संविधान सभा में देश के भविष्य को लेकर गंभीर बहस हुई. बहस में कहीं पर भी देश को चलाने के लिए राजनीतिक दल की कल्पना नहीं थी. स्वतंत्रता आंदोलन विजय पा चुका था और हिंदुस्तान की आज़ादी लगभग तय हो चुकी थी. संविधान सभा हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने से पहले 1946 में बन चुकी थी. संविधान सभा के सदस्यों ने न्यायपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीक़े से संविधान की रूपरेखा बनाई और उसमें हिंदुस्तान को आदर्श लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक देश बनाने में कोई कोताही नहीं की. संविधान के हिसाब से यह देश लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई सरकार के सहारे चलेगा. लोकसभा में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे और वे वहां पर बहुमत या सर्वसम्मति से अपने लिए सरकार चुनेंगे तथा उस सरकार का एक प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होगा. उन दिनों राजनीतिक दल भी मौजूद थे, लेकिन संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल शब्द का जिक्र इसीलिए नहीं है, क्योंकि संविधान में एक गणतंत्र की कल्पना की गई है. दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र माना जाता है. उस गणतंत्र के अध्ययन से पता चलता है कि गणतंत्र को चलाने वाली सभा में कभी भी पक्ष या विपक्ष नहीं होता. सभी लोग एकसाथ बैठकर गुण या दोष के आधार पर फ़ैसले लेते हैं और राज्य को चलाते हैं. इसी के आधार पर संविधान निर्माताओं ने संविधान में राजनीतिक दल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और संविधान सभा भी दलीय आधार पर नहीं चली. वह एक आदर्श गणतंत्र की संविधान सभा के रूप में ही काम करती रही.

तब आख़िर ऐसा क्या हुआ और कहां से यह राजनीतिक दल शब्द संसद के भीतर नज़र आया. हुआ यूं कि संविधान बनाते समय संविधान सभा के सदस्यों ने न्यायाधीश की तरह काम किया और एक ऐसा संविधान बनाया, जो भारत में सचमुच जनतंत्र का निर्माण करने वाला था. जब संविधान बन गया और यह संविधान 1950 में अंतरिम संसद में पास हो गया, तब राजनेताओं के कान खड़े हुए और उन्हें राजनीति नज़र आई और तभी से उन्होंने यह सोचना भी शुरू किया कि उनसे बहुत बड़ी ग़लती हो गई. अगर संविधान 26 जनवरी, 1950 को पास न हुआ होता, तो शायद संविधान का पन्ना ही बदला जाता, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे राजनेताओं ने न्यायाधीशों की तरह ही व्यवहार किया और उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचा, जो राजनीति को हमेशा अपने कब्जे में रखने के रूप में सोची जा सकती हैं.

1950 में संविधान को अंतरिम संसद ने स्वीकार किया, क्योंकि 1952 तक संविधान सभा ही दोनों काम कर रही थी. पहले उसने संविधान बनाया और फिर उसी ने उसे भी स्वीकार किया और छोटे-मोटे क़ानून बनाए. जब चुनाव आयोग बन गया (चुनाव आयोग की कल्पना संविधान में है), तब अचानक राजनेताओं को ध्यान आया कि पार्टियों को भी संसद में लाना है. संविधान के अनुसार जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यदि संसद में आ गए, तो पार्टियों का अस्तित्व संसद में समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जनतंत्र के खिलाफ पार्टी तंत्र को चुनाव आयोग के सहारे क़ानून बना कर दाख़िल कर दिया. दरअसल, इनका विश्वास था कि पार्टियां ही देश चला सकती हैं, इसलिए उन्होंने 1951 में जनप्रतिनिधित्व क़ानून पास किया. जनप्रतिनिधित्व क़ानून भी अंतरिम संसद ने पास किया. दरअसल, इसी के तहत राजनीतिक दलों ने चुनाव में हिस्सा लेने और अपने उम्मीदवार खड़ा करने की राह बनाई. चुनाव आयोग ने इसके आधार पर 1952 का आम चुनाव कराया, जिसमें लगभग 348 सीटें कांग्रेस को मिलीं और बाक़ी 100 सीटें दूसरे छोटे-मोटे दलों में बंट गईं.

अब सवाल यह उठता है कि भारत की जनता के भाग्य को अपनी मुट्ठी में बंद करने और लोकतंत्र को राजनीतिक पार्टियों की कैद में ले जाने के पीछे मुख्य दिमाग़ किसका था? उस समय वे सारे लोग मौजूद थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सज़ाएं काटीं और लड़ाइयां भी लड़ीं. इनमें से कुछ के ऊपर गांधी जी को बहुत ज़्यादा विश्वास था. ये सारे लोग उस समय ज़िंदा थे, जब 1951 का जनप्रतिनिधित्व क़ानून बना. सिर्फ़ एक शख्स हमारे बीच उस समय नहीं था, आज़ादी के आंदोलन का नेता, यानी मोहनदास करमचंद गांधी. आख़िर किस नेता के दिमाग़ में यह बात आई होगी कि राजनीतिक पार्टियों को चोर दरवाज़े से लोकसभा, विधानसभा या भारत की राजनीति में घुसा देना है. इनमें से कोई भी हो सकता है. राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल उनके कैबिनेट में थे. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, मौलाना आज़ाद एवं गोविंद वल्लभ पंत भी जिंदा थे. इन सारे लोगों ने बैठकर चुनाव आयोग के ज़रिए चोर दरवाजे से राजनीतिक दलों को लोकसभा में पहुंचा दिया. शायद यह इतिहास के गर्भ में रह जाएगा कि हिंदुस्तान की जनता के हित और संविधान के हित के ख़िलाफ़ आख़िर कोशिश की, तो किसने की? क्या कोई एक इसके लिए ज़िम्मेदार था, या ये सारे नेता ज़िम्मेदार थे?

दरअसल, इसका नतीजा बहुत भयानक निकला. पहली लोकसभा का समय बीत गया और दूसरी लोकसभा से लोकतंत्र का क्षरण होना शुरू हो गया. नतीजे के तौर पर देश की राजनीति में धीरे-धीरे भ्रष्टाचार घुसने लगा और पहली बार दूसरी लोकसभा के दौरान कुछ बड़े स्कैंडल भी सामने आए. आज अगर हम भ्रष्टाचार की जड़ तलाशें, तो वह चोर दरवाजे से घुसाए गए पार्टी सिस्टम में नज़र आती है. एक मजेदार चीज. अगर कोई क़ानून संविधान से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस क़ानून (जनप्रतिनिधित्व क़ानून 1951) के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ही नहीं उठी, जबकि यह संविधान की किसी भावना के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियों को भारत की संसद में घुसाना था, तो यह संविधान संशोधन द्वारा हो सकता था, लेकिन उस समय के नेताओं को डर था कि अगर उन्होंने तत्काल संविधान संशोधन किया, तो देश के लोगों को उनकी ईमानदारी पर शक हो जाएगा और इसीलिए यह किस्सा 1985 तक चला आया. पहली बार 1985 में संविधान संशोधन में पॉलिटिकल पार्टीज़ शब्द का इस्तेमाल हुआ, जब एंटी डिफेक्शन बिल संसद में आया. उस समय किस तरह से राजनीतिक दल में फ़ैसले होंगे, संसदीय दल में कैसे कोई निकाला जाएगा, कैसे बर्खास्त होगा, कैसे उसकी सदस्यता जाएगी, आदि-आदि चीजें 1985 में संविधान में जुड़ीं.

अब सवाल उठता है कि अगर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोज़गारी की जड़ में पार्टी सिस्टम है, तो क्या इस पार्टी सिस्टम के ऊपर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? दूसरा सवाल, अगर यह पार्टी सिस्टम मूल संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है, तो क्या इसके ऊपर देश के लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तीसरी चीज़, क्या यह सवाल सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग से नहीं पूछना चाहिए कि जिस समय यह क़ानून बना था, उस समय के संविधान के लिहाज़ से क्या यह क़ानून सही है? हम देश में संविधान का शासन चलाने की बात करते हैं, हर आदमी यह दुहाई देता है कि इसमें संविधान का शासन है और संविधान के हिसाब से क़ानून बनाए जाते हैं, लेकिन सच यही है कि देश और जनता के हाथ से लोकतंत्र में सीधे सहभागिता का अवसर इस क़ानून ने छीन लिया है. दरअसल, आज राजनीतिक पार्टियां इस बात को सोचना ही नहीं चाहतीं कि आम जनता की भी कोई हिस्सेदारी शासन चलाने में हो सकती है! इस सोच का दूसरा परिणाम यह निकला कि हिंदुस्तान की जितनी भी लोकतांत्रिक या संवैधानिक संस्थाएं थीं, वे धीरे-धीरे मरने और ख़त्म होने लगीं या सरकारों ने उन्हें अपने शिकंजे में लेने की कोशिश शुरू कर दी. पार्लियामेंट का नक्शा कुछ यूं बना कि राजनीतिक दल अपने हित के हिसाब से उसे इधर से उधर घुमाने और नचाने लगे. आम जनता पार्लियामेंट के अंदर होने वाले नाटक को सकते की नज़र से देखती रही, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और इस स्थिति ने लोगों के अंदर धीरे-धीरे लोकतंत्र के प्रति आस्था और अनास्था का भाव पैदा किया.

देश में हमारे संविधान को लेकर सवाल उठने लगे, जबकि सवाल संविधान को लेकर नहीं, बल्कि उसकी ग़लत व्याख्या करने वाले राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

डीजीपी वी दिनेश रेड्डी को राज्य के किसी भी पुलिस अधिकारी के स्थानांतरण का अधिकार है, लेकिन ऐसे समय में जब मंत्री अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, तो स्थानांतरण होना सवाल खड़ा करता है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

आंध्र के बाबू और नेताजी

ऐसा कम ही सुनने को मिलता है कि बाबू को काम करने के लिए राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़े. आंध्र प्रदेश के बाबू अपने राजनीतिक आक़ाओं के ख़िलाफ़ काम करने के लिए समाचारों में रहे हैं. कुछ समय पहले इसी कॉलम में मैंने लिखा था कि आंध्र प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से इस बात की शिकायत की थी कि राज्य के बाबू उनकी बात मानने से इंकार कर देते हैं. आंध्र प्रदेश में अभी 50 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है. वैसे तो डीजीपी वी दिनेश रेड्डी को राज्य के किसी भी पुलिस अधिकारी के स्थानांतरण का अधिकार है, लेकिन ऐसे समय में जब मंत्री अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, तो स्थानांतरण सवाल खड़ा करता है. लेकिन आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ. सूत्रों का कहना है कि इस स्थानांतरण में किसी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है. कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि इस स्थानांतरण के संबंध में वहां के मंत्रियों द्वारा जितनी भी सिफ़ारिश की गई थी, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया. अब देखने वाली बात यह है कि क्या आंध्र प्रदेश की तरह अन्य राज्यों में भी बाबू इस तरह के क़दम उठाएंगे.■

शीला दीक्षित की टीम

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और गृहमंत्री के बीच कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण के मुद्दे पर चल रहा विवाद अब बीते समय की बात हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से अपने चहेते आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश के मुद्दे पर शीला दीक्षित गुस्सा हो गई थीं, लेकिन अब शीला दीक्षित की परेशानी कम होती नज़र आ रही है. इसकी शुरुआत दो सीनियर आईएएस अधिकारी 1984 बैच के आरके वर्मा और जलज श्रीवास्तव का फिर से दिल्ली में स्थानांतरण करके की गई है. दोनों अब शीला दीक्षित की सरकार में महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभालेंगे. इसी तरह तीन अन्य अधिकारियों राजेश सोमल, दिलराज कौर और बसंत कुमार भी शीला की टीम में शामिल हुए हैं. सूत्रों का कहना है कि शीला दीक्षित ने गृहमंत्री से यह भी अनुरोध किया था कि कुछ महत्वपूर्ण विभागों में काम कर रहे अधिकारियों का स्थानांतरण रोक दिया जाए. उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाएगा.■

पंजाब सरकार को बाबू की चुनौती

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रहे मुक़दमे का फ़ैसला देश के बाबुओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. पंजाब के एक आईएएस अधिकारी वीके जानजुआ को तीन साल पहले भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आरोपित किया गया था और उन पर मुक़दमा चलाने की अनुमति पंजाब सरकार ने दी थी. इस अधिकारी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब सरकार के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा यह गया है कि उन पर मुक़दमा चलाने की अनुमति देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को है, क्योंकि वह आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक आक़ाओं को भी इस बात के लिए आरोपित किया है कि उनके पास केंद्रीय सेवा के अधिकारी को स्थानांतरित करने का अधिकार है, न कि बर्ख़ास्त करने का. इस आईएएस अधिकारी के कोर्ट जाने से बादल सरकार को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस अधिकारी के तर्कों के पक्ष में ही अपनी राय दी है. इस मामले में कोर्ट का फ़ैसला दूसरे बाबुओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जिनके ऊपर मुक़दमा चलाने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर महीने में होगी, लेकिन जानजुआ के तर्क की चर्चा अभी से ही बाबुओं के बीच होने लगी है. इसके साथ ही राज्य सरकारों की नज़र भी इस मामले में हाईकोर्ट के फ़ैसले पर टिकी हुई है. ■

dilipcherian@gmail..com

संविधान और जनता को धोखा

पृष्ठ एक का शेष

लेकर उठने चाहिए थे. लोगों की ज़िंदगी साल दर साल मुश्किल होने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, अपराध बढ़ने लगे, बेरोज़गारी बढ़ने लगी और किसानों एवं मज़दूरों की समस्याएं भी बढ़ने लगीं. सच यही है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ग़रीब के पक्ष में न खड़ी होकर उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती दिखाई दी. और सरकार, जिसकी कल्पना कल्याणकारी राज्य के रूप में की गई है, उसने बिना कुछ सत्य बताए, इस संविधान को ही एक तरह से बदल दिया. 1950 एवं 1952 में लागू किए गए पार्टी सिस्टम का चरम नज़र आया 1991 में. 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश के सामने एक खाका रखा कि वे देश में ख़ुशहाली और विकास की एक नई धारा लेकर आना चाहते हैं तथा देश से इंस्पेक्टर राज ख़त्म करना चाहते हैं. दरअसल, सरकार का नियंत्रण धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और लोग इंस्पेक्टर राज से तंग आ चुके थे. ऐसे समय में, संविधान द्वारा रेखांकित लोक कल्याणकारी राज्य की जगह बाज़ार आधारित राज्य की कल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं उनके वित्त मंत्री ने की और 1992 से लेकर आज तक सरकार का चरित्र पूरी तरह से बदल चुका है.

किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया कि कैसे बिना जनता को विश्वास में लिए और कैसे बिना संसद में संविधान संशोधन लाए सरकारों को लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की जगह, बाज़ार आधारित और लाभ आधारित सरकार में बदल दिया गया, यानी देश का संविधान देश के लोगों से राय लिए बिना ही बदल दिया गया! ऐसे में धीरे-धीरे संविधान की किताब अलमारी की शोभा बनकर रह गई है. संविधान में लिखी गई सारी चीजें एक-एक करके ख़त्म होने लगीं और इसीलिए आज देश में संविधान को लेकर बहुत आदर की भावना लोगों में नहीं है. देश में ऐसी भी ताक़तें हैं, जिनमें नक्सलवादी प्रमुख हैं, जो कहती हैं कि यह संविधान ग़रीब के ख़िलाफ़ खड़ा है. दरअसल, जो संविधान केवल इस देश के ग़रीब के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, उसे 1992 के बाद संसद में गए लोगों ने ग़रीब के ख़िलाफ़ खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. अब बाज़ार आधारित व्यवस्था कहती है कि सड़क पर चलना है, तो टोल टैक्स दीजिए, जबकि संविधान कहता है कि बुनियादी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए. संविधान कहता है कि लोगों के नागरिक अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं और किन कामों को सरकार को करना है, इसकी स्पष्ट व्याख्या दी गई है. लोक कल्याणकारी राज्य के लिए एक आदर्श शब्द वेलफेयर स्टेट हमारे संविधान में है और उसकी व्याख्या भी है, लेकिन सरकारों ने तो यह तय कर लिया है कि इलाज कराना है, तो महंगे अस्पतालों में जाओ और यदि शिक्षा पानी है, तो महंगे स्कूलों में जाओ. सरकार ने न तो शिक्षा का काम आगे बढ़ाया और न ही स्वास्थ्य का काम. महंगाई को खुलेआम बाज़ार के हवाले कर दिया गया. बेरोज़गारी दिन दोगुनी-रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है, कृषि आधारित उद्योग बंद होते जा रहे हैं, मूल खेती अपनी लागत नहीं निकाल पा रही है और किसान क़र्ज़ के जाल में फंसकर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं. पर सरकार ने चूंकि बाज़ार आधारित रुख़ अपना लिया है, इसीलिए अब उसे इस बात से कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ता कि इस देश में कितने लोग कुपोषण से मर रहे हैं, कितने इलाज उपलब्ध न हो पाने की वजह से मर रहे हैं और कितने क़र्ज़ के जाल में फंसकर मर रहे हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि रोज़गार क्यों सृजित नहीं हो रहे हैं, इसकी चिंता भी सरकार को कतई नहीं है.

परिणामस्वरूप, जहां 1992 में 40 ज़िले और 2004 में 70 ज़िले नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहीं आज 272 ज़िले सीधे नक्सलवाद के प्रभाव में हैं. इस संविधान विरोधी तरीक़े पर चलते हुए सरकारों ने हमें ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है, जहां लोग यह सोचने लगे हैं कि शांतिपूर्ण बात सरकार नहीं सुनती, इसीलिए धरना-प्रदर्शन करना बेकार है. हां, हिंसक क़दम उठाने की बात ज़रूर अब लोगों के दिमाग़ में तेजी से आ गई है. बहुत सारे प्रदेशों में जैसे ही रेल पटरियां 10-10, 15-15 दिनों के लिए लोगों द्वारा रोक ली जाती हैं, सरकार फौरन उनकी मांगों के ऊपर प्रतिक्रिया देती है. अगर उड़ीसा में आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नक्सलवादियों द्वारा अगवा कर लिया जाता है, तो उनकी मांगें वहां की सरकार 72 घंटे के भीतर ही पूरी कर देती है. कुल मिलाकर, जो ग़लती 1952 में हुई, उसका यही परिणाम निकला कि संपूर्ण लोकसभा जनता की समस्याओं से दूर खड़ी दिखाई दे रही है. दरअसल, ज़्यादातर क़ानून ऐसे ही बन रहे हैं, जो जनता की तकलीफों को दूर नहीं करते, बल्कि देश के सत्ताधारी वर्ग और उससे हाथ मिलाने वाले कॉरपोरेट वर्ग को लगातार मदद करने वाले क़ानून बनते जा रहे हैं. एक भी ऐसा क़ानून नहीं बन रहा है, जो महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ हो और लोगों को भरोसा दिला सके.

अब स्कैंडल्स लाखों में नहीं होते, अब करोड़ों में भी नहीं होते, क्योंकि बोफोर्स स्कैंडल 64 करोड़ का था, जिसने राजीव गांधी के हाथ से सरकार ही ले ली थी, लेकिन उसके बाद अब तक पांच हज़ार करोड़, दस हज़ार करोड़, 15000 करोड़, 20,000 करोड़, एक लाख करोड़, एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ और 26 लाख करोड़ जैसे स्कैंडल हमारे सामने आ चुके हैं. इन सारे स्कैंडल्स में बिना पार्टियों का भेद किए हुए पक्ष और विपक्ष, दोनों के लोग शामिल दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं, मनरेगा में घोटाला, किसानों की क़र्ज़ माफी योजना में घोटाला, आत्महत्या के सवाल के ऊपर विदर्भ में भेजे गए पैकेज में घोटाला, अनाज घोटाला और दवा घोटाला, यानी हर तरफ़ घोटालों की जैसे बाढ़ आ गई है.

अगर लोकसभा में संविधान के हिसाब से लोगों के प्रतिनिधि होते, लेकिन पार्टियों के प्रतिनिधि न होते, तो उक्त सारे घोटाले न होते, क्योंकि अगर एक व्यक्ति घोटाला करता, तो उसकी कॉन्स्टिटुएंसी के लोग, साथ बैठने वाले उसके दोस्त, संसद में उसके दूसरे साथी उस पर नैतिक प्रभाव डालते और वह भ्रष्टाचार वहीं पर रुक जाता. पर चूंकि अब पार्टियों का राज है, इसीलिए सांसद यह कहते हुए बच जाता है कि इसे तो हाईकमान ने हैंडल किया है. वैसे, यह भी एक सच है कि इतने बड़े घोटाले के पैसे अक्सर ऊपर भी जाते हैं, चाहे वह इस पार्टी की सरकार हो या उस पार्टी की. आज इस देश में यह सवाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि क्या लोगों को संविधान के साथ हुई इस धोखाधड़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए या फिर जैसी स्थिति है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? दूसरा सवाल यह कि क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े सवाल के ऊपर संवैधानिक बेंच बनाने की पहल करेगा या नहीं? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच नहीं बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट सत्तारूढ़ दलों के साथ जुड़ते दिखाई देते हैं. शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते ही दो दिनों के भीतर जज साहबान को कोई न कोई पोस्टिंग मिल जाती है. हिंदुस्तान की जनता सुप्रीम कोर्ट में बहुत विश्वास रखती है, इसीलिए अगर यह सवाल तेज़ होता है, तो आशा करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच बनाएगा और इस बात का फ़ैसला भी करेगा कि 1947 और 1951 के बीच देश की जनता की क़िस्मत और देश के संविधान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया? और साथ ही साथ यह फ़ैसला भी करेगा कि आज जितनी चीजें चल रही हैं, वे संविधान के हिसाब से कितनी सही हैं?

अगर सन् 85 में पार्टी शब्द जोड़ा गया, तो क्या उसके पहले जितनी चीजें हुईं, वे ग़लत थीं या जो संविधान संशोधन सन् 85 में किया गया, वह भी एक तरीक़े से मूल संविधान की भावना के विपरीत संशोधन है? ये सवाल जितने क़ानूनी और संवैधानिक हैं, उतने ही राजनीतिक भी हैं. हिंदुस्तान की जनता के सामने दो रास्ते हैं. पहला, जैसा चल रहा है, उसे चलने दिया जाए और महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी को यूं ही बढ़ने दिया जाए. दूसरा, वह पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, अपने बीच के लोगों को चुनाव में खड़ा करे और उन्हें वोट दे. अगर लोग पार्टियों की बजाय आम जनता के उम्मीदवारों को वोट देंगे, तो दूसरी तस्वीर देश के सामने आएगी और वह तस्वीर कम से कम आज बनी हुई तस्वीर से बहुत बेहतर ही होगी, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोज़गारी के रंग बहुत धुंधले होंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

राकेश मोहन अल्पसंख्यक मंत्रालय जाएंगे

1987 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश मोहन को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह ईआर सोलोमन की जगह लेंगे.

नवराज गोयल अतिरिक्त विकास आयुक्त बने

2002 बैच के आईआरएस (सी ऐंड सीई) अधिकारी नवराज गोयल को वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत अतिरिक्त विकास आयुक्त (हैंडीक्राफ्ट) बनाया गया है. वह अलका अरोड़ा की जगह लेंगे.

संजय वर्मा संघ लोक सेवा आयोग गए

1998 बैच के आईडीएएस अधिकारी संजय वर्मा को संघ लोक सेवा आयोग में निदेशक बनाया गया है. वह एसबी अय्यर की जगह लेंगे.

प्रवीन होरो सिंह गृह मंत्रालय गए

1994 बैच के आईएसएस अधिकारी प्रवीन होरो सिंह को गृह मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. वह नीरज कंसल की जगह लेंगे.

अमिताभ रंजन सिन्हा रक्षा मंत्रालय गए

1993 बैच के आईपी ऐंड टीए ऐंड एफए अधिकारी अमिताभ रंजन सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. वह प्रज्ञदीप्ता मोहंती की जगह लेंगे.

आर सुब्रह्मण्यम ग्रामीण विकास मंत्रालय जाएंगे

1985 बैच के आईएएस अधिकारी आर सुब्रह्मण्यम को भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनाकर उन्हें ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्त किया जा सकता है, जहां वह डीके जैन की जगह लेंगे.

पी जुनेजा राजकीय भाषा विभाग जाएंगे

1977 बैच के सीएसएस कैडर के अधिकारी पी जुनेजा को राजकीय भाषा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह एके पांडे की जगह लेंगे.

अश्विनी कुमार सोनिक एनटीआरओ जाएंगे

1986 बैच के आईआरपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार सोनिक को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (एनटीआरओ) में कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा. वह आनंद मिश्रा की जगह लेंगे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 13
दिल्ली, 03 जून–09 जून 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
6452888
011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

यूपीए-2 विश्व की शायद पहली सरकार होगी, जिसने अपनी असफलता पर जश्न मनाया. दरअसल, वह अपनी विफलताओं को ही सफलता समझती है.

यूपीए-2 के चार साल

यह सरकार झूठी है

यूपीए-2 के चार साल अभूतपूर्व घोटालों की शृंखला और निर्लज्ज भ्रष्टाचार के लिए याद किए जाएंगे. इन चार सालों में देश में महंगाई बढ़ी, विकास रुका, किसानों ने आत्महत्याएं कीं, मज़दूर बेहाल हुए और सरकारी तंत्र को लकवा मार गया, लेकिन दूसरी ओर एकसच यही है कि पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने जमकर माल भी कमाया. इतिहास के पन्नों में यह दौर जनांदोलन के लिए दर्ज होगा, क्योंकि यही वह दौर था, जब देश की जनता यूपीए सरकार की करतूतों, घोटालों, भ्रष्टाचार, भूमि अधिग्रहण, काले धन और महिलाओं पर अत्याचार के ख़िलाफ़ सड़क पर उतरी. अन्ना हज़ारे, रामदेव एवं अरविंद केजरीवाल जैसे कई लोग इन्हीं चार सालों में आशा के प्रतीक बनकर देश के सामने आए. मनमोहन सिंह की सरकार अपना नाम इतिहास में एक विफल सरकार के रूप में दर्ज करा चुकी है. यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी यूपीए-2 के चार साल पूरे होने पर ढंग से जश्न भी नहीं मना पाई, क्योंकि जो लोग समझदार थे, उन्होंने इस जश्न में शामिल होना उचित ही नहीं समझा.

मनीष कुमार

वर्ष 2009 में जब चुनाव हुए, तब कांग्रेस पार्टी को यह विश्वास ही नहीं था कि वह दोबारा सरकार बना सकेगी, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलीं, इसलिए यूपीए-2 को सरकार बनानी पड़ी. दरअसल, मनमोहन सिंह जानते थे कि पिछली सरकार में वे देश के लिए कुछ नहीं कर सके और उन्होंने हमेशा गठबंधन की मजबूरियों का बहाना बनाया. इसलिए जब सरकार बनी, तब मनमोहन सिंह हरकत में आए. उन्होंने सौ दिनों के एजेंडे की घोषणा की और अलग-अलग मंत्रालयों से टारगेट मांगे. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के ज़रिए सरकार ने यह वादा किया था कि सौ दिनों के अंदर महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी, किसानों को राहत मिलेगी, मज़दूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होगी, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और महिला आरक्षण विधेयक भी पास किया जाएगा. इसके साथ-साथ सरकार ने घोषणा की थी कि अगले 5 सालों में झुग्गी-झोपड़ियों को ख़त्म कर दिया जाएगा और ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों को हर महीने 3 रुपये किलो की दर से 25 किलो अनाज दिया जाएगा. यूपीए सरकार ने रोज़ाना 20 किलोमीटर और हर साल 700 किलोमीटर सड़क बनाने का भी लक्ष्य रखा था. लेकिन अफसोस! सरकार ने वादाख़िलाफ़ी की. फिलहाल देश में हर रोज़ दो किलोमीटर से भी कम सड़क बन पा रही है. बिजली के क्षेत्र में 5653 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी फिलहाल अधूरा ही है. सौ दिन का वादा था, अब तो चार वर्ष बीत गए. यूपीए-2 सरकार एक झूठी सरकार है, जो जनता से झूठ बोलती है, संसद में झूठ बोलती है और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी झूठ बोलने से नहीं हिचकती. इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि झूठ पकड़े जाने के बाद भी यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती.

यूपीए-2 के चार सालों में जनता पिसकर रह गई. सबसे बड़ी समस्या महंगाई की रही, जिससे जनता व्याकुल हो उठी. पिछले चार सालों में अभूतपूर्व महंगाई देखी गई. महंगाई की मार ऐसी कि ग़रीब तो ग़रीब, वह अमीरों को भी चुभने लगी. शर्म की बात तो यह है कि सरकार ने जब-जब यह ऐलान किया कि दो या चार महीने में महंगाई में कमी आ जाएगी, तब-तब महंगाई और बढ़ जाती थी. मनमोहन सिंह फिर वादा करते थे, लेकिन महंगाई फिर बढ़ जाती थी. इतना ही नहीं, ऐसी आर्थिक नीति अपनाई, जिससे महंगाई और भी बढ़ती चली गई. सरकार ने डीजल एवं पेट्रोल से अपना नियंत्रण हटा लिया, उसे बाज़ार के हवाले कर दिया, नतीजतन उनके दाम लगातार बढ़ते ही चले गए. यही नहीं, हर चीज की क़ीमत बढ़ गई. अगर उससे भी कुछ होता नहीं दिखा, तो यूपीए के कुछ मंत्रियों ने बयान देकर महंगाई बढ़ाने का काम किया. इसलिए जब भी लोग मनमोहन सिंह की सरकार को याद करेंगे, तो वे इसे महंगाई बढ़ाने वाली सरकार के नाम से याद करेंगे.

यूपीए-2 विश्व की शायद पहली सरकार होगी, जिसने अपनी असफलता पर जश्न मनाया. दरअसल, वह अपनी विफलताओं को ही सफलता समझती है और आंकड़ों की चालबाजी से लोगों को भ्रमित करती रहती है. एक उदाहरण देता हूं. 2-जी घोटाले में फंसने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नीलामी के आदेश दिए. सरकार ने नीलामी से 400 बिलियन रुपये का टारगेट बनाया, लेकिन जब नीलामी हुई, तो सरकार अपना ही टारगेट पूरा नहीं कर पाई. हैरानी इस बात से हुई कि टेलीकाम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा कि 2-जी के बारे में जो बातें लोग कह रहे थे, वे गलत थीं और वह सही निकले. अब सवाल यह उठता है कि अगर वह सही थे, तो 400 बिलियन रुपये का टारगेट क्यों रखा गया? चार सालों की उपलब्धियां गिनाते वक्त प्रधानमंत्री ने देश में मूलभूत सेवाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास के बारे में कुछ नहीं बताया. ऐसा इसलिए, क्योंकि इस मामले में यूपीए-2 का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है. सड़कों की हालत जर्जर हो रही है और पीने का पानी उपलब्ध कराने में सरकार की कोई खास उपलब्धि नहीं है. बिजली के उत्पादन में भी मनमोहन सिंह की सरकार फिसड्डी रही है. सरकार द्वारा संचालित थर्मल पावर प्लांट पिछले चार सालों में कोयला उपलब्ध न होने का रोना रोता रहा. मनमोहन सिंह भी हर जगह अपने भाषणों में कोयले की कमी का गीत गाते रहे, जबकि उन्होंने ही अपनी कलम से 52 लाख करोड़ रुपये का कोयला लुटवा दिया. सिर्फ़ लुटवाया ही नहीं, बल्कि पकड़े भी गए. आज कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के क्रियाकलापों पर जो टिप्पणी की है, वह सचमुच शर्मनाक है. इसमें कोई शक नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने पिछले चार सालों में लोगों को सिर्फ़ धोखा देने का काम किया है.

चार साल की यूपीए-2 सरकार के बारे में प्रधानमंत्री ने इनक्लूसिव ग्रोथ (समावेशी विकास) का ढोल पीटा. वैसे यह कहना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह ने इनक्लूसिव ग्रोथ का नाम लेकर एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की. उन्होंने इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात कहकर यह दावा किया कि भारत के ग्रामीण इलाकों में विकास और खपत 3 फ़ीसद की दर से बढ़े. प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश की. ग्रामीण विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कम है. अगर सिर्फ़ 3 फ़ीसद की दर से ग्रामीण विकास हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि देश के 70 फ़ीसद इलाके पिछड़ रहे हैं और शहरों का विकास ज़्यादा हो रहा है. शहर और गांव के बीच की खाई बढ़ रही है. जब भी शहर और गांव के बीच खाई बढ़ती है, तो देश में असंतोष बढ़ता है. यही वजह है कि देश में नक्सलियों की पकड़ मजबूत हो रही है. यह देश के सामने सबसे बड़ा ख़तरा है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है. अब जहां तक बात इन्क्लूसिव ग्रोथ की है, तो इसका मतलब यही होता है कि विकास का वह रास्ता, जिसमें ग़रीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं सभी वंचित वर्गों को विकास में हिस्सेदारी और लाभ मिल सके.

अब जरा वंचित वर्गों के विकास और सशक्तिकरण पर यूपीए-2 की नीतियों को परखते हैं. उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए, तो उससे पहले यूपीए-2 ने रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का शिगूफा छोड़ा, लेकिन देश के मुसलमानों ने कांग्रेस की इस चाल को भांप लिया. मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण के नाम पर यूपीए ने खुलेआम धोखा दिया. महिलाओं के आरक्षण का बिल आज भी लटका हुआ है. आश्चर्य की बात तो यह है कि दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देने के नाम पर यूपीए ने उसका भी राजनीतिकरण कर दिया. ग़रीबों एवं किसानों को कोई राहत नहीं मिली. भूमि अधिग्रहण बिल भी लटका हुआ है. जिस सरकार में किसानों, मज़दूरों, पिछड़ों, ग़रीबों, अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों को कोई राहत नहीं, वह सरकार अगर इन्क्लूसिव ग्रोथ के बारे में कुछ कहती है, तो यह सरासर देश के साथ एक मज़ाक़ है.

यह सचमुच हैरानी की बात है कि मनमोहन सिंह यूपीए-2 को एक सफल सरकार मानते हैं. जबकि सच्चाई इसके उलट है. देश में गंभीर आर्थिक संकट है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार घटती जा रही है और सरकार की नीतियां एक के बाद एक नाकाम हो रही हैं. मनमोहन सिंह की सरकार जो भी वादे करती है, उन्हें वह पूरा नहीं कर पाती. एक उदाहरण देता हूं. यह बात 2011 की है. बजट पेश करने से पहले मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है, जिनसे देश की आर्थिक स्थिति खासी मज़बूत हो जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार 2011-12 में 9 प्रतिशत विकास दर हासिल कर लेगी. हालांकि कुछ समय बीतते ही सरकार को समझ में आ गया कि 9 प्रतिशत विकास दर मुमकिन नहीं है, तो उसने इस टारगेट को घटाकर 8.4 प्रतिशत कर दिया. इसके बाद एक बार फिर सरकार को लगा कि यह करना भी मुमकिन नहीं है, तो विकास दर का टारगेट घटाकर 6.9 प्रतिशत तय किया गया. कहने का मतलब यह है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार अपनी नीतियों और उसके परिणाम को लेकर न सिर्फ़ भ्रमित रही, बल्कि वह अपनी गलतियां छुपाने के लिए आंकड़ों के साथ कलाबाजी भी करती रही. इस बार प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता जिन आंकड़ों को दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वे महज एक छलावा हैं, क्योंकि इन चार सालों में किसी भी प्राथमिक क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हुई. मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं, इसलिए उन्हें यह समझना पड़ेगा कि आंकड़ों की कलाबाजी से सेमिनारों में बहस को तो जीता जा सकता है, लेकिन उससे देश नहीं चलाया जा सकता. एक सफल सरकार का मापदंड सिर्फ़ यह है कि वह कम से कम अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करे. जो सरकार अपने ही लक्ष्यों को पूरा नहीं पाई, उसे एक सफल सरकार कैसे माना जा सकता है.

> **उस सरकार से भ्रष्टाचार ख़त्म करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जो स्वयं सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो. आख़िर में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को देश के निकम्मे विपक्ष का धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिसकी अकर्मण्यता की वजह से यूपीए-2 चार सालों तक शासन कर पाया.**

मनमोहन सिंह देश या शायद विश्व के ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विदेशी दौरे किए. विदेशी दौरों के मामले में वे रिकॉर्ड बना चुके हैं. शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस बात का विश्वास था कि वे अपने आपको एक विश्वस्तरीय नेता के रूप में स्थापित कर सकेंगे. खैर, पिछले नौ सालों में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया. दरअसल, मनमोहन सिंह जिन बड़े देशों में गए, वहां से उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया और जिन छोटे देशों में गए, वहां वे कुछ न कुछ गंवाकर ही लौटे. बावजूद इसके वे चार सालों की विदेश नीति को सफल मानते हैं. उन्होंने कहा कि भारत के रिश्ते आज अमेरिका, रूस एवं यूरोप के देशों के साथ पहले से ज़्यादा गहरे हो गए हैं, लेकिन वे बड़ी सफाई के साथ इस बात को छुपा गए कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से ज़्यादा खराब हो गए हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका, यहां तक कि नेपाल के साथ भी हमारे रिश्तों में खटास आई है. पाकिस्तान को यूपीए सही ढंग से हैंडिल नहीं कर सका. मुंबई धमाकों में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने या भारत लाने में यूपीए विफल रहा. यह मसला ऐसा था, जिसके जरिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया जा सकता था, लेकिन यह मौक़ा गंवा दिया गया. मनमोहन सिंह से सबसे बड़ी गलती तब हुई, जब उन्होंने बलूचिस्तान के मामले को संयुक्त बयान में शामिल करा दिया. यूपीए सरकार की गलतियों का ही यह नतीजा है कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर धड़ से अलग करने और सरबजीत की निर्मम हत्या की जुर्रत कर बैठता है. और तो और, अब तो बांग्लादेश, नेपाल एवं श्रीलंका भी आंखें दिखाने लगे हैं. सबसे शर्मनाक तो मालदीव का मामला है, जहां भारत का अब कोई असर ही नहीं है. हालांकि विदेश नीति पर लोगों के बीच चर्चा नहीं होती, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यूपीए के तहत भारत की विदेश नीति सबसे ज़्यादा दिशाविहीन रही.

यूपीए सरकार पूरी तरह बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी रही, चाहे वह गैस एवं पेट्रोल की क़ीमतें हों, टेलीकाम स्पेक्ट्रम का आवंटन हो, खनन, वित्तीय सेक्टर, रिटेल सेक्टर या फिर विदेशी शिक्षा संस्थान हों. सरकार की हर नीति का फ़ायदा देश के बड़े उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों को ही पहुंचा. पिछले चार सालों से नेताओं, उद्योगपतियों एवं दलालों के गठजोड़ जिस तरह से देश में फल-फूल रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया. सरकार तो बजट के जरिए भी कॉरपोरेट जगत को मदद पहुंचाने में कोई शर्म महसूस नहीं करती. हर साल लाखों करोड़ रुपये की छूट यूपीए ने पूंजीपतियों को दी. इस साल के बजट के मुताबिक, कॉरपोरेट जगत को मिलने वाली छूट 460972 करोड़ रुपये की है. इसमें 88263 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स के रूप में माफ़ कर दिए गए, जबकि एक्साइज ड्यूटी के रूप में 198291 करोड़ रुपये और कस्टम ड्यूटी के रूप में 174418 करोड़ रुपये की छूट दी गई.

यूपीए सरकार का कोई भी विश्लेषण भ्रष्टाचार की चर्चा के बगैर नहीं किया जा सकता. यह इतिहास की पहली सरकार है, जिसका कोई सिटिंग मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हो. जब सरकार बनी थी, तब मनमोहन सिंह को लोग एक ईमानदार आदमी मानते थे, लेकिन कोयला घोटाले में जिस तरह से खुलासा हुआ, उससे यूपीए ने यही हासिल किया कि अब लोगों की नज़रों में मनमोहन सिंह ईमानदार नहीं रहे. भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सरकार का है, लेकिन यह सरकार तो भ्रष्टाचार से लड़ने वाले सामाजिक नेताओं को ही अपना दुश्मन मानती है. वैसे भी उस सरकार से भ्रष्टाचार ख़त्म करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जो स्वयं सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो. आख़िर में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को देश के निकम्मे विपक्ष का धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिसकी अकर्मण्यता की वजह से यूपीए-2 चार सालों तक शासन कर पाया.■

manish@chauthiduniya.com

अन्ना की हुंकार

जन विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंक

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

अन्ना हज़ारे की जनतंत्र यात्रा का तीसरा चरण उत्तराखंड में बीते 24 मई को संपन्न हुआ. समाजसेवी अन्ना हज़ारे एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय की अगुवाई में चल रही जनतंत्र यात्रा अपने तीसरे चरण में 18 मई को उत्तराखंड के जोशीमठ एवं बद्रीनाथ पहुंची. जोशीमठ में जनसभा को संबोधित करते हुए अन्ना ने कहा कि जनता मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी है, इसीलिए वे जनतंत्र यात्रा के ज़रिए जनता को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि उसे यह एहसास हो कि उसमें जनविरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकने की ताक़त है. अन्ना हज़ारे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश की जनता को जागरूक बनाने की उनकी मुहिम जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सशक्त जन लोकपाल विधेयक पारित करने के प्रति गंभीर नहीं है. इसलिए सितंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसंसद आयोजित की जाएगी. अन्ना के मुताबिक़, जन लोकपाल विधेयक और राइट टू रिजेक्ट जैसे मामलों के प्रति जनता को जागरूक और संगठित करना अब नितांत ज़रूरी हो गया है. वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने कहा कि इस जनतंत्र यात्रा का असल मक़सद है देश की जनता को जागरूक करना, ताकि वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत में चैन और सुकून की ज़िंदगी जी सके. उन्होंने कहा कि जन लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार का ख़ात्मा करने में सहायक होगा, लेकिन सरकार इसे लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों. दरअसल, अब निर्णायक लड़ाई उन्हें ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा राजनेताओं ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है. अन्ना हज़ारे जैसे लोग जब अवाम के अधिकारों की बात करते हैं, तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती. ऐसा करने में राजनेता इसलिए भी सफल हो रहे हैं, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है. संतोष भारतीय के अनुसार, अब देश को राजनेताओं के हवाले छोड़ना ठीक नहीं है. अगर राजनीतिक दलों के नेता जनविरोधी कार्य करेंगे, तो उन्हें चौतरफ़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा.

ग़ौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अन्ना की जनतंत्र यात्रा के प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण राजस्थान में संपन्न हुआ. इसके बाद उन्होंने जनतंत्र यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 14 मई को उत्तराखंड के ऋषिकेश से की. 20 मई को वह नारायण बागड़, कुलसारी एवं ग्वालदम होते हुए कौसानी पहुंचे. नारायण बागड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अन्ना ने कहा कि जनता मालिक है और नेता उसके नौकर हैं, लेकिन मालिक अपनी ताक़त भूल गया है. इसलिए उसे फिर से मालिक की भूमिका में आना होगा. जनता को अपनी ताक़त का एहसास नहीं है. मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था सड़ चुकी है. इस व्यवस्था में सुधार की नहीं, बल्कि परिवर्तन की ज़रूरत है. व्यवस्था परिवर्तन से ही जनता के दु:ख-दर्द दूर किए जा सकते हैं. अपने काफिले के साथ जब अन्ना हज़ारे कुलसारी पहुंचे, तो वहां अन्ना हज़ारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, के नारों के साथ लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे. अन्ना ने भी उन्हें निराश नहीं किया. भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जब उन्होंने जनता को संबोधित करना शुरू किया, तो माहौल में देशभक्ति की भावना का संचार हो गया.

कुलसारी के बाद अन्ना हज़ारे ग्वालदम पहुंचे, जहां लोग क़रीब दो घंटे से उनके आगमन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर थकान की शिकन तक नहीं थी. ऐसा लग रहा था कि अगर पूरी रात भी इंतज़ार करना पड़े, तो वे अन्ना को सुने बिना नहीं जाएंगे. अन्ना ने कहा कि आप लोगों के इसी प्यार से ही मुझे ऊर्जा मिल रही है और मैं 71 साल का युवा हो जाता हूं. उन्होंने लोगों को उनकी ताक़त के बारे में बताया और भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा की रजामंदी की अनिवार्यता की बात भी कही. उन्होंने लोगों से सशक्त लोकपाल बनाने के लिए सहयोग करने और सितंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में आयोजित होने वाली जनसंसद में आने को कहा. उन्होंने कहा कि एक बार फिर मैं होऊंगा रामलीला मैदान में और हाथों में तिरंगा लिए होंगे आप. सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे. जब तक जिएंगे, देश एवं समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे, तो देश एवं समाज के लिए मरेंगे. सोमेश्वर, रानीखेत एवं अल्मोड़ा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अन्ना हज़ारे ने कहा कि जब तक सशक्त जन लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा. जब अन्ना हज़ारे जनतंत्र यात्रियों के साथ सोमेश्वर पहुंचे, तो वहां हज़ारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. रानीखेत एवं अल्मोड़ा में भी अन्ना हज़ारे और संतोष भारतीय का नागरिक अभिनंदन किया गया. रानीखेत में रैली को संबोधित करते हुए अन्ना ने कहा कि राजनेता सेवक हैं और अवाम उन्हें देश की सेवा करने के लिए चुनती है. लेकिन जब वे विधानसभाओं एवं संसद में लुटेरों की भूमिका में आ जाते हैं, तो देश की करोड़ों जनता ख़ुद को ठगा हुआ महसूस करती है. अन्ना 23 मई को उत्तराखंड के कैंचीधाम और नैनीताल पहुंचे. यहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया. 24 मई को अन्ना हज़ारे ने रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सशक्त जन लोकपाल के माध्यम से ही देशव्यापी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को देश की आम जनता के दु:खों एवं तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं है. अन्ना ने उत्तराखंड को वीरों की धरती बताया और नौजवानों का आह्वान किया कि वे देशहित के लिए आगे आएं. ■

प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे जी का
विकास खण्ड घाट आगमन पर हार्दिक अभिनन्दन

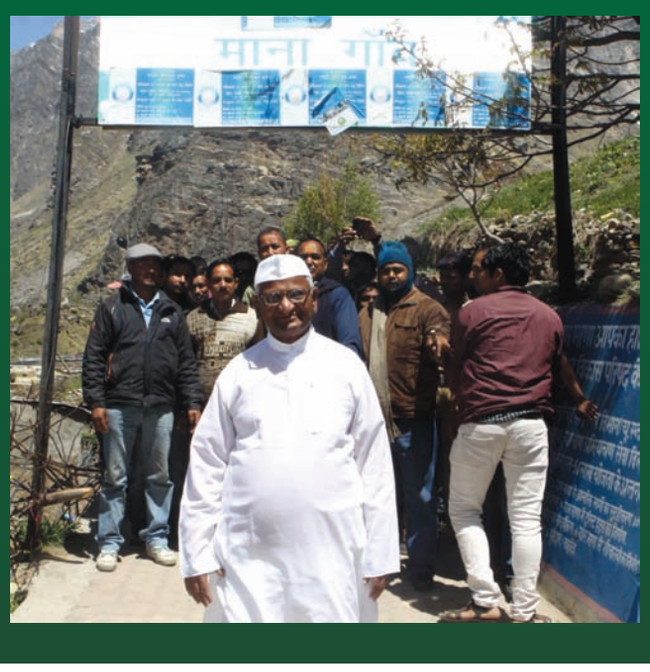

अन्ना लड़ा है इसलिए कि
प्यार जग में जी सके
आदमी का खून कोई
आदमी न पी सके

प्रक्रिया शुल्क में भारी कटौती
भारतीय स्टेट बैंक
हर भारतीय का बैंक
एसबीआई कार लोन
चलकर आइए. चलाकर ले जाइए
वाकई आश्चर्यजनक!
न्यूनतम ईएमआई ₹1683#/लाख
समय से पूर्व भुगतान दंड
अधिकतम अवधि 7 वर्ष
85% वित्त
शीघ्र ही अपनी नज़दीकी शाखा से संपर्क करें !!!
कोई अग्रिम ईएमआई नहीं
दैनिक घटते हुए शेष पर ब्याज
अधिक जानकारी के लिए www.sbi.co.in पर लॉग ऑन करें या 1800 425 3800 (टोल फ्री)
1800 11 22 11 (टोल फ्री एमटीएनएल/बीएसएनएल)/080 26599990 पर कॉल करें।

अमित शाह उत्तर प्रदेश में तभी कुछ कर पाएंगे, जब उन्हें छोटे-बड़े सभी नेताओं का सहयोग मिलेगा और यह तो समय ही बताएगा कि ऐसा हो पाएगा या नहीं.

उत्तर प्रदेश

कांग्रेस-भाजपा में मंथन का दौर

क्या इनके सपने पूरे होंगे?

2014 का महासमर. कांग्रेस और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दोनों ही पार्टियां हर क़दम फूंक-फूंककर रख रही हैं. संगठन को मज़बूत बनाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह-तरह की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं. लेकिन देखना यह है कि कौन अपने मक़सद में कितना सफल होता है?

अजय कुमार

अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल जनता से जुड़े मुद्दों के सहारे जीत हासिल नहीं करना चाहता. खासकर, उत्तर प्रदेश के बारे में यह बात दावे के साथ ज़रूर कही जा सकती है. सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि मतदाता जातिवाद में बंटा रहे. यह बात कोई सीधे तौर पर तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन रणनीतियां कुछ ऐसी बनाई जाती हैं, जिनसे वोटों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में किया जा सके. भाजपा नेतृत्व चाहता है कि मतदान हिंदुत्व के नाम पर हो, तो कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी मुसलमानों को लुभाने में लगी हैं. ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग एवं दलित भी विभिन्न दलों के एजेंडे में प्राथमिकता के साथ शामिल हैं. इसी को ध्यान में रखकर नए-नए प्रयोग हो रहे हैं. भाजपा हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए गुजरात के विवादित एवं कट्टर हिंदूवादी नेता अमित शाह को उत्तर प्रदेश ले आई है. दरअसल, नरेंद्र के राइट हैंड अमित शाह के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही यह बात साफ़ हो गई है कि देर-सबेर मोदी भी आ जाएंगे. उधर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जो नई टीम बनाई है, उसमें उन्होंने बड़ी संख्या में मुस्लिम चेहरों, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के नेताओं को शामिल करके बसपा, खासकर समाजवादी पार्टी को चुनौती देने का मन बना लिया है. राजनीतिक पंडित राहुल की कथनी और करनी में अंतर से हैरान हैं. कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची में मुसलमानों एवं कुछ अन्य बिरादरियों का दबदबा देखकर लोग राहुल गांधी की नीयत और सोच पर अब उंगली उठाने लगे हैं.

अमित शाह को प्रदेश भाजपा प्रभारी बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति के हाथ गुजरात नरसंहार में सने हुए हैं, उसे सूबे की ज़िम्मेदारी देने से भाजपा की कट्टरपंथी सोच साफ़-साफ़ उजागर होती है.

राजनाथ की अगुवाई में भाजपा ने दिल्ली में यह घोषणा कर दी है कि वह चुनाव के लिए तैयार है.

केंद्र में मोदी, तो उत्तर प्रदेश में उनके शिष्य अमित शाह का जलवा देखने को मिलेगा. जैसे ही अमित शाह को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनाया गया, प्रदेश भाजपा की राजनीति उनके इर्द-गिर्द घूमने लगी. अमित भले ही सूबे के लिए बहुत चर्चित चेहरा न हों, लेकिन उन्हें प्रभारी बनाकर भाजपा ने यहां की सियासत में हिंदुत्व और गुजरात दंगों का रंग भर दिया है. ऐसे में जो हालात बन रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में गुजरात दंगों की जमकर चर्चा होगी. यह चर्चा भाजपा के पक्ष में वोटों के ध्रुवीकरण के हालात भी पैदा कर सकती है. पार्टी उग्र हिंदुत्व का एजेंडा उभारेगी, वहीं मुस्लिम वोटों के लिए ग़ैर भाजपा दलों में होड़ मचेगी. अमित शाह के नरेंद्र मोदी के खास होने के अलावा, उनकी जो विवादित पृष्ठभूमि है, उसके मद्देनज़र विरोधी दलों ने भाजपा के ख़िलाफ़ हल्ला बोलते हुए उस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है. मुस्लिम वोट अपने पाले में करने के लिए सपा, कांग्रेस एवं बसपा के बीच होड़ मच गई है. सच तो यह है कि भाजपा पर उंगली उठाने वाले दल भी जातिवाद के कीचड़ में धंसे हुए हैं. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार और केंद्र में कांग्रेस सरकार मुसलमानों को लुभाने के लिए संविधान को भी ताख पर रखने से परहेज नहीं करती. दु:खद यह कि पुलिस हिरासत में अक्सर कैदियों की मौत हो जाती है, लेकिन उस पर कभी कोई हल्ला नहीं मचाता, लेकिन जब आतंकवाद का आरोप झेल रहा कोई शख्स मर जाता है, तो धरती-आसमान एक कर दिया जाता है. ऐसे में पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ आनन-फानन में मुकदमे भी अखिलेश सरकार दर्ज करा देती है.

कांग्रेस अमित को लेकर काफी उत्साहित नज़र आ रही है. उसके रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुक़ाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा. उन्हें लगता है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह को मिल रही तवज्जो को रोकने के लिए अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस को अपना मज़बूत विकल्प चुन सकते हैं. अभी चुनाव होने में क़रीब एक साल का समय है, लेकिन जब अमित शाह नरेंद्र मोदी को यहां ले आकर सूबे का दौरा कराएंगे, तो साफ़ हो जाएगा कि सूबे की जनता के बीच मोदी की हिंदूवादी नेता की छवि काम करती है या गुजरात के विकास मॉडल की. अमित शाह को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने से एक उम्मीद यह भी बन रही है कि नरेंद्र मोदी को लखनऊ से चुनाव लड़ाया जा सकता है. लेकिन ऐसा तब संभव होगा, जब पार्टी मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी. प्रदेश भाजपा के एक तबके को यह भय है कि अमित शाह के आने से कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के ख़िलाफ़ किसी एक दल के पक्ष में न हो जाए. वहीं एक अन्य पक्ष का कहना है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से खास अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यह वर्ग वैसे भी भाजपा को वोट नहीं देता. पार्टी का यह प्रयोग कितना सफल होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह के आने से राजनीतिक गर्मी पैदा हो गई है. दरअसल, भाजपा नेतृत्व ने अमित एवं मोदी की पृष्ठभूमि और विवादित छवि को ही पार्टी के लिए मजबूत पक्ष माना है तथा उसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश होगा. अमित शाह सूबे के भाजपाइयों को बताएंगे कि संग्राम कैसे जीता जाए. अमित का साथ निभा सकते हैं वरुण गांधी एवं उमा भारती जैसे नेता, जिनकी आवाज़ में खनक और धमक सुनाई देती है. दरअसल, सूत्र बताते हैं कि इन्हीं तीन नेताओं के सहारे भाजपा हिंदुत्व को जगाने का बीड़ा उठाएगी. वैसे अतीत में भाजपा इस तरह के कई छोटे-बड़े प्रयोग वोटों के लिए कर चुकी है, जैसे कल्याण सिंह को आगे-पीछे करना, उमा भारती को मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में उतार देना और बसपा से निकाले गए बाबू सिंह कुशवाहा को यह सोचकर शामिल कर लेना कि उनके माध्यम से पिछड़ों का वोट भाजपा के खाते में चला आएगा.

उधर, अमित शाह को प्रदेश भाजपा प्रभारी बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति के हाथ गुजरात नरसंहार में सने हुए हैं, उसे सूबे की ज़िम्मेदारी देने से भाजपा की कट्टरपंथी सोच साफ़-साफ़ उजागर होती है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अमित शाह को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने को ख़तरे की घंटी बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा किसे पदाधिकारी बनाए, यह उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन विवादित अमित शाह के प्रदेश आने पर जनता को सतर्क और होशियार रहने की ज़रूरत है. कांग्रेस अमित शाह के बहाने भाजपा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप तो लगा रही है, लेकिन उसके हाथ भी तुष्टिकरण की राजनीति में रंगे नज़र आ रहे हैं. राहुल कहने को तो प्रदेश कांग्रेस में चुस्ती-फुर्ती लाकर उसे सरपट दौड़ाने के लिए प्रयोग दर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन

अमित शाह के नरेंद्र मोदी के खास होने के अलावा, उनकी जो विवादित पृष्ठभूमि है, उसके मद्देनज़र विरोधी दलों ने भाजपा के ख़िलाफ़ हल्ला बोलते हुए उस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है. मुस्लिम वोट अपने पाले में करने के लिए सपा, कांग्रेस एवं बसपा के बीच होड़ मच गई है. सच तो यह है कि भाजपा पर उंगली उठाने वाले दल भी जातिवाद के कीचड़ में धंसे हुए हैं. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार और केंद्र में कांग्रेस सरकार मुसलमानों को लुभाने के लिए संविधान को भी ताख पर रखने से परहेज नहीं करती.

कामयाबी उन्हें भी हाथ नहीं लग रही है. कांग्रेस में जोनल प्रभारी के रूप में जो नई व्यवस्था शुरू हुई थी, उसमें एक साल के भीतर ही बदलाव करना पड़ा. पहले पार्टी के दिग्गज नेताओं और उसमें भी सांसदों को यह कहकर जोनल प्रभारी बनाया गया था कि वे अपने अनुभवों से संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन एक ही झटके में उनकी उपयोगिता ख़त्म कर दी गई. उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि उन सबको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है. पंकज मलिक एवं ललितेश पति त्रिपाठी को संयोजक से प्रोन्नत कर प्रभारी बनाया गया है. दूसरी तरफ़ पार्टी ने 31 जिला एवं शहर अध्यक्षों की जो सूची जारी की है, उसमें 13 मुस्लिम हैं. पहले चरण में मुसलमानों को एक तिहाई से ज़्यादा पद देकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि वह उन्हें खासी अहमियत देने की तैयारी में है और यह एक शुरुआत भर है. अभी 30-35 जिला एवं शहर अध्यक्षों की तैनाती और होनी है.

बहरहाल, कांग्रेस और भाजपा ने जो फ़ैसले लिए हैं, उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त दोनों राष्ट्रीय दल राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस राज्य में अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल करने में कामयाब रहेंगे. अमित शाह उत्तर प्रदेश में तभी कुछ कर पाएंगे, जब उन्हें छोटे-बड़े सभी नेताओं का सहयोग मिलेगा और यह तो समय ही बताएगा कि ऐसा हो पाएगा या नहीं. यहां यह बताना ज़रूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को उत्तर प्रदेश में सक्रिय कर प्रचार अभियान की कमान सौंपी गई थी, लेकिन उन्हें पार्टी के नेताओं से वैसा सहयोग नहीं मिला, जैसा मिलना चाहिए था. इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी. इसी प्रकार कांग्रेस ने अपने सभी आठ जोनल प्रभारियों को बदलने का जो निर्णय लिया, उसका उद्देश्य चाहे जो हो, लेकिन उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि पहले जिन लोगों को पार्टी को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया था, वे अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा सके, जबकि उनमें से कुछ ताकतवर केंद्रीय मंत्री थे. अब जिन लोगों को जोनल अध्यक्ष बनाया गया है, वे कुछ कर सकेंगे, इसमें फिलहाल संदेह है. वजह, उन्हें भी उन सवालों से जूझना होगा, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर उठ रहे हैं. राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां यदि नेतृत्व के स्तर पर बदलाव करके संतुष्ट हो जाती हैं, तो उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला. यदि वे वास्तव में अपने जनाधार में गिरावट को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें उन बुनियादी कारणों का समाधान करना ही होगा, जिनके चलते वे आम जनता का भरोसा खोती जा रही हैं.

समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस एवं भाजपा के पैतरों से अंजान नहीं है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने चौथी दुनिया से कहा कि भाजपा और कांग्रेस चाहे जितने भी प्रयोग कर लें, लेकिन काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती. भाजपा की सांप्रदायिक नीति के कारण प्रदेश का पहले ही काफी नुकसान हो चुका है, इसलिए अब जनता भाजपा के हाथों और नुकसान नहीं कराएगी. जनता कांग्रेस को नौ वर्षों से झेल रही है और इस बार वह ग़ैर भाजपा एवं ग़ैर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उसमें सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की मुख्य भूमिका रहेगी. बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने देश-प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का समाजवादियों का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता. कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है और अब वह मनमोहन या राहुल के नाम में फंसकर वोट नहीं करेगी तथा भाजपा तो वैसे ही हारने वाली पार्टी बन गई है.■

feedback@chauthiduniya.com

नई आर्थिक नीतियों के नाम पर सरकार ने देश के मज़दूरों, किसानों एवं आम आदमी को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है.

मारुति, मानेसर के अनसुलझे सवाल

श्रमिक, शोषण और सरकार?

मारुति-सुजुकी वर्कर्स यूनियन की मांगें

- 18 जुलाई, 2012 को मानेसर प्लांट में हुई हिंसा की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाए.
- बर्ख़ास्त सभी 546 स्थायी और 1800 ठेका मज़दूरों को तत्काल बहाल किया जाए.
- मज़दूर यूनियन बनाने का हक़ मिले, क्योंकि यह कामगारों का संवैधानिक अधिकार है.
- कारखानों में ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए और मज़दूरों को स्थायी नौकरी मिले.
- न्यूनतम मज़दूरी देने का प्रावधान किया जाए.
- मज़दूरों को साप्ताहिक अवकाश और अन्य ज़रूरी सुविधाएं मिलें.
- श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई हो.

मारुति-सुजुकी वर्कर्स यूनियन पिछले दो वर्षों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर मानेसर (गुड़गांव) में संघर्षरत है, लेकिन कंपनी और सरकार लगातार उसका दमन कर रही हैं. सरमाएदारों की हमदर्द बन चुकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने यह तय कर लिया है कि मारुति प्रबंधन के हितों की ख़ातिर उसे मज़दूरों की लाशों से भी गुजरने में कोई गुरेज़ नहीं है. कैथल में निहत्थे मज़दूरों के साथ हुई पुलिसिया ज़्यादती इस बात की तस्दीक करती है कि हरियाणा सरकार की नीतियां पूरी तरह जनविरोधी हैं. मेहनतकश मज़दूरों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर प्रस्तुत है चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह
arsingh@chauthiduniya.com

दो दशक पहले भारत में कार बनाने वाली इक्का-दुक्का कंपनियां ही हुआ करती थीं, लेकिन आज हिंदुस्तान में दर्जनों देशी-विदेशी कार कंपनियों का बाज़ार मज़बूत हो चुका है. मारुति-सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है और इसीलिए उसका मुनाफ़ा भी दूसरी ऑटो कंपनियों से कहीं ज़्यादा है. भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तेज़ी से विस्तार हो रहा है. भारत के मज़दूरों की कड़ी मेहनत को कार निर्माता कंपनियां न सिर्फ़ भुला देती हैं, बल्कि उन पर अंकुश बनाए रखने के लिए तानाशाही व्यवहार भी अपनाती हैं. मानेसर स्थित मारुति-सुजुकी प्लांट में पिछले दो वर्षों से जारी श्रमिक असंतोष इसका एक उदाहरण है. हालांकि कंपनी से जुड़े आला अधिकारियों एवं केंद्र सरकार द्वारा इसे बेहद हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा करना उनके लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकता है. मारुति, मानेसर और मज़दूर कुछ अनसुलझे सवालों का वह पुलिंदा है, जो नब्बे के दशक में शुरू हुई नव-उदारवादी नीतियों की कोख से जन्मा है. बीते दो दशकों में किसानों के खेत-खलिहान उजड़ते चले गए और उनकी जगह कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गईं. जो काश्तकार कल तक अपनी ज़मीनों के मालिक थे, उनमें से अधिकांश न केवल आज भूमिहीन हो चुके हैं, बल्कि मज़दूरी करने के लिए विवश हो गए हैं.

पिछले दिनों मारुति-सुजुकी के मज़दूरों की जबरन गिरफ्तारी और उनके परिवारजनों पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में मज़दूर बिगुल दस्ता के कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर और हरियाणा भवन पर उग्र विरोध-प्रदर्शन किया. सैकड़ों की तादाद में मौजूद श्रमिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों ने इस बर्बर घटना को अलोकतांत्रिक क़रार देते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में दख़ल देने की मांग की. ग़ौरतलब है कि 18 जुलाई, 2012 को मारुति-सुजुकी के मानेसर प्लांट में हुई तोड़-फोड़ और आगजनी के बाद बग़ैर किसी ठोस जांच के कारखाने में कार्यरत मज़दूरों के ख़िलाफ़ प्रबंधन और सरकार ने एकतरफ़ा कार्रवाई की, जिसे लेकर मज़दूरों में काफ़ी गुस्सा है. अपने साथियों के साथ हुए इस अन्याय के विरोध में पिछले दो महीने से मारुति के मज़दूर हरियाणा के कैथल में शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे. बीते 18 मई की रात पुलिस ने धरना स्थल पर धावा बोलकर 96 मज़दूरों को बग़ैर कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया. इस पुलिसिया बर्बरता के ख़िलाफ़ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्त्री मज़दूर संगठन से जुड़ी एक कार्यकर्ता ने चौथी दुनिया को बताया कि कैथल में 18 मई को हरियाणा के उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के घर के सामने सैकड़ों मज़दूर प्रदर्शन कर रहे थे.

देश में श्रमिक असंतोष बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को इससे कोई मतलब ही नहीं है. अगर सरकार मज़दूरों के हित में कोई ठोस क़दम नहीं उठाती है, तो यह आंदोलन और तेज़ होगा.

गुरुदास दासगुप्ता
महासचिव एटक एवं सांसद सीपीएम

उसी दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस बल आया और उसने निहत्थे-निर्दोष मज़दूरों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दीं. साथ ही वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इस घटना में कई महिलाओं को गंभीर चोटें आईं. उनके मुताबिक़, इस घटना से यह साबित हो गया है कि हरियाणा सरकार कॉरपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर श्रमिक हितों को कुचलना चाहती है. मारुति-सुजुकी वर्कर्स यूनियन की लड़ाई में शामिल बिगुल मज़दूर दस्ता के संयोजक अभिनव ने चौथी दुनिया को बताया कि नई आर्थिक नीतियों के नाम पर सरकार ने देश के मज़दूरों, किसानों एवं आम आदमी को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है.

उनके अनुसार, मारुति प्लांट (मानेसर) में काम करने वाले श्रमिक पिछले दो वर्षों से यूनियन बनाने का संवैधानिक अधिकार देने, कारखाने में ठेकेदारी प्रथा बंद करने और स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मारुति-सुजुकी प्रबंधन और हरियाणा सरकार मिलकर मज़दूरों की आवाज़ दबा रहे हैं. उन्होंने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के उदासीन रवैये पर भी नाराज़गी ज़ाहिर की. अभिनव के अनुसार, पिछले दो दशकों से सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, जो जनता के पैसे से खड़ी की गई हैं, का धड़ल्ले से निजीकरण किया जा रहा है.

एटक के महासचिव एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गुरुदास दासगुप्ता ने हरियाणा सरकार को जनविरोधी क़रार देते हुए कहा कि ट्रेड यूनियनें मज़दूरों पर हो रहे अन्याय को और सहन नहीं करेंगी. चौथी दुनिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में श्रमिक असंतोष बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को इससे कोई मतलब ही नहीं है. उनके मुताबिक़, अगर सरकार मज़दूरों के हित में कोई ठोस क़दम नहीं उठाती है, तो यह आंदोलन और तेज़ होगा. ग़ौरतलब है कि मानेसर स्थित मारुति प्लांट में 18 जुलाई, 2012 को हुई हिंसक झड़प और आगजनी में कंपनी के जनरल मैनेजर (एचआर) की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद 151 मज़दूरों पर अलग-अलग धाराओं के तहत मुक़दमे दायर कर उन्हें जेल भेज दिया गया था. गिरफ्तार लोगों में मारुति-सुजुकी वर्कर्स यूनियन का पूरा नेतृत्व शामिल है. बहरहाल, ताज़ा घटनाक्रम को देखते हुए यह कहना ग़लत नहीं होगा कि मारुति-सुजुकी का मानेसर प्लांट देश में मज़दूर आंदोलन का एक केंद्र बनता जा रहा है. पिछले दो वर्षों से यहां जारी श्रमिक आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. यही वजह है कि मानेसर में पनप रहे मज़दूर असंतोष की चर्चा अब देश-विदेश के सम्मेलनों में होने लगी है. पिछले दो वर्षों से जारी इस लड़ाई को व्यापक जन-समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मुख्य धारा का मीडिया इसे लगातार नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि इससे उसके व्यवसायिक हित जुड़े हुए हैं. ■

इंद्रजीत की शहादत को सलाम!
कानपुर हमें तुम पर नाज़ है

घटना अनोखी नहीं थी, क्योंकि ऐसी घटना देश के किसी भी हिस्से में हो सकती है और होती भी रहती है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर अक्सर रोशनी नहीं पड़ती. कानपुर में अपने नागरिक कर्तव्य को अंजाम देते हुए इंद्रजीत सिंह उर्फ राजू सरदार ने शहादत क्या दी, पूरे शहर, पूरे समाज को उसकी सामाजिक ज़िम्मेदारी का इस कदर एहसास हुआ कि लोगों ने शासन-प्रशासन की ओर से किसी मदद-इमदाद का इंतज़ार न करके खुद अपने दम पर पाई-पाई जमाकर एक ऐसी रकम एकत्र कर दी, जो प्रभावित परिवार के लिए न सिर्फ़ एक मरहम है, बल्कि यह भरोसा भी कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे अनगिनत हाथ हैं. श्रमिकों की काशी कहलाने वाले कानपुर के इस जज्बे को सलाम कहना चाहिए.

महेंद्र अवधेश
mahendra.awdhesh@gmail.com

मई के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के कानपुर में शास्त्री नगर इलाक़े में चेन स्नेचरों से मोर्चा लेते समय अपनी जान गंवाने वाले इंद्रजीत सिंह उर्फ राजू सरदार के परिवार के लिए आर्थिक सहायता जुटाने का जो जज्बा स्थानीय नागरिकों, स्वैच्छिक-सामाजिक संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, गुरुद्वारों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, डॉक्टरों, व्यापारियों एवं पत्रकार समाज ने दिखाया, वह न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि आज के समय में, जबकि लोगों में संवेदना का स्तर शून्य हो गया है, एक राहत भरी आश्वस्ति का एहसास भी दिलाता है. सच तो यह है कि जन सहयोग की भावना ने इंद्रजीत के परिवार के भविष्य के लिए जो धनराशि (लगभग 16-17 लाख रुपये) एकत्र की है, वह बहुत बड़ी या पर्याप्त राशि तो नहीं है, लेकिन हक़ीक़त में यह राशि किसी सरकारी सहायता से लाख-करोड़ गुना महत्व रखती है.

किस-किस ने दिया पैसा और क्या सोच कर दिया, सवाल यह नहीं है, लेकिन किसी और की तरफ़ निहारने की बजाय अपने शहर के एक बेसहारा हो चुके परिवार के लिए यह उम्मीद पैदा करना कि उसका आने वाला कल अगर सुनहरा न हुआ, तो स्याह भी नहीं होने दिया जाएगा, यह अपने आप में एक बड़ी बात है. बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन कानपुर के लोगों ने इससे भी कहीं आगे बढ़कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि एक-एक सांस का दान किसी एक पूरे परिवार के लिए जीवन का वरदान बन सकता है. हम सरकारी कार्यालयों में कार्यरत लोगों पर पथभ्रष्ट होने का आरोप तो सहज चस्पा कर देते हैं, लेकिन अफसोस यह कि उनके द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य की चर्चा तक नहीं होती. इंद्रजीत के मामले में सरकारी महकमों के लोगों ने जो अपनापन दिखाया, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता.

वैसे भी कानपुर हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी की कर्मभूमि है, जो देश और समाज-सेवा के लिए आज भी गाहे-बगाहे याद किए जाते हैं. श्रमिकों की काशी रहा कानपुर कुछ मायनों में अभी भी बदला नहीं है, यह जानकर परम संतोष का अनुभव होता है. इंद्रजीत सिंह

की शहादत शहर में एक मिसाल इसलिए भी बनी है कि दूसरों की मुसीबत को अपना समझने की प्रवृत्ति आज लोप-सी हो गई है, ऐसी स्थिति में भी यह जज्बा और जुनून! सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है! कत्ल हो, लड़ाई-झगड़ा हो या फिर मार्ग दुर्घटना, हमारी मानसिकता कुल मिलाकर किनारा पकड़ कर किसी तरह वहां से निकल लेने की हो गई है. ऐसे में, इंद्रजीत सिंह ने अपनी जान पर खेलकर हमें बताया कि नहीं, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, लेकिन असल जीना तो दूसरों के लिए भी जीना है. ऐसे में, संजीव कुमार अभिनीत फिल्म बादल (1966) के लिए जावेद अनवर द्वारा लिखा यह गीत अनायास याद आ जाता है....अपने लिए जिए, तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल, जमाने के लिए...हम इंद्रजीत को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहर में, समाज में और भी इंद्रजीत पैदा ज़रूर कर सकते हैं. और, यही संदेश इस बार कानपुर ने समवेत स्वर में दिया है.

होता यह है कि ऐसी किसी भी घटना के मौक़े पर हम शासन-प्रशासन की बाट जोहते रहते हैं कि वह आगे आएगा और पीड़ित के आंसू पोछेगा. हालांकि कभी-कभी यह इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, जबकि पीड़ित की हालत बद से बदतर होती चली जाती है. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक गूंगी-बहरी किशोरी कुछ दिनों पहले मां बन गई, लेकिन शासन-प्रशासन ने उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया. नतीजतन, उसके मज़दूर माता-पिता अन्याय का शिकार होने के साथ-साथ इलाकाई साहूकारों के कर्जदार भी हो गए. सच तो यह है कि अब शासन-सत्ता की ओर से भी मदद की पहल तभी होती है, जबकि उसे भविष्य में कोई राजनीतिक फ़ायदा दीख रहा हो. आर्थिक सहायता-मुआवजा, संरक्षण और पुरस्कार-सम्मान की नीति में राजनीति इस कदर घुस गई है कि अब किसी से कोई उम्मीद रखना भी बेमानी है. उदाहरण के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. बीते दिसंबर माह में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी दामिनी के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 20 लाख रुपये की सहायता मिली. उसके बाद सीमा पर शहीद हुए एक सैनिक के परिवार को 20 लाख रुपये की सहायता मिली. और, कुंडा-प्रतापगढ़ में शहीद हुए सीओ जियाउल हक के परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता मिली. यानी जहां भी वोटबैंक की राजनीति का जादू चल जाता है, वहां राहत का मरहम भी समय से पहुंच जाता है. और जहां बदले में कुछ वापस मिलने की उम्मीद न हो, वहां का रास्ता सरकारी सहायता जल्दी नहीं तय करती. आश्चर्य की बात है? ■

कुशवाहा वोट की राजनीति

क्या पप्पू का महासमागम सफल होगा?

बिहार में कुशवाहा जाति की बहुलता है. माना जाता है कि यह समाज जिस दल के साथ होगी, वह चुनावी गणित बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है. ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने साथ करने की जुगाड़ में लगी हैं. कैसे, पढ़िए यह रिपोर्ट...

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बिहार में कुशवाहा वोटरों के दावेदारों की कमी नहीं है. सभी पार्टियां इस समाज के बारे में दावा करने से नहीं चूकतीं कि यह पूरा समाज उनके साथ है. यह समाज जिस पार्टी के साथ होती है, वह पार्टी चुनावी गणित को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. इस कड़ी में एक कवायद जदयू नेता और शिक्षा के कारोबार से जुड़े निरंजन कुमार पप्पू ने शुरू की है. हालांकि कई सालों से पप्पू अपने समाज के बीच घूम-घूमकर काम करते रहे हैं और सूबे के हर ज़िले में समाज के बीच उनकी पैठ जगजाहिर है. इस सिलसिले को अब जोर-शोर से आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पटना के गांधी मैदान में अंतरराष्ट्रीय कुशवाहा महासमागम आयोजित कराने का फ़ैसला किया है. दुनियाभर के नामी गिरामी हस्तियों को इस समागम में बुलाने की योजना है.

पप्पू बताते हैं कि कुशवाहा महासमागम का उद्घाटन मॉरीशस के प्रधानमंत्री करेंगे. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के अलावा, नेपाल, ब्रिटेन, पोलैंड, थाइलैंड, चीन और श्रीलंका के प्रतिनिधि भी इस समागम में शिरकत करेंगे. पप्पू ने बताया कि महासमागम की तैयारी के लिए राज्य के सभी 38 ज़िलों में पांच-पांच तैयारी संयोजक बनाए गए हैं. ये संयोजक प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक कमिटी बनाकर महासमागम के लिए राज्यभर में माहौल बनाएंगे.

गौरतलब है कि इस समागम को लेकर कुशवाहा समाज में चर्चा ग़रम है. दरअसल, चुनाव के आहट के साथ ही कुशवाहा समाज पर अपना दबदबा कायम करने के लिए नेताओं ने प्रयास शुरू कर दिया है. हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने भी गांधी मैदान में सफ़ल रैली कर अपनी ताक़त का एहसास और इस बिरादरी में अपने दबदबे का परिचय दिया था. जदयू में उसी दिन से बैचेनी थी और प्रयास यह चल रहा था कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा की ताक़त को कम किया जाए. जानकार बताते हैं कि इस समागम के पीछे जदयू की यह रणनीति है कि कुशवाहा समाज को अपने साथ बनाए रखा जाए. इसलिए इस समागम को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है, लेकिन निरंजन पप्पू कहते हैं कि समागम का एकमात्र मकसद है इस समाज में जागृति लाना. वह कहते हैं कि कुशवाहा समाज की आबादी इस सूबे में लगभग एक करोड़ है. यह समाज मेहनत रहा है और संघर्ष कर आगे बढ़ने की क्षमता भी रखता है. दुनियाभर में यह समाज फैला हुआ है. इस समागम के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि कुशवाहा समाज जहां भी है, वह पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या नेता से समाज के मसले पर हमारा कोई विरोध नहीं है. इस समागम में कोई राजनीतिक मसला नहीं है, यह तो केवल समाज को जागृत करने का एक प्रयास है. उन्होंने कहा कि हम इस समाज की नुमाइंदगी करने वाले सभी नेताओं के घर-घर जाकर उनसे इस समागम में आने का अनुरोध करेंगे. सम्राट अशोक फाउंडेशन के बैनर तले इस समाज में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा. ख़ासकर उन्हें ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि यह समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके. पप्पू ने यह भी कहा कि कोई भी इस समागम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे. वैसे, पप्पू जो भी दावा करें, लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज है कि इस समागम का राजनीतिक अर्थ भी है. अब देखना यह है कि इस समागम से राजनीति की कौन सी परिभाषा लिखी जाती है. पप्पू अगर इस महासमागम को सफल बना लेते हैं, तो यह माना जाएगा कि कुशवाहा समाज की एक बड़ी जमात उनके साथ है और यही जमातआगे आने वाले चुनाव में एक बड़ी ताक़त बनकर उभरेगी. ■

पिछले कुछ सालों से ऐसी स्थिति बना दी जाती है, जिससे संसद अपना कार्य नहीं कर पाती, यानी कुल मिलाकर देखें, तो संसद को कार्य ही नहीं करने दिया जाता.

www.kamalmorarka.com

नौ सालों में हासिल क्या हुआ?

यूपीए सरकार ने अपने नौ साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर उसकी कामयाबियों का बखान भी जोर-शोर से किया जा रहा है, लेकिन इसकी हक़ीक़त क्या है? यह सवाल उठाती एक विचारोत्तेजक टिप्पणी.

कमल मोरारका

संप्रग यानी यूपीए सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए. इन 9 सालों में सरकार ने क्या-क्या किया, इसे लेकर उसने एक रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया. यह सब ठीक है और यह एक नियमित अभ्यास भी है, जो हर सरकार करती है. सरकार का यह काम ही है कि वह लोगों को बताए कि उसने अपने कार्यकाल में कब क्या किया, लेकिन इन नौ सालों में पहले पांच साल यूपीए सरकार के लिए अहम रहे. उसी दौरान उसने नए क़ानून और नई योजनाएं बनाईं, वह चाहे सूचना का अधिकार अधिनियम हो या नरेगा योजना या फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल. लेकिन यहां एक सवाल ज़रूर उठता है कि यूपीए-2 ने बाद के चार सालों में क्या किया? इन चार वर्षों में यूपीए के पास दिखाने के लिए क्या बचा? कुछ नहीं. पहले पांच साल के विपरीत, बाद के चार सालों में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तथाकथित घोटाले ही सामने आए हैं.

इस रिपोर्ट कार्ड और उत्सव का उद्देश्य क्या है, इसे किसी के द्वारा भी समझा जा सकता है. ग़ौरतलब है कि एक वृद्धाश्रम या एक अनाथालय भी एक संस्थान के तौर पर कई सालों तक चलता है. यह सरकार भी नौ सालों तक चली. कैसे चली, यह बहस का विषय है. लेकिन यहां सवाल सरकार के लंबे समय तक चलने का नहीं है, बल्कि मूल सवाल यह है कि सरकार ने इतने लंबे समय तक क्या किया? जाहिर है, सरकार के पास अपनी उपलब्धि दिखाने एवं बताने के लिए घपलों-घोटालों के अलावा और क्या बचा है?

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जो संसद से जुड़ा है. पिछले कुछ सालों से ऐसी स्थिति बना दी जाती है, जिससे संसद अपना कार्य नहीं कर पाती, यानी कुल मिलाकर देखें, तो संसद को कार्य ही नहीं करने दिया जाता. संसद का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, क़ानून पारित करने वाली एक संस्था. लेकिन संसद का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जैसा कि पश्चिमी

दरअसल, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं, ताकि संसद चले ही नहीं. विपक्ष का काम है, जनता के मुद्दे को उठाना और सरकार का काम है जवाब देना. अगर सरकार चुप रहती है और फिर संसद बाधित होती है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? अगर सरकार एक उपयुक्त जवाब नहीं देगी, तो एक उपयुक्त समाधान कहां से आएगा?

देशों में, जहां लोकतंत्र लाया गया था, वहां के मुताबिक़ संसद बहस के लिए सक्षम हो, वह जनता के मन की बात सामने रख सके और उस पर चर्चा कर सके. और अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर जनता के भीतर गुस्सा पनपेगा, जो भयानक रूप भी ले सकता है. इसलिए यह ज़रूरी है कि जिस जनता ने आपको अपनी बात संसद के भीतर रखने के लिए चुनकर भेजा है, आप वह काम करें, यानी जनता के मूड, मांग और विचार को संसद में रखें, उस पर बहस-चर्चा करें और फिर क़ानून बनाएं. लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझ कर संसद को अपना काम नहीं करने दिया जाता है. दरअसल, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं, ताकि संसद चले ही नहीं. विपक्ष का काम है, जनता के मुद्दे को उठाना और सरकार का काम है जवाब देना. अगर सरकार चुप रहती है और फिर संसद बाधित होती है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? अगर सरकार एक उपयुक्त जवाब नहीं देगी, तो एक उपयुक्त समाधान कहां से आएगा? अगर सरकार विपक्ष का सामना करने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या होगा?

दरअसल, यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह संसद को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करे. उसे संवेदनशील होना चाहिए. अगर वह संवेदनशील नहीं है, तो फिर विपक्ष ज़िम्मेदार नहीं हो सकता. अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए ही इन लोगों को जनता चुनकर भेजती है. लोगों के लिए चिंता के कई विषय हैं, जैसे मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार और क़ानून-व्यवस्था की समस्या. आख़िर इन सब पर संसद के भीतर बहस क्यों नहीं होती है? सरकार यह क्यों नहीं बताती है कि उसने क्या क़दम उठाए हैं और क्या कार्रवाई की है. संसद को अपना काम करने से रोककर आप संसद का अपमान कर रहे हैं. अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री ख़ुद इन सारे मसलों को देखें और एक उचित समाधान निकालें.■

feedback@chauthiduniya.com

क्या यही है सच्चा देश प्रेम!

ठाकुरदास बंग
feedback@chauthiduniya.com

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि इस देश में उद्योगों का विकास होना है, तो खेती का उत्पादन बढ़ाकर वह माल सस्ता से सस्ता प्राप्त करते जाना चाहिए. इस कथन का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है, किसान नेता श्री शरद जोशी ने बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय कृषि वस्तु मूल्य समिति की रिपोर्ट में पृष्ठ 15-16 पर लिखा गया है कि किसान को माल पैदा करने में जो उत्पादन ख़र्च आता है, वह क़ीमत के रूप में देना व्यवहार्य नहीं है. क्योंकि यदि यह लागत ख़र्च निकालना हुआ, तो किसान कुटुम्ब के सदस्यों की मज़दूरी हिसाब में पकड़नी होगी. ऐसा किया गया, तो कारख़ानों को कच्चा माल और अनाज महंगा ख़रीदना पड़ेगा. और इससे कारख़ाने के मज़दूरों की रोज़ी बढ़ानी पड़ेगी. इसलिए दुनिया की मंडियों में इस भारतीय महंगे माल की प्रतियोगिता करना कठिन जाएगा. वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने ऐसा अजब तर्क दिया कि किसान परिवार के लोगों के श्रम उपज का लागत ख़र्च निकालने में क्यों गिने जाएं, उन्हें दूसरी जगह नौकरी तो नहीं मिलने वाली है. वे तो छोटे-छोटे फुटकर काम करते रहते हैं. यानी सच पूछा जाए, तो वे कुछ काम ही नहीं करते हैं. इस प्रकार के अत्यंत क्रूर कथन सरकारी रिपोर्टों में जगह-जगह लिखे गए हैं.

इसका परिणाम वही होना था, जो हुआ, क्योंकि भारत के किसान-मज़दूरों का दारिद्रय बढ़ा. करोड़ों लोग कंगाल हो गए. हर साल कच्चा माल सस्ता एवं पक्का माल महंगा होता चला गया. दरअसल, इस नीति के कारण ही प्रति वर्ष किसानों का दस हज़ार करोड़ रुपये का शोषण होता है, यह एक हिसाब है. गांव के लोग अधमरे-से हो गए, क्योंकि उन्हें दो जून मोटा अनाज भी पर्याप्त मात्रा में समय पर खाने को नहीं मिलता है. ऐसे में पूरा कपड़ा छोटा ही सही, लेकिन व्यवस्थित मकान, शिक्षा एवं प्राथमिक आरोग्य की बात ही व्यर्थ है. ऐसी परिस्थिति में अकाल आते रहते हैं. औद्योगिकीकरण के लिए जंगलों की बेतहाशा कटाई होने की वजह से बारिश न केवल कम हुई, बल्कि और अनियमित हुई. जब फ़सल पैदा नहीं हुई, तो किसान-मज़दूर काम के अभाव में मारे-मारे भटकने लगे और रिलीफ के कामों में या खिचड़ी के लिए हाथ फैलाने के वास्ते विवश हो गए. ऐसे में किसान पर क़र्ज़ बढ़ने लगा और क़र्ज़ के बाहर निकलने की सूरतें उसकी नज़रों से धीरे-धीरे ओझल होने लगीं. बैल मर गया, घर की दीवाली ढह गई, तो बैल ख़रीदने के लिए या दीवाल बनाने के लिए वह पैसा कहां से लाएं. शादी जैसे प्रसंगों पर सामान्य पारिवारिक ख़र्च तो करना ही होता है. शासन की नीतियों के कारण शराब की बिक्री बढ़ी. गाय-बैलों के बेतहाशा क़त्ल होने के

बीसवीं सदी के छठे और सातवें दशक तक हरित क्रांति अवतीर्ण नहीं हुई थी. नीचे के आंकड़ों से साफ़ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से योजनाकारों ने यह समझ-बूझकर तय किया कि कम से कम प्रतिशत ख़र्च कृषि पर किया जाए और योजना का अधिक प्रतिशत उद्योग, संचार व्यवस्था आदि में लगाया जाए.

कारण बैल महंगे हो गए, नई-नई फैशन की चीज़ें देश में गांवों तक आने लगीं और इस कारण ख़र्च और बढ़ गया. लेकिन फिर सवाल यही उठा कि पैसा कहां से लाया जाए, इसके लिए क़र्ज़ बढ़ने लगा. पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लड़कों में खेती का बंटवारा होने के कारण खेती की जोतें छोटी-छोटी होने लगीं और ग्रामीण बंधु निराशा में आकंठ डूब गए. कृषि ही एकमात्र धंधा है, जिसमें प्रकृति गुणन करती है, यानी एक बीज के अनेक गुना दाने देती है. लेकिन उल्लेखनीय है कि और धंधों में यह नहीं होता. इसलिए कृषि का यह अतिरिक्त मूल्य पूंजी के रूप में बनकर उद्योगों को मिलना चाहिए, क्योंकि कृषि के सरप्लस से ही पूंजी निर्माण होता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि शहरों में वह क्यों जाए. यदि वे देहातों में ही किसानों के पास रहे, तो वे गांवों में उद्योग खोल सकते हैं.

औद्योगिकीकरण के लिए शासन की नीति रही कि शहरों में विपुल मात्रा में सस्ता अनाज और कच्चा माल उपलब्ध हो. इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में और हरित क्रांति के प्रारंभ के समय यह तय किया गया कि देश में सभी जगह नई कृषि-तकनीकी और सिंचाई आदि की सुविधाएं फैलाने से उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन एक सच यह भी सामने आया कि सदियों से भूखा ग्रामीण वह अनाज खा जाएगा. और इसका परिणाम यह होगा कि शहर की मंडियों में अधिक उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं आ पाएगा. अतः निर्णय यह लिया गया कि जहां किसान अधिक दरिद्र नहीं है, यानी जहां उसका पेट अपेक्षाकृत भरा हुआ है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि स्थानों में सिंचाई की सुविधाएं और नई तकनीकी विशेष रूप से लगाई जाए. इससे बहुत अधिक उत्पादन होगा और पहले से ही किसानों का पेट भरा होने के कारण बढ़ा हुआ उत्पादन किसान शहर की मंडी में लाएगा. इससे अनाज और कच्चा माल न केवल कारख़ानों, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी सस्ते में मिलेगा और औद्योगिक माल पर कृषि अधिकाधिक अवलंबित होगी. पहले कृषि ऐसी नहीं थी. थोड़े में सारा ध्यान इसी एक धुरी के इर्द-गिर्द घूमता रहा और इसके अनुकूल शासकीय नीतियां निर्मित होती रहीं कि नगर-निवासियों को कृषि का उत्पादन सस्ता मिले, भले ही कृषकों को लागत-क़ीमत मिले या न मिले. इसीलिए कवि दिनकर ने ठीक ही गाया है- कृषक मेधे की रानी दिल्ली. पुराने ज़माने में अश्वमेध यज्ञ होता था. नए ज़माने में भारत में कृषक-मेध हो रहा है.

बीसवीं सदी के छठे और सातवें दशक तक हरित क्रांति अवतीर्ण नहीं हुई थी. नीचे के आंकड़ों से साफ़ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से योजनाकारों ने यह समझ-बूझकर तय किया कि कम से कम प्रतिशत ख़र्च कृषि पर किया जाए और योजना का अधिक प्रतिशत उद्योग, संचार व्यवस्था आदि में लगाया जाए. इसलिए कृषि की उन्नति अधिक नहीं हो सकी. जनसंख्या लगातार बढ़ ही रही थी, इसलिए बाज़ार में अनाज और कपास आदि कच्चे माल का अपेक्षाकृत अभाव बना रहा. कृषि में उत्पादित माल की क़ीमतें ऊपर जाने लगीं. तब गोरे अंग्रेजों ने विश्व-युद्ध के ज़माने में जो किया था, वही उन काले अंग्रजों ने किया. दरअसल, सस्ते भाव में, यानी लागत मूल्य से कम दाम में अनाज किसान से प्राप्त करने के लिए शासन ने लेवी लगाई. और किसान के खेत में माल पैदा हुआ हो या न हुआ हो, तो भी अनेक किसानों को बाज़ार से महंगा अनाज ख़रीदकर सरकार को सस्ते दाम में लेवी देनी पड़ी या इन दोनों भावों में फ़र्क़ जितनी रक़म, नक़द भरनी पड़ी. कई बार अपने लिए आवश्यक अनाज में से सरकार को लेवी देनी पड़ी और ख़ुद के परिवार के लिए महंगा अनाज बाज़ार से किसान को ख़रीदना पड़ा. इस प्रकार अत्यंत क्रूर रीति से लेवी के नियमों पर अमल किया गया. अभाव की परिस्थिति में क़ीमतें नीची रखी गईं. लेकिन इसी क़ीमत पर भारतीय किसान से कपास या गेहूं नहीं ख़रीदा गया और महंगे दाम देकर विदेशी किसानों से गेहूं ख़रीदा गया. वाह रे देश-प्रेम!■

पाठकों की दुनिया

सियासी दल करें पहल

देश से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए अन्ना हजारे से लेकर कई समाजसेवी अपनी तरफ़ से हरसंभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार पूरी तरह तो दूर, कण भर भी समाप्त नहीं हो सका है. देश के नेता न केवल भ्रष्टाचार की गंगा में ख़ुद नहा रहे हैं, बल्कि साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी डुबकियां लगवा रहे हैं. ऐसे हालात में देश से भ्रष्टाचार को दूर करने की बातें मात्र काग़ज़ी ही साबित होती हैं. दरअसल, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक देश से भ्रष्टाचार को बाहर करना सपने देखने के बराबर है.

सरकार को सबसे पहले अपना दामन साफ़ करने के लिए दाग़ी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर देश की जनता को यह संदेश देना होगा कि देश से इस समस्या को मिटाने के लिए सियासी दल मात्र बातें ही नहीं करते, बल्कि उस पर अमल भी करते हैं.

-शिबली रामपुरी, सहारनपुर, *उत्तर प्रदेश*

ख़ामियां क्यों हैं पुलिस प्रणाली में?

लगभग बीस लाख से भी ज़्यादा पुलिस की संख्या हमारे भारत में है. क़ायदे के मुताबिक़, आंतरिक सुरक्षा का दारोमदार हमारे पुलिस बल पर ही निर्भर है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी सशक्त जनशक्ति होते हुए भी हमारा समाज असुरक्षा के दायरे में ही जी रहा है, जो कि एक यक्ष प्रश्न है इस व्यवस्था के लिए. कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी देश में रहता हो, उसका अपने पुलिस बल से सीधा साबका पड़ता है. पुलिस पर आरोपों की कमी नहीं है. सत्ता प्रतिष्ठानों के लिए काम करना, ख़ास समुदायों के साथ भेदभाव करना, भ्रष्ट होना वग़ैरह-वग़ैरह. फिर भी ज़्यादातर देशों में जनता को यही लगता है कि पुलिस इन्हीं लोगों के लिए काम करती है, जिनके पास धन, बल और ताक़त है. बोस्टन (अमेरिका) विस्फोट में अमेरिका की पुलिस और सुरक्षा बल जिस तरह से कार्रवाई करते दिखे, वह एक सबक़ है पूरी दुनिया के लिए. इस दौरान एक अच्छी बात यह भी दिखी कि बोस्टन के लोगों और आसपास के नगर निकायों ने पुलिस बल के साथ जमकर सहयोग किया.

आश्चर्य की बात तो यह है कि मीडिया ने भी घटनास्थल से दूरी बनाए रखी. दरअसल, लोग घरों में ही दुबके रहे. उन लोगों के मन में पुलिस सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर सराहना का भाव था. सप्ताहांत के बाद आतंकवादियों की गिरफ्तारी के पश्चात जब सुरक्षा बल वापस लौट रहे थे, तो तमाम लोगों ने गलियों में पंक्तिबद्ध होकर करतल ध्वनि से उन बहादुरों का शुक्रिया अदा किया. बोस्टन में जिस तरह से स्थानीय पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों ने पूरी स्थिति संभाली और आम लोगों से लगातार संवाद बनाए रखा, वह सचमुच सराहनीय था. यह एक मिसाल है हम सबके लिए, जबकि मुंबई में हुए 26/11 के हमले को यदि याद करें, तो हम पाएंगे कि वहां सर्वत्र सांसद और विधायक एवं मीडिया एक दूसरे की भूमिका को केवल साझा करते हुए दिखे. किसी ने भी जनता की सुध नहीं ली, उनसे संवाद नहीं क़ायम किया. अवाम को कुछ भी नहीं कहा गया. कोई सफ़ाई नहीं दी गई, जबकि यह बेहद ज़रूरी था. दरअसल, बुरे और अच्छे लोग हर जगह हैं, लेकिन व्यवस्था, क़ानून और क़ायदा दुरुस्त होना चाहिए.

-अशोक निर्मोही (मुन्ना), *दरभंगा, बिहार*

यह बीमारी और फैलेगी, यदि ...

क्रिकेटर बन गए फिर फिक्सर. दोषी क्रिकेटरों के ख़िलाफ़ यदि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह बीमारी और, और फैलेगी. ऐसे में हमारे ये तथाकथित हीरो एक दिन जीरो की श्रेणी में आ जाएंगे. यह हम सभी जानते हैं कि इस खेल में, यानी क्रिकेट फिक्सिंग में बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इन खिलाड़ियों पर लगाम कसनी पड़ेगी और इसकी व्यवस्था भी करनी होगी कि इन्हें सख्त सज़ा मिले और हम भविष्य में जब इनके ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई कर पाएंगे, तभी दूसरे खिलाड़ी ऐसा घिनौना काम करने में हिचकिचाएंगे, शर्म महसूस करेंगे. शायद यह देख कर बड़ों को भी शर्म आ जाए.

युद्ध से समस्या का हल नहीं हो सकता?

चारों ओर भ्रष्टाचार और घूसख़ोरों की चर्चा है. अभी पवन बंसल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि क्रिकेट फिक्सिंग का मामला सामने आ गया. दूसरी तरफ़ भारत पर चीन का दबाव भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है. क्या चीन युद्ध चाहता है, जबकि हम सभी जानते और मानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता. लेकिन हम यह तो कर ही सकते हैं कि हम उन मंचों पर चीन का समर्थन करने से पहले उनसे डील तो कर ही सकते हैं. क्यों हम वैश्विक मंचों पर बार-बार चीन का समर्थन करने से बाज़ नहीं आते हैं. क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं हम? ■

-समर दत्त, *दिल्ली*

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

मुसलमान उसी तरह एक देश हो सकता था, जिस तरह हिंदू एक था, लेकिन दोनों समुदाय स्वतंत्रता पूर्व के भारत के सभी हिस्सों में बिखरे हुए थे.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

समाचारों का स्थानीयकरण बेहद चिंताजनक

भारत में एक मज़ेदार खेल समाचारपत्रों द्वारा खेला जा रहा है. सूचनाओं का प्रवाह रुक गया है और उसे रोकने में सबसे बड़ा रोल समाचारपत्रों का ही है. न केवल समाचारपत्र इस स्थिति में ख़ुश हैं, बल्कि सरकार को भी यह स्थिति रास आ रही है. पिछले 25 सालों में समाचारों का स्थानीयकरण बहुत तेजी से हुआ है. 20 या 25 साल पहले जनेऊ, मुंडन, शादी, जन्मदिन एवं छोटे अपराध जैसी ख़बरें समाचारपत्रों में अपनी जगह नहीं बना पाती थीं, लेकिन पहले समाचारपत्रों के राज्य संस्करण निकले, फिर उनके क्षेत्रीय संस्करण निकले और अब ज़िले के संस्करणों से बात आगे बढ़कर तहसील संस्करणों तक पहुंच चुकी है. समाचारपत्रों का समाचारों वाला हिस्सा ज़िले और तहसील में घट रही घटनाओं के ऊपर ज़्यादा आधारित होता है. जनता अपने समाचारों को अख़बार में छपा देखकर ख़ुश हो जाती है और अख़बार भी छोटे से छोटे समाचारों को छापने में सहूलियत महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें इसके लिए अन्यत्र कहीं जाना नहीं पड़ता. अपराध के समाचार ऐसी स्थिति में ज़्यादा प्रमुखता पा जाते हैं, पर अपराध के समाचारों और उन्हें पढ़ने वालों का दायरा बहुत छोटा होता है. दरअसल, अब ख़बरें एक ज़िले में भी नहीं दौड़तीं. जो लोग यह सोचते हैं कि उनकी ख़बरें समाचारपत्रों में छप गईं और उनसे सारा ज़िला या सारा प्रदेश परिचित हो गया, तो वे एक बहुत बड़े भ्रम में हैं. सच तो यह है कि उनकी ख़बरों को ज़िले के अधिकारी तक नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर ज़िले में ही दो या तीन तरह के संस्करण उपलब्ध हों, तो ज़िले का अधिकारी ज़्यादातर उस संस्करण को ही पढ़ता है, जहां उसका घर होता है और उस घर को कवर करने वाला क्षेत्र होता है.

पहले समाचारपत्रों में छपी ख़बरें अधिकारियों के ऊपर अंकुश का काम करती थीं और इसीलिए उन्हें यह डर रहता था कि अगर यह समाचार राजधानी में बैठे उच्चाधिकारियों या मंत्रियों तक पहुंच गई, तो उनसे सवाल–जवाब हो सकता है. इसीलिए वे अख़बारों में छपी ख़बरों के ऊपर ध्यान देते थे और कोशिश करते थे कि समस्याओं का समाधान हो जाए, ताकि अख़बारों में ऐसी ख़बरें छपे ही ना. पर अब ज़िले के अधिकारी इस स्थिति से बहुत ख़ुश हैं, क्योंकि अब उन्हें समाचारों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. इसीलिए समाचारों का असर प्रशासन और शासन पर से अब समाप्त हो गया है. यही नहीं, ख़बरों की गुणवत्ता भी घटी है. आज से 20 या 25 साल पहले ख़बरों को तलाशने और उनकी पुष्टि करने के पीछे पहला मक़सद यही होता था कि ख़बर ग़लत न साबित हो जाए और ख़बरें अपना सम्मान न खो दें. इसीलिए 25 साल पहले छपी ख़बरों के ऊपर प्रशासन और शासन ध्यान देता था, लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं होती.

> **कुछ अख़बारों ने पैसे लेकर चुनाव में ख़बरें छापने की परंपरा क्या चलाई कि हर अख़बार को आम पाठक शक की नज़र से देखने लगा है, पर इससे बड़ा ख़तरा समाचारों के स्थानीयकरण का है, क्योंकि ऐसे में एक ज़िले में घटी घटना दूसरे ज़िले में नहीं जा पाती. आधे ज़िले की घटना पूरे ज़िले में नहीं जा पाती! पहले पृष्ठ पर दिल्ली में घटी कुछ घटनाएं ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन वे सिर्फ़ एक झलक भर होती हैं.**

पहले अख़बार में छपी ख़बरों के ऊपर हर जगह से निराश व्यक्ति की आशा टिक जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जब कोई उसकी बात नहीं सुनेगा और ऐसे में अगर उसकी बात अख़बार के लोग सुन लेंगे, तो उसकी समस्या का निदान आसानी से हो जाएगा. पर अब लोगों की यह आशा भी धीरे–धीरे समाप्त हो रही है. अब लोग कहने लगे हैं कि बहुत छोटी क़ीमत पर अख़बारों में ख़बरें छप जाती हैं. हालांकि इस तरह के आरोप पहले भी लगते थे कि ज़िले से निकलने वाले अख़बार ब्लैकमेलिंग जैसे काम में शामिल हो जाते हैं. वे स्थानीय ठेकेदारों या छोटे अफसरों के बारे में ख़बरें छापने का डर दिखाकर कुछ पैसों की वसूली कर लेते हैं. हो सकता है, कुछ जगहों पर ऐसा होता रहा हो, पर यह बड़े पैमाने पर होने लगेगा, ऐसा कभी कल्पना में नहीं था. आज हालात ये हैं कि सारे देश में पेड न्यूज़ को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा है कि हर अख़बार एक बाज़ार की वस्तु दिखाई दे रहा है. कुछ अख़बारों ने पैसे लेकर चुनाव में ख़बरें छापने की परंपरा क्या चलाई कि हर अख़बार को आम पाठक शक की नज़र से देखने लगा है, पर इससे बड़ा ख़तरा समाचारों के स्थानीयकरण का है, क्योंकि ऐसे में एक ज़िले में घटी घटना दूसरे ज़िले में नहीं जा पाती. आधे ज़िले की घटना पूरे ज़िले में नहीं जा पाती! पहले पृष्ठ पर दिल्ली में घटी कुछ घटनाएं ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन वे सिर्फ़ एक झलक भर होती हैं. इसका नतीजा यह होता है कि पाठक देश की घटनाओं एवं समस्याओं से बिल्कुल अनजान और अछूता रह जाता है. ज़मीन के संघर्ष, ग़रीबों पर होने वाले अत्याचार या किसी अन्याय के प्रति लोगों द्वारा किए गए सशक्त विरोध को अख़बारों में कोई स्थान ही नहीं मिल पाता है. और अगर मिलता भी है, तो उसकी जानकारी पूरे ज़िले को ही नहीं हो पाती है, पड़ोस के ज़िलों और प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए.

यह सारी स्थिति बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि पहले अख़बार में छपी ख़बरें शासन और प्रशासन को इस बात का आभास देती थीं कि किस तरह की हलचल लोगों में हो रही है, लेकिन आज वे जानकारियां उन्हें नहीं मिल पातीं. उनकी जानकारी के स्रोत सिर्फ़ इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, जो अपना काम जिस समझदारी से करती हैं, उसकी मिसालों की एक लंबी फेहरिस्त है. इसीलिए शासन–प्रशासन न तो लोगों के प्रति अपनी कोई ज़िम्मेदारी अनुभव करता है और न ही उन समस्याओं के ऊपर ध्यान देता है, जिन्हें लेकर सबसे निचले स्तर पर असंतोष पैदा हो रहा होता है.

ऐसी स्थिति में लोगों के सामने राष्ट्रव्यापी समाचारों को जानने का सिर्फ़ एक माध्यम टेलीविज़न रह जाता है. टेलीविज़न भी ज़्यादातर सनसनी फैलाने वाले समाचारों को दिन भर पीटते रहते हैं. एक ज़रिया दूरदर्शन ज़रूर है, जो लोगों के लिए समाचार उपलब्ध कराता है, पर अफसोस! अब वह भी उसी ढर्रे पर चल पड़ा है, जिस पर बाक़ी टेलीविज़न चैनल चल रहे हैं. दरअसल, समाचार चैनल समाचारों की मसखरी, समाचारों का उथलापन और समाचारों का ग्लैमर ही लोगों तक ले जाते हैं. जो समाचार ग्लैमरस नहीं होते हैं, वे उनके लिए त्याज्य होते हैं और इसीलिए वे उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उन्हें कवर ही नहीं करते. यह सारी स्थिति संपूर्ण देश के लिए भयावह है. उत्तर के लोगों को दक्षिण के लोगों की और दक्षिण के लोगों को उत्तर के लोगों की जानकारी नहीं मिलती. देश में ज़मीन के संघर्ष धीरे–धीरे नक्सलवादियों की बढ़ोत्तरी में आग में घी जैसा काम कर रहे हैं, पर इसकी जानकारी सरकारों को नहीं है और राजनेताओं को बिल्कुल नहीं है. इसीलिए यह मानना चाहिए कि समाचारपत्र दो तरह से लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं. वे उन लोगों, जो जनता की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, के पास जानकारी नहीं जाने देना चाहते और जिन लोगों की समस्याएं हैं, उन्हें वे ख़तरनाक ढंग से संगठित होने का अवसर देते हैं और देश में एक निराशा का वातावरण पैदा करते हैं. समाचारपत्रों के मालिकों, अधिकारियों एवं राजनेताओं का यह गठजोड़ इस देश में किस तरह की नई समस्याएं पैदा करेगा, अगर उन्हें हम सोचें, तो माथा ठनक जाता है. इसके बावजूद समाचारपत्रों का स्थानीयकरण होने का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है और आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकारें इसे अपने लिए शुभ संकेत मानकर ख़ामोश बैठी मुस्करा रही हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

परिवर्तन की राह पर पाकिस्तान

पाकिस्तान में हाल में हुए चुनावों ने नई उम्मीदों को जन्म दिया है. इस आशा को विशेष बल मिला है कि अवाम को अब तक जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे उसे निजात मिलेगी. पेश है एक गंभीर, विश्लेषणात्मक टिप्पणी.

पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर है. 1999 में जब सेना द्वारा नवाज़ शरीफ को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, तो ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान में हमेशा किसी भी चुनी हुई सरकार को सेना द्वारा हटाया जाएगा. अब कम से कम पहली बार कोई लोकतांत्रिक सरकार सत्ता लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई किसी सरकार को सौंपेगी. नवाज़ शरीफ को सबसे अधिक सीटें मिली हैं. इमरान ख़ान ने ख़ुद को दूसरे विकल्प के तौर पर पेश किया. हालांकि पाकिस्तान के मतदाता उनके प्रलोभन में नहीं आए, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उन्हें खारिज भी नहीं किया. उनकी पार्टी ख़ैबर पख्तून–ख्वा में क्षेत्रीय दल बनेगी, क्योंकि उसे इस प्रांत में सरकार बनाने लायक़ बहुमत मिला, जैसा कि सिंध में पीपीपी को मिला. नवाज शरीफ पीएमएल (एन) का नेतृत्व करते हैं, जो कि पंजाब की पार्टी है. पाकिस्तान के लिए पंजाब की वही अहमियत है, जैसी कि पुराने जर्मनी के लिए प्रुसिया की थी. पाकिस्तान के भविष्य के बारे में भारतीय एवं विदेशी लेखकों द्वारा बहुत कुछ लिखा जाता रहा है. हम लोग कहते रहे हैं कि पाकिस्तान एक पेचीदा राष्ट्र है. बहुत सारे लोग कहते रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा और रूढ़िवादी इस्लामिक संगठन तालिबान या कोई दूसरा सत्ता में आएगा. मैंने हमेशा महसूस किया कि पाकिस्तानी पंजाब के लोग संभ्रांत हैं और देश को वही नियंत्रित करते हैं, इसलिए वे पाकिस्तान को गर्त में नहीं जाने देंगे. उन्होंने पिछले 67 सालों से यह देश चलाया है, चाहे शासन सेना के हाथ में रहा हो या फिर लोकतांत्रिक सरकार के हाथ में. आगे भी वे इसी तरह देश को चलाएंगे.

> **1971 में पाकिस्तान को फिर इस प्रश्न का सामना करना पड़ा कि वह एक राष्ट्र है या दो. जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहते थे, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र नहीं, बल्कि वह पश्चिमी तरीक़े का उदार देश चाहते थे. बाद में वहां शासन करने वाले जनरलों और सिविल सेवकों के पास भी इसका उत्तर नहीं था. जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यह अनुभव किया गया कि धर्म के आधार पर एकता स्थापित नहीं की जा सकती, बल्कि भाषा विभाजन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है. ऐसे में देखा जाए, तो पाकिस्तान क्या था?**

पाकिस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या इस बात की है कि वहां राष्ट्रीय पहचान की कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है. जिन्ना ने हमेशा यह तर्क दिया कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में दो राष्ट्र थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय भी दो राष्ट्रीय राज्य नहीं थे. मुसलमान उसी तरह एक देश हो सकता था, जिस तरह हिंदू एक था, लेकिन दोनों समुदाय स्वतंत्रता पूर्व के भारत के सभी हिस्सों में बिखरे हुए थे. क्या सभी लोग 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर राजी हुए थे, जिससे भारत अविभाजित रह सकता था और जिसे तीन क्षेत्रीय उप–परिसंघों में बांटा जाता. इस अविभाजित भारत को तीन क्षेत्रों, मौजूदा पाकिस्तान, जिसमें पूरा पंजाब होता, मौजूदा भारत, जिसमें असम एवं बंगाल न होते और तीसरा असम एवं बंगाल का क्षेत्र, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान बना. इसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना. 1971 में पाकिस्तान को फिर इस प्रश्न का सामना करना पड़ा कि वह एक राष्ट्र है या दो. जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहते थे, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र नहीं, बल्कि वह पश्चिमी तरीके का उदार देश चाहते थे. बाद में वहां शासन करने वाले जनरलों और सिविल सेवकों के पास भी इसका उत्तर नहीं था. जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यह अनुभव किया गया कि धर्म के आधार पर एकता स्थापित नहीं की जा सकती, बल्कि भाषा विभाजन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है. ऐसे में देखा जाए, तो पाकिस्तान क्या था?

किसी भी राष्ट्र को दूसरे द्वारा परिभाषित किया जाना काफी नहीं है. पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अपने राष्ट्र को भारत के साथ शत्रुता के आधार पर परिभाषित करते हैं. भारत के भी कुछ लोग, विशेषकर हिंदुत्ववादी, इसी तरीके से भारत को पाकिस्तान के साथ शत्रुता के आधार पर परिभाषित करते हैं, लेकिन किसी भी देश को सकारात्मक परिभाषा की ही ज़रूरत होती है. पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दूसरे देशों से अलग नहीं है, जहां कोई स्पष्ट पहचान नहीं है. भारत एक अपवाद है, क्योंकि इसकी पहचान को परिभाषित करने के लिए नेहरू थे, जबकि पाकिस्तान बनने के कुछ समय बाद ही जिन्ना की मृत्यु हो गई थी. बांग्लादेश एक अलग देश बनने के बाद तब तक लड़खड़ाता रहा, जब तक कि उसने लोकतांत्रिक संविधान नहीं बना लिया. श्रीलंका 25 सालों तक गृहयुद्ध से जूझता रहा. वह सभ्य एवं उदार राष्ट्र से एक क्रूर बुद्धिस्ट गणराज्य बन गया. पाकिस्तान भी अब उत्तर देने के क़रीब पहुंचता दिखाई दे रहा है. वह एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश बनेगा, जहां विशाल मुस्लिम जनसंख्या तो होगी, लेकिन इस्लामिक राज्य नहीं होगा. पाकिस्तान ने बहुत खराब नहीं किया है. स्वतंत्रता के बाद पहले 50 सालों तक पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट भारत से अच्छा नहीं रहा, लेकिन भारत के बराबर ज़रूर था. उसके पास भी भारत की तरह नाभिकीय हथियार हैं. हो सकता है, पाकिस्तान अपने बारे में फिर से सोचना शुरू करे और यह तय कर ले कि वह सकारात्मक तौर पर क्या बनना चाहता है. भारत को इस तरह के पाकिस्तान से ही फ़ायदा हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

इस मॉडल ने गुड़िया का लुक पाने के लिए लाखों रुपये स्वाहा कर दिए. उन्होंने अपनी पहली सर्जरी 19 साल की आयु में करवाई थी.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

अगर पेंशन मिलने में परेशानी हो...

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बिहार के जमालपुर से आर के निराला ने हमें पत्र के माध्यम से दो मामलों के बारे में सूचित किया था. दोनों घटनाएं नगर परिषद, जमालपुर से संबंधित थीं. पहला मामला था चंपा देवी का. चंपा देवी नगर परिषद जमालपुर में सफ़ाई मज़दूर के रूप में नियुक्त थीं. रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का भुगतान अब तक नहीं हो पाया था, जबकि पटना हाईकोर्ट ने भी भुगतान का आदेश दे दिया था. दूसरा मामला बेबी देवी का था, जिनके पति की मृत्यु नौकरी के दौरान ही हो गई थी, लेकिन उन्हें अब तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकी थी. इन दोनों मामलों में समानता थी, यानी अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफ़ी, लालफ़ीताशाही और अड़ियल रवैया. लेकिन आरटीआई क़ानून ऐसे ही अधिकारियों को सही रास्ते पर लाने का काम करता है. यहां पर इन दोनों घटनाओं का ज़िक्र इसलिए भी किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी विभागों में अधिकांश मामले ऐसे ही होते हैं. बाबुओं की फाइल दबाऊ नीति अपनाने के कारण आम आदमी परेशान होता रहता है. कभी पेंशन, कभी नौकरी या कोई अन्य मामला. सरकारी बाबू बिना रिश्वत लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते और ऐसे में लोग दफ्तर के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं. तब, ऐसे ही मामलों में आरटीआई (सूचना क़ानून) का असर दिखता है.

अगर किसी सरकारी दफ्तर में आपका भी ऐसा ही कोई मामला फंसा हो, तो आप पहले एक साधारण आवेदन देकर अपनी शिकायत अधिकारी तक पहुंचाएं और याद करके अपने आवेदन की प्राप्ति रसीद ज़रूर ले लें. साथ ही आवेदन की एक फोटो कॉपी भी अपने पास रखें. अगर सप्ताह, दस दिनों के भीतर आपके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर आप सूचना का अधिकार क़ानून के तहत एक आवेदन देकर अपने पहले वाले आवेदन पर हुई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगे. ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि आरटीआई आवेदन डालते ही अधिकारी/कर्मचारी हरकत में आ जाते हैं, क्योंकि क़ानून के मुताबिक़ उन्हें 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है. हमें विश्वास है कि यदि आप सूचना क़ानून का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका काम ज़रूर होगा वह भी बिना रिश्वत दिए. इस अंक में हमने उक्त दोनों मामलों से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित किया है, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या का समाधान या सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र/ईमेल या फोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

किसी विभाग में लंबित पड़े मामले से संबंधित आवेदन:

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम
पता-

दिनांक-

विषय:-सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के तहत आवेदन

मैंने अपने केस के संबंध में एक आवेदन आपके विभाग में जमा कराया था. (पूर्व में आपने जो साधारण आवेदन दिया था, उसकी एक कॉपी संलग्न करें) लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. कृपया इस संबंध में मुझे निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं.

1. मेरे आवेदन पर हुई कार्रवाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.

2. उन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम और पदनाम बताएं, जिनके पास मेरा आवेदन इस दौरान रहा. कृपया यह बताएं कि किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास कितने वक़्त तक मेरा आवेदन रहा और उन अधिकारियों/कर्मचारियों ने उन पर क्या कार्रवाई की?

3. मेरा आवेदन एक अधिकारी/कर्मचारी से दूसरे अधिकारी/कर्मचारी को जब-जब प्रेषित किया गया या प्राप्त किया गया, उसका प्रमाण उपलब्ध कराएं.

4. आपके विभाग के नियम/क़ानून/आदेश/दिशानिर्देश के मुताबिक़ ऐसे मामलों का निपटारा कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए. उस नियम/क़ानून/आदेश/दिशानिर्देश की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं.

5. यदि अधिकारियों/कर्मचारियों ने मेरे आवेदन का निपटारा उक्त नियम/क़ानून/आदेश/दिशानिर्देश के तहत नियत समय के भीतर नहीं किया है, तो क्या ये अधिकारी/कर्मचारी उक्त नियम/क़ानून/आदेश/दिशानिर्देश के न माने जाने के लिए दोषी हैं?

6. इन अधिकारियों/कर्मचारियों के रवैये की वजह से मुझे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी मेरे मानसिक शोषण के लिए दोषी हैं?

7. इन अधिकारियों/कर्मचारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने उक्त सभी नियम/क़ानून/आदेश/दिशानिर्देश का उल्लंघन किया है और जिसकी वजह से मुझे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. कब तक इन अधिकारियों/कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी?

मेरे आवेदन का निपटारा कब तक हो जाएगा?

मै इस आवेदन के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम-

हस्ताक्षर
पता-

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह धन लाभ और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे. दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा और पारिवारिक मांगलिक कार्य भी संभव है. नया वाहन ख़रीदने की योजना बनेगी. स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव भी महसूस होगा. पूर्व लंबित कार्य में सफलता थोड़े संघर्ष के बाद मिलेगी. व्यर्थ के भ्रमण से बचें.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

बिगड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक सुख में भी बढ़ोत्तरी होगी. किसी मांगलिक कार्य में ख़र्च की संभावना है. कार्य स्थल पर तनाव की अनुभूति होगी, लेकिन आप संयम बनाए रखें. समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें. किसी बुज़ुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी.

मिथुन 21 मई से 20 जून

आप मिश्रित फल का अनुभव करेंगे. आपके वाहन में कुछ ख़र्च के संकेत हैं. विद्यार्थी वर्ग को मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी. आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपके नए मित्र बनेंगे और आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन दोनों के अच्छे संकेत हैं.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

आपकी भागदौड़ और अपव्यय दोनों के बढ़ने के योग हैं. ख़र्च बढ़ने के कारण थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा और आप असुरक्षित महसूस करेंगे. व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे. आप बनते कार्यों में बाधा का अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. अपने अंदर आलसी प्रवृत्ति न आने दें.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

आपकी धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. सामाजिक और पारिवारिक रूप से मज़बूती भी आएगी. पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई नया विवाद भी दिखेगा. आप पारिवारिक सदस्यों को उचित समय देंगे. आप धन कमाने से संबंधित कोई जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से बचें. व्यवसायी अपने साझेदार पर कड़ी नज़र रखें.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों अपने कार्यस्थल पर ग़ुस्से वाली प्रवृत्ति से बचें. सफलता के लिए आपको संघर्ष करना होगा और आपको शक्ति अपने अंदर से ही मिलेगी. वित्तीय और पारिवारिक रूप से समय मज़बूत रहेगा. सामाजिक रूप से आप बहुत सारे नए कार्यों में संलग्न रहेंगे. माता-पिता का भरपूर प्रेम मिलेगा.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

आपकी व्यक्तिगत छवि अच्छी होगी. यह समय व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने का है और आप इसमें सफल भी होंगे. व्यापारी और नौकरीपेशा लोग भी आमतौर पर ख़ुश रहेंगे. इस सप्ताह आप परिवार के अंदर अपने अड़ियल स्वभाव को बदलें. धार्मिक या दार्शनिक स्थलों की यात्रा संभव है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

आप थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस कर सकते हैं. आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होगा. आत्मनियंत्रण की ज़रूरत है. पारिवारिक यात्रा संभव है. भाई-बहनों के साथ संबंध में तनाव महसूस कर सकते हैं. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों वर्ग थोड़ा आर्थिक तनाव महसूस करेंगे.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

आप धैर्य बनाए रखें. कार्य की शुरुआत में थोड़ी परेशानी रह सकती है, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलकर रहेगी. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. रोज़गार की तलाश में लगे लोगों को ख़ुशख़बरी मिलेगी. आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक़ धन संचय में भी सफल रहेंगे. व्यवसायी अच्छा व्यवसाय करेंगे.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल और महत्वपूर्ण रहेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. पारिवारिक सुख के लिए यह अच्छा समय रहेगा और हर्ष का वातावरण रहेगा. अचानक यात्रा का योग है और इससे आपको लाभ होगा. किसी के साथ पैसे इंवेस्ट करने से बचें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा आगे तकलीफ़ होगी.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

आप अपने गूढ़ चिंतन को किसी के साथ शेयर न करें. राजनीतिक लोगों से आपको फ़ायदा पहुंचेगा. थोड़ा भ्रमण बढ़ेगा, लेकिन अपने वाहन को थोड़ी सावधानी से चलाएं. मसालेदार खाना खाने से बचें. किसी के ऊपर भरोसा करके कोई बड़ा निर्णय न लें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों मेहनत ज़्यादा करेंगे.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

आप अपने नियमित कार्य को सुचारू रूप से निपटाएंगे और ख़ुश रहेंगे. अपनी ज़िंदगी, घर और गाड़ी में नयापन लाने में आपका ध्यान लगा रहेगा. आपके साथ कार्य करने वाले लोगों से आपके संबंध और मज़बूत होंगे. ज़िंदगी के आदर्श और दर्शन पर आधारित बातें दिमाग़ में ज़्यादा आएंगी.

cshekhar_3@hotmail.com

ज़रा हट के

प्यार से बंधा एक परिवार

आज है कि कोई भी संयुक्त परिवार में रह नहीं पाता, क्योंकि आए दिन छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं. आजकल भाई ही अपने भाई की हत्या करने में लगा रहता है, ऐसे में एक साथ छत के नीचे रहना. तो बहुत दूर की बात है. कोई घर तब तक ही घर रहता है, जब तक उग नहीं आते उसी में से और कई छोटे-छोटे घर. दरअसल, चामुंडा मंदिर के नज़दीक तंगरोटी गांव में एक घर ऐसा भी है, जो अब तक घर है, क्योंकि उसमें भरा-पूरा परिवार है. इस वातावरण में जब हर व्यक्ति एक घर बनाने को आतुर है, तो ऐसे में तंगरोटी के परसराम का परिवार शाम को एक-साथ एक ही छत के नीचे सामूहिक रूप से भोजन करता है. सुबह की पहली किरण के साथ इस परिवार का हर सदस्य अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है. सुबह से शाम

तक इस परिवार में शायद ही आठ या दस सदस्य नज़र आए, लेकिन शाम के 9 बजे खाने के दौरान परिवार के 34 सदस्य जब एक साथ खाना खाते हैं तो एक उत्सव सा माहौल बन जाता है. यह संयुक्त परिवार टूटते परिवारों के लिए एक मिसाल है. इस परिवार ने ग़रीबी भी देखी, लेकिन फिर भी यह परिवार एकजुट रहा. हां, परिवार के सदस्यों की संख्या धीरे-धीरे ज़रूर बढ़ती गई, लेकिन विचार नहीं बदले और न रिश्तों की डोरी ही कमज़ोर पड़ी. दरअसल, आज भी परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन सभी करते हैं. यही वजह है कि कभी रेत बजरी उठाकर दो वक्त की रोटी की जुगाड़ करने वाला यह परिवार अब ट्रांसपोर्टर भी है. उनके पास तीन बसें, एक ट्रक, एक ट्रैक्टर, एक वैन और कार हैं. परिवार की एकजुटता और कार्यशैली का आलम यह है कि इन सभी कारोबार में अपने ही परिवार के लोग विभिन्न तरह की ज़िम्मेदारी निभा रहे है. कोई गाड़ी चलाता है, तो कोई कंडक्टर है. अपनी खेतीबाड़ी को भी सभी सदस्य संयुक्त रूप से संभालते हैं. सच तो यह है कि जिस रेत बजरी ने उनके घर को समृद्ध बनाया, उस कारोबार को उन्होंने अब भी नहीं छोड़ा है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

सुंदरता के लिए कराई सर्जरी

आजकल लोग सुंदर दिखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, क्योंकि लोगों का मानना है कि सुंदर है, तो सब कुछ है, नहीं, तो कुछ भी नहीं. दरअसल, यह कहानी है जापान की एक मॉडल वैनिला चामू की. सुंदर न होने के कारण बचपन में लोग उन्हें बदसूरत कहकर चिढ़ाया करते थे. इससे इतनी आहत हुईं कि उन्होंने फ्रांस की एक मशहूर गुड़िया की तरह बनने और दिखने की ठान ली. इसे भले ही कुछ लोग सनक कहें, लेकिन इस मॉडल ने गुड़िया का लुक पाने के लिए लाखों रुपये स्वाहा कर दिए.

उन्होंने अपनी पहली सर्जरी 19 साल की आयु में करवाई थी. उसके बाद से अब तक वह लगातार विभिन्न अंगों की 30 सर्जरी करा चुकी हैं. इन सब चिकित्सकीय प्रक्रियाओं में वे अब तक पचास लाख से अधिक रुपये बर्बाद भी कर चुकी हैं, लेकिन इतने पर भी वे थमना नहीं चाहती हैं. उनका कहना है कि अगर इसके बाद भी उनका लुक उस फ्रेंच डॉल की तरह नहीं दिखता है, तो वह तब तक सर्जरी कराती रहेंगी, जब तक वैसा नयन-नक्श न बन जाए. ■

कपड़े धोने की टेंशन को बाय-बाय

इन दिनों ज़्यादातर लोग बहुत व्यस्त हैं, इसीलिए अपने निजी कामों के लिए भी समय निकालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है. लेकिन निकालना तो पड़ता ही है. सबसे ज़्यादा समय निकालना पड़ता है कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए. लेकिन जल्द ही इन समस्याओं

से छुटकारा पाया जा सकता है. दरअसल, अमेरिका की एक कंपनी ने एक ऐसी शर्ट बनाने का दावा किया है, जिसे सौ दिन तक बिना धुले और प्रेस किए पहना जा सकता है. इसे बनाने में ऊन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं. कुछ खास विधि से तैयार होने के कारण बार-बार पहनने पर भी इसमें बदबू नहीं आती. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि हम आज के जमाने की वार्डरोब के लिए एक कंप्लीट शर्ट बनाना चाहते थे और इसके लिए हमने ऑक्सफोर्ड सॉलिड ब्लू फैब्रिक तैयार भी किया है. यह शर्ट नीले रंग के चेक पैटर्न में उपलब्ध है. अमेरिकी कंपनी वूल ऐंड प्रिंस का दावा है कि इस शर्ट को कभी भी पहना जा सकता है. कंपनी ने प्रचार के लिए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मालिक मैक बिशप सौ दिन से यही शर्ट पहने हुए हैं. इस खास शर्ट की क़ीमत 98 डॉलर (5262 रुपये) है.■

भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश ज़रूर हैं, लेकिन दोनों देशों के शासन का तरीक़ा अलग है. भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था है.

क्या चीन पर विश्वास करना चाहिए?

जिस तरह चीनी सैनिक भारतीय सीमा का अतिक्रमण करते हैं और चीन भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसे देखते हुए चीन पर विश्वास करना आसान नहीं है. इसलिए चीन को भारत का विश्वास हासिल करने के लिए कुछ न कुछ करके दिखाना होगा. सवाल यह भी है कि चीन किसी भी तरह भारत से व्यापारिक संबंध बहाल रखना और इसे बढ़ाना क्यों चाहता है?

राजीव कुमार
rajiv@chauthiduniya.com

विवादों के बीच चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने भारत की यात्रा की. प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी. मार्च में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत भारत आने की योजना बना ली थी और समय भी सुनिश्चित कर लिया था, लेकिन इसके बाद अप्रैल में चीनी सैनिकों ने लद्दाख़ में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया. उस समय ऐसा लगा कि चीन और भारत के बीच संबंधों में खटास बढ़ जाएगी, लेकिन चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बयानों, बातचीत, वादों और समझौतों से तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल महीने की सीमा संबंधी विवाद का कोई विशेष प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा. क्या सही मायने में दोनों देश एक दूसरे के क़रीब आ रहे हैं? क्या दोनों के बीच विवाद का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है या कुछ दूसरे विषय भी हैं, जो दोनों को क़रीब नहीं आने देते हैं?

भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश ज़रूर हैं, लेकिन दोनों देशों के शासन का तरीक़ा अलग है. भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था है, जिसे वह ठोस लोकतंत्र कहता है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोकतंत्र से यह कोसों दूर है. ज़ाहिर है कि शासन के तरीक़े अलग होने का प्रभाव उनकी नीतियों के निर्माण में पड़ता है. चीन आक्रामक राष्ट्र है, जबकि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है. चीन आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में समय-समय पर अपनी आक्रामकता का परिचय देता रहता है, जबकि भारत अपने सॉफ्ट स्टेट की छवि से बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं करता है. दोनों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक भिन्नता के बावजूद दोनों की नीतियों में एक नीति ऐसी है, जिसे समान कहा जा सकता है, यानी दोनों देश एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं. दोनों के पास एशिया ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ताक़त है. दरअसल, यही दोनों के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि दोनों साझा तौर पर एशियाई ताक़त बनना नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे से कुछ क़दम आगे बढ़ना चाहते हैं. चूंकि चीन की प्रवृत्ति आक्रामक है, इसलिए वह आक्रामक रुख़ अपनाता रहा है, जबकि भारत अपनी छवि के अनुरूप थोड़ा नरम रुख़ अपनाता रहा है. दोनों के बीच प्रतिस्पर्द्धा और रिश्तों में कड़वाहट को समझने के लिए इतिहास में जाना ज़रूरी है. भारत को 1947 में आज़ादी मिली और चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और एक तरह से नए चीन का उदय हुआ. उस समय दोनों के बीच संबंध अच्छे थे, जिसका कारण शायद चीनी नेताओं की भारत के प्रति सोच रही होगी. चीन को ऐसा लगा होगा कि भारत से उसकी कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है और दूसरे पड़ोसी देशों की तरह वह भारत को भी अपने इशारों पर नचाता रहेगा.

ग़ौरतलब है कि नेहरू ने साम्यवादी चीन को मान्यता भी दी थी, जबकि पश्चिमी देश ताईवान को मान्यता दे रहे थे. दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ और हिंदी चीनी भाई-भाई के नारे भी लगे. भारत ने तिब्बत पर चीन के हमले और उसे चीन में शामिल कर लेने को भी मान्यता दे दी. सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने में भी भारत ने चीन का साथ दिया, लेकिन भारत की उदार नीति के कारण चीन को धोखा हो गया. और इसलिए चीन ने भारत के बारे में ग़लत अनुमान लगाया. दरअसल, चीन को इस बात की जानकारी तब हुई, जब विकासशील देशों ने चीन से ज़्यादा भरोसा भारत में जताना शुरू कर दिया. साठ के दशक में भारत न तो कोई बड़ी आर्थिक शक्ति था और न ही सैन्य शक्ति, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर इसकी अहमियत चीन से बड़ी थी. गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुआ भारत वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा था. स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा हो या फिर कोरियाई संकट का, सभी में भारत की भूमिका की सराहना की गई. एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों का झुकाव भारत की ओर ज़्यादा था. इससे चीन नींद से जाग गया, क्योंकि अब दौर साम्राज्यवाद का नहीं, बल्कि आपसी संबंधों का था, जिसका इस्तेमाल वाणिज्य-व्यापार बढ़ाने और इन नवस्वतंत्र देशों के संसाधनों का इस्तेमाल कर अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताक़त बढ़ाना था. चीन को भारत की बढ़ती लोकप्रियता सहन नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वह चुप था, क्योंकि भारत ने प्रत्यक्ष तौर पर चीन को चुनौती नहीं दी थी. जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो चीन को लगा कि अब भारत ने उसे चुनौती दी है. दलाई लामा को भारत में शरण देने से चीन की संप्रभुता को कोई ख़तरा नहीं होने वाला था, क्योंकि वह जानता था कि भारत पहुंचने पर अगर दलाई लामा को वह शरण नहीं भी देता है, तो किसी न किसी पश्चिमी देश में दलाई को शरण मिल जाती और यह चीन के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होता. लेकिन यह इस बात का संकेत था कि भारत चीन को चुनौती दे सकता है. चीन पहले से ही भारत को सीमित करने की कोशिश में था और दलाई लामा को शरण देने के बाद उसे भारत की कमज़ोरी को उजागर करना था, ताकि भारत पर भरोसा करने वाले दूसरे देशों को यह पता चल सके कि एशिया में भारत नहीं, बल्कि चीन का वर्चस्व है. यही कारण है कि उसने भारत पर 1962 में आक्रमण किया और एक तरफ़ा युद्ध विराम की घोषणा करके बाहर चला गया. वह चाहता, तो पराजित भारत के साथ समझौता कर सकता था और दलाई लामा को चीन को सौंपने या भारत से बाहर करने के लिए विवश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. यह केवल भारत की छवि कमज़ोर करने की क़वायद थी. यहीं से दोनों देशों के बीच संबंध ख़राब हुए.

यहां यह बताना ज़रूरी है कि वर्तमान समय में भी दोनों के बीच संबंधों में कड़वाहट का कारण प्रतिस्पर्द्धा ही है. सीमा विवाद का समाधान अगर नहीं भी होता है, तो वर्तमान स्थिति को बदलना लगभग असंभव है. अभी चीनी सैनिकों द्वारा लद्दाख़ में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया गया. चीनी सैनिकों ने अस्थाई टेंट भी लगा लिए थे, लेकिन अंततः पूर्व स्थिति बहाल हो ही गई. दोनों के बीच युद्ध होने का मतलब विनाश है, जो दोनों राष्ट्र नहीं चाहेंगे. दोनों परमाणु हथियारों वाले देश हैं, सैन्य मामले में भी उन्नीस-बीस का अंतर हो सकता है, इसलिए सीमा विवाद को जितना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, उतना महत्वपूर्ण वास्तविकता में यह है नहीं. हालांकि इसे दोनों देशों के बीच संबंध ख़राब होने का एक कारण माना जा सकता है. इससे बड़ा मुद्दा है नदी जल विवाद का. चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाए हैं, जिनका इस्तेमाल वह भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को तबाह करने के लिए कर सकता है. बाढ़ और सूखा दोनों स्थितियां पैदा करने के लिए चीन इसका इस्तेमाल कर सकता है. इसी तरह दोनों के बीच आर्थिक मुद्दों पर भी कई विवाद हैं. वैश्विक व्यापार में दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी हैं. हालांकि अगर प्रतिस्पर्द्धा सकारात्मक हो, तो इससे कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन यह प्रतिस्पर्द्धा नकारात्मक है. अफ्रीका हो या फिर एशियाई देश, हर जगह चीन और भारत एक दूसरे के आमने-सामने दिखाई पड़ते हैं. दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति का चीन ने प्रखर विरोध किया था. हालांकि भारत ने अपनी नीति नहीं बदली और चीन भी कोई कड़ा क़दम नहीं उठा सका, लेकिन संबंधों में कड़वाहट आना तो लाज़िमी ही है.

भारत और चीन के बीच संबंधों में दरार का एक अन्य कारण चीन का भारत विरोधी देशों को समर्थन देना और भारत को घेरने की नीति अपनाना भी है. यह जानते हुए कि पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है. उसने 1965 में हुए भारत-पाक युद्ध में भी पाकिस्तान का पक्ष लिया और भारतीय नीति की ही आलोचना की. चीन के हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता रहा है. पाकिस्तान के आतंकवाद, जो कि भारत के लिए इस्तेमाल होता है, का खुलकर विरोध चीन नहीं करता है. पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कुछ संगठनों के चीन के साथ किसी न किसी तरह के संबंध होने के सबूत हैं. भारत में नक्सलवाद, जो कि अब माओवाद के नाम से जाना जाता है, चीनी नेता माओ से प्रभावित है और हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल है. चीन को चाहिए कि इस संगठन के ख़िलाफ़ बोले तथा उसे अपने यहां से किसी भी तरह के समर्थन को प्रतिबंधित करे. इसके अलावा, चीन की एक नीति भारत के पड़ोसी देशों के साथ गठजोड़ की भी रही है. चीन ने म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों के साथ कई समझौते किए हैं. हालांकि ऐसी नीति सभी देश अपनाते हैं, लेकिन जिस देश के हितों को इससे नुक़सान होने वाला है, उसके साथ विश्वास बहाली ज़रूरी होती है. लेकिन चीन विश्वास बहाली के बदले विश्वास को नुक़सान पहुंचाने वाला काम करता है. जिस देश के साथ उसका संबंध सुधरता है, वहां भारत का विरोध शुरू हो जाता है. नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के आने के बाद भारत का विरोध शुरू हो गया था, जबकि चीन का समर्थन बढ़ने लगा था. ऐसी स्थिति में भारत किस आधार पर चीन को अपना हितैषी राष्ट्र मान सकता है? अगर चीन एक सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा करता, तो भारत को कोई नुक़सान नहीं था, लेकिन वह नकारात्मक रवैया ही अपनाता है, जो कि भारत के हितों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है.

अब सवाल यह उठता है कि इतने विवादों के बावजूद चीन किसी भी तरह भारत से व्यापारिक संबंध बहाल रखना और इसे बढ़ाना क्यों चाहता है? चीन और भारत ने 2015 तक आपसी व्यापार 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है कि चीन और भारत के बीच व्यापार चीन के पक्ष में है. चीन के ही सीमा शुल्क विभाग के एक आंकड़े के अनुसार, 2012 में भारत के साथ चीन का व्यापार आधिक्य 28.87 अरब डॉलर का रहा है, जबकि 2007 में यह 9.38 अरब डॉलर था. इसका मतलब यही है कि दोनों देशों के बीच का व्यापार जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत का चीन के संदर्भ में व्यापारिक घाटा भी उसी तेज़ी से बढ़ रहा है. ऐसे में चीन भारत के साथ व्यापारिक संबंध कमज़ोर करना क्यों चाहेगा, जिससे उसे आर्थिक लाभ होता है. यही कारण है कि चीन अन्य विवादों को परे रखकर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता बनाने की बात करता है.

अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या चीन के प्रधानमंत्री के बयानों और वादों से दोनों के बीच संबंध सुधर जाएंगे? ली केकियांग ने कहा है कि अगर दोनों देश एक सुर में बोलेंगे, तो पूरी दुनिया को उनकी बात सुननी पड़ेगी. इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों महाशक्ति अगर एक मंच पर आ जाएं, तो पूरी दुनिया को इनकी बात सुननी होगी, लेकिन संदेह इस बात का है कि दोनों एक सुर में बोलेंगे क्यों और कैसे, क्योंकि दोनों के हित परस्पर टकराते हैं. चीन चाहे, तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि इस आतंकवाद का सीधा संबंध भारतीय हितों से है और वह भारत को परोक्ष तौर पर भी लाभ नहीं पहुंचाना चाहता, यह तो प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की बात होगी. जब तक चीन अपनी भारत विरोधी नीति नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान के ग़लत कामों का समर्थन करना नहीं छोड़ेगा, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों की आलोचना नहीं करेगा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का सहयोग नहीं करेगा, तब तक भारत किस तरह से चीन पर विश्वास कर सकता है? चूंकि दोनों के बीच संबंध ख़राब करने के लिए चीन ज़िम्मेदार है, इसलिए संबंध सुधारने की कोशिश करना भी उसी का दायित्व है.

भारत को यह दिखना चाहिए कि सचमुच चीन उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है. केवल वादों से तो चीन भारत का विश्वास जीत नहीं सकता, इसके लिए उसे कुछ उदाहरण पेश करने होंगे. चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की पहली विदेश यात्रा भारत की रही है, यह एक क़दम है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए जब तक चीन ठोस क़दम नहीं उठाता, तब तक इस संबंध को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. भारत ने चीन से धोखा खाया है और इस धोखे की क्षतिपूर्ति के लिए चीन को भारतीय हितों को नुक़सान पहुंचाने वाले तत्वों का समर्थन करना बंद करना होगा, ताकि भारत भी इतिहास के धोखे को भूलकर आगे संबंध मज़बूत करने के बारे में सोचे, नहीं तो ऊपरी तौर पर दोनों के बीच सुधरते संबंध अंदर से खोखले ही रहेंगे. ■

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए. एक दिन बाबा ने राधाकृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा.

बाबा का उपदेश और आचरण

साई बाबा ने हमेशा लोगों को अच्छा आचरण करने की शिक्षा दी. साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए. आइए जानते हैं कि किस तरह देते थे बाबा उपदेश?

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न करके बाबा यथायोग्य समय पर स्वतंत्रतापूर्वक उपदेश दिया करते थे. एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे. गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के प्रति दोषारोपण में इतने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी. बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करके विवाद उत्पन्न करते हैं. संत तो परदोषों को दूसरी दृष्टि से देखा करते हैं. उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भिन्न होती है. वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिव्हा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार देखा जाए तो, वे दूसरों की निंदा करके उनका उपकार ही करते हैं, जिसके लिए दरअसल, वे धन्यवाद के पात्र हैं. निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साई बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न थी. वह तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को समझ गए. जब लेंडी के समीप उस भक्त से भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो, वह कितने प्रेमपूर्वक विष्ठा खा रहा है. तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है. अनेक शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया, तो शिरडी तुम्हारी क्या सहायता कर सकेगी. कहने का तात्पर्य केवल यही है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया. इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वह उपदेश दिया करते थे. यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए, तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर नहीं होगा.

एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्रीहरि होगा, तो वह मुझे चारपाई पर बैठे-बैठे ही भोजन पहुंचाएगा. यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस बात पर विश्वास कर आलस्य वश बैठा रहे, तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकेगा, उलटे पतन के घोर अंधकार में गुम हो जाएगा. इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए सबको अनवरत परिश्रम करना चाहिए. बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. केवल उनके भ्रम निवारणार्थ, जिनकी दृष्टि में वह साढ़े तीन हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए. इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और उन्होंने दिन-रात उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई, जिस प्रकार माधुर्य एवं मिश्री, लहर एवं समुद्र और नेत्र एवं कांति में अभिन्नता हुआ करती है. जो लोग आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें. दुखदायी-कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखी न करके सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भयरहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए. जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी. उन्होंने अनेक लोगों से नाम का जापकर के अपनी शरण में आने को कहा. जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूं, बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण-मनन करने का परामर्श दिया. किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण, ज्ञानेश्वरी एवं धार्मिक ग्रंथों का पठन-अध्ययन करने को कहा. कई लोगों को उन्होंने अपने चरणों के समीप रखा, बहुतों को खंडोबा मंदिर भेजा और कई लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का जाप और छांदोग्य उपनिषद एवं गीता का अध्ययन करने को कहा. उनके उपदेशों की कोई सीमा नहीं थी. उन्होंने किसी को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए. एक बार वह एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रगट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई, तभी उसे छोड़ा. किसी-किसी को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया और कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठकर धैर्य रखने को कहा. उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन असंभव है.

साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए. एक दिन बाबा ने राधाकृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा. एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके कहे अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगाया. वह उनके घर पर चढ़ गए और राधाकृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए. इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया. राधाकृष्ण माई उस समय ज्वर से कांप रही थीं. इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया हो. नीचे उतरने के बाद शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को दो रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए. तब एक ने साहस करके उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है. उन्होंने कहा कि बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए किसी से कार्य नहीं कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उदार हृदय से मज़दूरी देनी चाहिए. यदि बाबा के इस नियम का पालन किया जाए, यानी मज़दूरी का भुगतान शीघ्र और संतोषप्रद हो, तो मज़दूर अधिक उत्तम कार्य करेंगे और लगन से कार्य करेंगे. फिर कार्य छोड़ने एवं हड़ताल जैसी कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी और न मालिक और मज़दूरों के बीच वैमनस्य पैदा होगा.■

प्रसिद्ध मंदिर

सागर किनारे महाबलिपुरम पुकारे

दक्षिण भारत में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं. इन्हीं में से एक है महाबलिपुरम. महाबलिपुरम का धार्मिक महत्व तो है ही, इसके अलावा पर्यटन के लिहाज़ से भी यह मशहूर है. महाबलिपुरम का नाम कैसे पड़ा, जानने के लिए पढ़िए यह लेख.

सोनिका गुप्ता feedback@chauthiduniya.com

महाबलिपुरम मंदिर वास्तव में तमिलनाडु के दक्षिणी राज्य के अंदर बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है. यह मंदिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 45 किलोमीटर की दूरी पर है. बंगाल की खाड़ी के सागर की लहरें 1400 वर्ष पूर्व बनाए गए महा आकर्षक मंदिरों के जिस समूह से टकराती हैं, उन्हें महाबलिपुरम के नाम से जाना जाता है. मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती हैं. प्रारंभ में इस शहर को मामल्लापुरम कहा जाता था. प्राचीन चट्टानों तथा विशाल शिलाओं को काट कर बनाए गए इन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत के प्रसिद्ध प्राचीन पल्लव राजवंश के शासनकाल में शुरू हुआ तथा राजा महेंद्रवर्मन द्वारा इनका प्रमुख भाग निर्मित करवाया गया.

तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर-तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है. सातवीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था. द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है. यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है. यहां के तीन मंदिर प्रसिद्ध हैं. बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके दोनों तरफ़ शिव मंदिर हैं. यहां पर निर्मित पल्लव मंदिरों और स्मारकों के मिलने वाले अवशेषों में चट्टानों से निर्मित अर्जुन की तपस्या, गंगावतरण जैसी मूर्तियों से युक्त गुफ़ा मंदिर और समुद्र तट पर बना शैव मंदिर प्रमुख हैं. ये सभी मंदिर भारत के प्राचीन वास्तुशिल्प के गौरवमय उदाहरण माने जाते हैं. पल्लवों के समय वृहत्तर भारत, विशेष कर स्याम, कम्बोडिया, मलाया और इंडोनेशिया में दक्षिण भारत से बहुसंख्यक लोग जाकर बसे थे और वहां पहुंच कर उन्होंने नए-नए भारतीय उपनिवेशों की स्थापना भी की थी. महाबलिपुरम के निकट एक पहाड़ी पर स्थित दीपस्तंभ समुद्र यात्राओं की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था. इसके निकट ही सप्तरथों के परम विशाल मंदिर विदेश यात्राओं पर जाने वाले यात्रियों को मातृभूमि का अंतिम संदेश देते रहे होंगे. इस नगर के पांच रथ या एकाश्म मंदिर, उन सात मंदिरों के अवशेष हैं, जिनके कारण इस नगर को सप्तपगोडा भी कहा जाता है.

इन मंदिरों का संबंध पांडवों से भी जोड़ा जाता है. हालांकि पांडवों के दक्षिण भारत जाने के प्रमाण बहुत कम हैं, परंतु यहां के रथों में से दो रथों का नाम राजा पांडु पुत्र नकुल तथा सहदेव के नाम पर है. मध्ययुग में जब यूरोपियन लोग यहां पहुंचे, तो इन मंदिरों का आकर्षण देखकर उनकी हैरानी की सीमा न रही. इन मंदिर समूहों का कुछ भाग सागर से सटकर अभी भी सुरक्षित खड़ा है, परंतु इनमें से काफ़ी मंदिर समुद्र में डूब गए हैं. स्थानीय मान्यतानुसार इन मंदिरों की सुंदरता से ईर्ष्या के चलते इंद्र ने यहां के मंदिरों का बाक़ी भाग समुद्र में डुबो दिया. पौराणिक मान्यतानुसार यह स्थान महातपस्वी राक्षस हिरण्यकश्यप के साम्राज्य की राजधानी थी, जो उसके पोते तथा भक्तराज प्रह्लाद के पुत्र राजा बलि को विरासत में प्राप्त हुआ था. राजा बलि अपने बल, तप, तेज तथा वैभव से अधिक अपनी दानवीरता के लिए माने जाते थे. एक बार उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण के रूप में उनसे मात्र तीन क़दम भूमि दान में मांगी, परंतु जब ब्राह्मण रूपी उस वामन अवतार द्वारा मात्र अढ़ाई क़दमों में सारी धरती को माप लिया गया, तो महादानी राजा बलि ने उनके पांव रखने के लिए अपना सिर ही आगे कर दिया.कहा जाता है कि प्रभु के वामनावतार के पांव का वेग व भार इतना था कि उससे राजा बलि अपने राज्य के उस भू-भाग सहित धरती के नीचे धंस कर पाताल में जा पहुंचा और इसी कारण आज तक पाताल लोक में राजा बलि का राज है और इसी वेग में अन्य मंदिर डूब गए. समुद्र में डूबे कुछ मंदिर इतने आकर्षक हैं कि इन्हें देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं.

यहां पर राजा स्ट्रीट के पूर्व में स्थित इस संग्रहालय में स्थानीय कलाकारों की 3000 से अधिक मूर्तियां देखी जा सकती हैं. संग्रहालय में रखी मूर्तियां पीतल, रोड़ी, लकड़ी और सीमेंट की बनी हुई हैं. यहां पर एक कृष्ण मंडप है. यह मंदिर महाबलिपुरम के प्रारंभिक पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिरों में से एक है. मंदिर की दीवारों पर ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिलती है. एक चित्र में भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए दिखाया गया है. यहां पर महाभारत के पांच पांडवों के नाम पर इन रथों को पांडव रथ कहा जाता है. पांच में से चार रथों को एकल चट्टान पर उकेरा गया है. द्रौपदी और अजरुन रथ वर्ग के आकार का है. एक भीम रथ है. धर्मराज रथ सबसे ऊंचा है. महाबलिपुरम से 21 किलोमीटर की दूरी पर मुट्टुकाडु नामक एक स्थान है, जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है. यहां नौकायन, केनोइंग, कायकिंग और विंडसर्फ़िंग जैसी जलक्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है. यहां से 19 किलोमीटर की दूरी पर कोवलोंग नामक एक स्थान है, जहां पर एक बहुत ख़ूबसूरत बीच रिजॉर्ट है. इस शांत फिशिंग विलेज में एक किले के अवशेष देखे जा सकते हैं. यहां तैराकी, वाटर स्पोर्ट्स की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं. यहां से 14 किलोमीटर की दूरी पर क्रोकोडाइल बैंक है. इसे 1976 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने स्थापित किया था. इसकी स्थापना के लगभग 15 वर्ष बाद यहां मगरमच्छों की संख्या 15 से 5000 तक पहुंच गई थी.

महाबलिपुरम का नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है. यह नृत्य पर्व सामान्यत: जनवरी या फरवरी माह में आयोजित किया जाता है. भारत के जाने माने नृत्यकार शोर मंदिर के निकट अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. पर्व में बजने वाले वाद्ययंत्रों का संगीत और सागर की लहरों का प्राकृतिक संगीत की एक अनोखी आभा भी देखने को मिलती है.

यहां की नक्काशी बहुत ही प्रसिद्ध है. महाबलिपुरम में एक महाविद्यालय है, जहां विद्यार्थियों को स्थापत्य और मंदिर वास्तुकला की शिक्षा भी दी जाती है.

महाबलिपुरम पहुंचना आसान है. यहां हवाई जहाज़ से आसानी से आया जा सकता है. यहां भारत के सभी प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट्स हैं. यहां से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है. यहां से रेल स्टेशन 29 किलोमीटर की दूरी पर है. चेन्नालपट्टू महाबलिपुरम सबसे निकटतम स्टेशन है. महाबलिपुरम तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है. राज्य परिवहन निगम की नियमित बसें अनेक शहरों से महाबलिपुरम के लिए आसानी से मिल जाती हैं. ■

आस्था

नास्तिक लगती ज़रूर हूं, पर हूं पक्की आस्तिक : मौली गांगुली

मौली गांगुली टीवी की जानी मानी ऐक्ट्रेस हैं. उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा, कहीं किसी रोज़, रेशम डंक और कुटुंब जैसे धारावाहिकों में दमदार अभिनय किया है. हालांकि मौली अब दांपत्य सूत्र में बंध गई हैं, लेकिन भगवान में उनकी कितनी आस्था है, बता रही हैं अमित कुमार को...

क्या भगवान में आपकी आस्था है?

भगवान में मेरी बेहद आस्था है. यह ईश्वर की कृपा थी कि मुझे उस दौरान बेहतर किरदार नहीं मिल रहे थे, जबकि मैं टाइप्ड रोल्स करने के पक्ष में नहीं थी. ऐसे में मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक लेना मुनासिब समझा. लेकिन मुझे क्या पता कि ईश्वर ने मेरे बारे में कुछ और ही सोच रखा था. यही वजह रही कि इस ब्रेक के दौरान ही मुझे मनपसंद हमसफ़र मिल गया और मैं शादी के बंधन में बंध गई. अगर काम कर रही होती, तो शादी के लिए अलग से ब्रेक लेना पड़ता और हम दोनों एक-दूसरे को पर्याप्त वक़्त नहीं दे पाते!

क़िस्मत को आप कितना मानती हैं?

मैंने ऋतुपर्णो घोष की बांग्ला फिल्म रेनकोट में काम किया है. ऐक्टिंग की दुनिया में आने के बारे में कभी नहीं सोचा था. अब इस फील्ड में हूं, तो यह ईश्वर की इच्छा ही है. मैं कोलकाता से मुंबई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के इरादे से आई थी. लेकिन होटल मैनेजमेंट का कोर्स बीच में इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. शायद यही ईश्वर की इच्छा थी, क्योंकि मेरे मन में कुछ क्रिएटिव करने की उमंगें हिलोरे मारने लगी थीं. मेरे कुछ दोस्त थे, जो ऐड एजेंसियों में काम करते थे. उनकी वजह से मैंने कुछ विज्ञापनों के लिए ऑडिशन दिया. मेरे लिए विज्ञापनों की दुनिया में आना बहुत मुश्किल नहीं रहा. दरअसल, एडवर्टाइजर्स नए चेहरे की तलाश करते रहते हैं और शायद मैंने उनकी जेब का भी ख्याल रखा. मुझे इस तरह ऐड के ऑफर्स मिलते रहे. धीरे-धीरे टीवी की दुनिया में भी इसी तरह एंट्री मिल गई. कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐक्टिंग की दुनिया में क़दम रखने से पहले ईश्वर ने हाथ पकड़कर मुझे अलग-अलग चीज़ों का अनुभव दिलाया, ताकि मुझे यहां नाकामी न झेलनी पड़े. इसके लिए मैं ईश्वर की शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मेरे लिए एक कामयाब करियर का चुनाव किया.

आप ईश्वर को किस रूप में मानती हैं?

मैं मूर्ति पूजा में यक़ीन नहीं करती. ईश्वर के किसी ख़ास रूप में यक़ीन नहीं करती. मेरे लिए हर वस्तु में भगवान हैं और हर वस्तु भगवान का ही रूप है. यही वजह है कि मैंने पूजा-पाठ के लिए किसी ख़ास दिन का चुनाव नहीं किया है. मैं व्रत-उपवास भी नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना यही है कि ख़ुद को प्रताड़ित करके आप ईश्वर को ख़ुश नहीं कर सकते. ईश्वर ने आपको इस संसार में ख़ुश रहने के लिए भेजा है, क्योंकि अपने बच्चों की ख़ुशियों में ही माता-पिता की ख़ुशी निहित होती है. मैं चालीसा पाठ वग़ैरह में भी यक़ीन नहीं करती, बल्कि ईश्वर को सुबह-सवेरे धन्यवाद देती हूं. मैं ईमानदारी, सच्चाई और नीयत को मानती हूं, क्योंकि ये सभी भाव ईश्वर की कृपा से ही संचालित

एवं संचारित होते हैं. इन भावों को आत्मसात करने के लिए मैं ध्यान का सहारा लेती हूं, क्योंकि इससे न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि उसके बाद आप जो भी काम करते हैं, उसमें परफेक्शन भी होता है. दरअसल, यह परफेक्शन ईश्वर की कृपा से ही आता है. यही वजह है कि मैं आंख मूंदकर किसी पर यक़ीन नहीं करती, बल्कि इस काम में मैं अपने दिल और दिमाग़ का इस्तेमाल करती हूं. दिल और दिमाग़ जिस चीज़ को ओके कर देते हैं, उसे ही मैं सच मान लेती हूं. कुल मिलाकर, आप कह सकते हैं कि देखने-सुनने में भले ही मैं नास्तिक नज़र आती हूं, लेकिन मैं हूं पक्की आस्तिक, लेकिन थोड़ी अलग तरह की.■

साहित्यकार बिरादरी में प्रतिष्ठा नहीं मिलने के बावजूद गुलज़ार पाठकों और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे.

अनंत विजय

गुलज़ार बेहद लोकप्रिय क्यों?

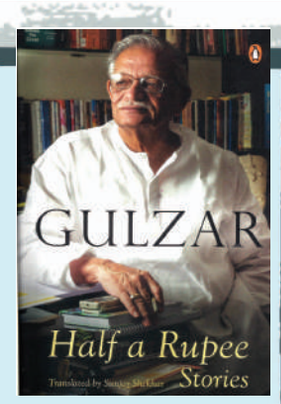

साहित्यकार बिरादरी में प्रतिष्ठा नहीं मिलने के बावजूद गुलज़ार पाठकों और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे. आजकल गुलज़ार जो भी लिखते हैं, उस पर न केवल जमकर चर्चा होती है, बल्कि उसको छापने के लिए प्रकाशकों के बीच होड़ लगी रहती है. क्यों?

गुलज़ार भारतीय सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है, जो पिछले एक दशक में हिंदी–अंग्रेजी प्रकाशकों के बीच भी लोकप्रिय हो गया है. गुलज़ार को लंबे वक्त तक साहित्य की दुनिया में गंभीरता से नहीं लिया गया. दरअसल, उनको फिल्मी लेखक कहकर हाशिए पर रखा जाता रहा. इसमें उस दौर के वामपंथी आलोचकों का बड़ा हाथ रहा है, जो विचारधारा से अलग लेखकों को लेखक मानते ही नहीं थे. साहित्य में न केवल वामपंथी लेखकों का बोलबाला था, बल्कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन के एवज में देश की तमाम साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं पर उनका दबदबा भी था. इसे क़ब्ज़ा भी कह सकते हैं. अपने इस दबदबे का वामपंथी या यूं कह सकते हैं कि मार्क्सवादी साहित्यकारों ने जमकर फ़ायदा उठाया और लेखकों को विचारधारा में शामिल करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. जन और लोक की बात करने वाले इन साहित्यकारों ने लोकप्रियता की एक नई परिभाषा गढ़ी. जनता और पाठकों के बीच लोकप्रियता के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले लेखकों को हल्का और फूहड़ कहकर ख़ारिज करते रहे. साहित्य में उनका मूल्यांकन होने ही नहीं दिया गया. इसका सर्वोत्तम उदाहरण शिवानी की रचनाएं हैं. मानवीयता और घर–परिवार को अपने लेखन का विषय बनाने वाली शिवानी को प्रचुर लेखन और ज़बरदस्त लोकप्रियता के बावजूद वामपंथी साहित्यकारों ने साज़िशन गंभीरता से नहीं लिया. क्या शिवानी की रचनाएं किसी भी तथाकथित विचारधारा के लाल रंग में डूबे उपन्यासकार या कहानीकार की रचनाओं से कम हैं? क्या शिवानी की रचनाओं में मानवीय मूल्यों की कमी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है. आज भी शिवानी के उपन्यास अपनी पठनीयता और विषयवस्तु की वजह से बेहद लोकप्रिय हैं. सालों तक शिवानी के उपन्यास हिंदी के कथित प्रतिष्ठित प्रकाशकों के यहां से नहीं छप सके, इसके पीछे की वजह को जानना भी दिलचस्प होगा. उनकी मृत्यु के चार साल पश्चात दो हज़ार सात के आसपास राजकमल प्रकाशन ने शिवानी की रचनाओं का एक पूरा सेट प्रकाशित किया. यह वामपंथी फ़ासीवाद का एक बेहतरीन नमूना है.

साहित्यकार बिरादरी में प्रतिष्ठा नहीं मिलने के बावजूद गुलज़ार पाठकों और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे. वामपंथ के लगभग पतन के बाद गुलज़ार की न केवल लोकप्रियता में इज़ाफ़ा हुआ, बल्कि लेखक समुदाय के बीच उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ी. आजकल गुलज़ार जो भी लिखते हैं, उस पर न केवल जमकर चर्चा होती है, बल्कि उसको छापने के लिए प्रकाशकों के बीच होड़–सी लगी रहती है. बाज़ार का दबाव या पाठकों का प्यार. पिछले एक दशक में गुलज़ार की लोकप्रियता ने भाषा की सरहद को भी छिन्न–भिन्न कर दिया. पहले उनकी रचनाएं उर्दू और पंजाबी के अलावा हिंदी भाषी लोगों के बीच लोकप्रिय थीं, लेकिन कालांतर में उनकी रचनाएं अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में अनूदित प्रकाशित होने लगीं. अंग्रेजी के प्रकाशकों ने तो गुलज़ार को हाथों–हाथ लिया और सलेक्टेड पोएम्स से लेकर नेगलेक्टेड पोएम्स तक छापा. गुलज़ार के 100 गीतों का संग्रह हंड्रेड लिरिक्स के नाम से भी छपकर बाज़ार में आया. इन किताबों की बिक्री भी ठीक ठाक हुई.

पिछले कई सालों से रवीन्द्र कालिया के संपादन में निकलने वाली साहित्य पत्रिका नया ज्ञानोदय में गुलज़ार एक स्तंभ लिख रहे हैं. कभी उसमें कविताएं होती हैं, कभी संस्मरण और कई बार छोटी कहानी. नया ज्ञानोदय में लिखे गुलज़ार के संस्मरणों और छोटी कहानियों का एक संग्रह अंग्रेजी में अनूदित होकर आया है हाफ अ रुपि. अनुवाद किया है संजय शेखर ने. कवर पर स्टोरीज लिखकर पाठकों को यह बताने की कोशिश की गई है कि यह गुलज़ार की कहानियों का संग्रह है, जबकि यह आंशिक तौर पर ही सही है. इसमें गुलज़ार के लिखे कई संस्मरण भी छपे हैं. जैसे कुलदीप नैयर, साहिर, जावेद अख्तर और भूषण बनमाली पर लिखे उनके संस्मरण हैं. कुलदीप नैयर वाले संस्मरण में पीर साहब को लेकर गुलज़ार ने अद्भुत संस्मरण लिखा है, लेकिन उसका ही जब मैंने अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, तो वह मज़ा नहीं आया, जो हिंदी में पढ़कर आया था, क्योंकि जो भाषा की रवानगी हिंदी में थी, वह अंग्रेजी में नहीं है. हो सकता है कि गुलज़ार को हिंदी में नहीं पढ़ पाने वाले पाठकों को अंग्रेजी में पढ़ना सुखकर लगे, लेकिन गुलज़ार की भाषा का आस्वादन तो हिंदी में ही संभव है.

साहिर लुधियानवी और जावेद अख्तर का बेहद आत्मीय और क़रीबी रिश्ता था. अपने इस संस्मरण में गुलज़ार ने साहिर और जावेद, जिसे उनके क़रीबी जादू कहते हैं, के प्यार और प्यार भरे नफ़रत के रिश्तों पर आत्मीयता से लिखा है. गुलज़ार के मुताबिक़, जावेद अख्तर और उनके पिता जां निसार अख्तर के बीच बनती नहीं थी, लेकिन जब तक जावेद की मां जीवित रहीं, तब तक तो वह अपने पिता के साथ रहते रहे, लेकिन मां की मौत के बाद उनका पिता के साथ रहना मुमकिन नहीं हो पा रहा था और वह किसी इमोशनल ठौर की तलाश में थे. इस तलाश ने उनको साहिर के और क़रीब ला दिया था. साहिर उस दौर में कृष्ण चंदर की जुहू वाली कोठी में रहा करते थे और हर रोज़ शाम को पीने पिलाने का दौर चलता था. उनके साथ ओम प्रकाश अश्क भी रहा करते थे. एक रोज़ रसरंजन के दौरान अश्क ने साहिर से पूछा– एक पैग के बाद तुम सभी को गाली–गलौच क्यों करने लगते हो? साहिर ने पंजाबी में बोला– यार...अब शराब नाल कुछ चटपटा तो होना ही चाहीदा ना. उसके बाद साहिर की मौत और जादू के सौ रुपये का मशहूर वाक़या भी गुलज़ार ने लिखा है. साहिर की मौत अचानक हुई थी. वह अपने बीमार दोस्त डॉ. कपूर का दिल बहलाने के लिए ताश की बाज़ी तैयार करवा रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और साहिर वहीं गिर पड़े. बाद में जावेद अख्तर साहिर के पार्थिव शरीर को एक टैक्सी ड्राइवर और साहिर के ड्राइवर की मदद से रात को उनके घर लेकर पहुंचे. सुबह जब जादू साहिर के घर से बाहर निकले, तो टैक्सी ड्राइवर बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था. जावेद ने बातचीत के बाद उसको सौ रुपये का नोट देने लगे, लेकिन ड्राइवर के इंकार करने पर बोले–रख लो, रख लो यह सौ रुपये. मैं जानता हूं कि वह शख्स अपने पैसे वसूलना जानता था. अपनी मौत के बाद भी उसने अपने सौ रुपये वसूल ही लिए. दरअसल, मुफ़लिसी के वक़्त जावेद को साहिर ने सौ रुपये दिए थे. यह वाक़या कई बार लिखा–बोला जा चुका है, लेकिन गुलज़ार की क़लम के कहने के अंदाज़ ने इसे ख़ास बना दिया है.

इसके अलावा भी सवा दो सौ पेज के इस संग्रह में कई दिलचस्प संस्मरण और कहानियां हैं, जो अंग्रेजी के पाठकों को गुलज़ार के गद्य से परिचित करवाएंगे. मेरी आपत्ति सिर्फ़ इस बात को लेकर है कि इस संग्रह को गुलज़ार की कहानियों के संग्रह के रूप में पेश किया गया है, जबकि यह संग्रह कहानियों और संस्मरणों का कोलाज है. दरअसल, यह बाज़ार की मांग और प्रकाशक की स्मार्टनेस है, जो पाठकों को भरमाकर अपनी झोली भरते हैं. हलांकि बैक कवर पर फैसिनेटिंग स्टोरीज के शीर्ष के बाद इन संस्मरणों को रियल लाइफ स्टोरीज कहा गया है और आलोचना से बचने का रास्ता छोड़ा गया है. सवाल यह उठता है कि क्या यह अनुवादक का दायित्व नहीं था कि वह इस बात को साफ़ करते कि इस संग्रह में कहानियों के अलावा, गुलज़ार के संस्मरण भी हैं. लेकिन बाज़ार को भुनाने की चाहत ने युधिष्ठिर के अश्वत्थामा हतो– नरो वा कुंजरो कहने के बीच शंख बजा देने की चालाकी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वह तो महाभारत था, जहां यह चालाकी काम कर गई. पुस्तकों के बाज़ार में यह शंखघोष कितना काम करता है, यह देखने वाली बात होगी.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

नामवर सिंह की कविताई विशेषताएं!

हाल में राजकमल प्रकाशन ने आलोचक नामवर सिंह की प्रारंभिक रचनाओं की एक किताब प्रकाशित की है. आइए जानते हैं, इस किताब में क्या ख़ास है?

फ़िरदौस ख़ान
firdaus.journalist@gmail.com

नामवर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रमुख समकालीन आलोचक हैं. 26 जुलाई, 1926 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के गांव जीयनपुर में जन्मे नामवर सिंह ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत काव्य लेखन से की थी. उन्होंने पहली कविता 1938 में लिखी. पहले वह ब्रजभाषा में कवित्त और सवैया लिखते थे. 1941 में अध्ययन के लिए वह बनारस आए और यहां उनकी मुलाक़ात त्रिलोचन शास्त्री से हुई. त्रिलोचन ने उन्हें खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने दो बार अपनी कविताओं की किताब प्रकाशित कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. इसके बाद वह गद्य लेखन करने लगे. 1951 में उनका निबंध संग्रह बक़लम ख़ुद प्रकाशित हुआ. इसका पुस्तक परिचय त्रिलोचन शास्त्री ने कुछ यूं लिखा, बक़लम ख़ुद में 17 व्यक्ति व्यंजक निबंध हैं. व्यंजना तो इस प्रकार की है कि पुस्तक की बजाय यह ज़िंदादिल आदमी ही लगेगी. बक़लम ख़ुद जनता की जय का उद्घोष, संघर्ष की प्रेरणा और अभियान की आकांक्षा है. निरुद्देश्य मज़ाक़ नहीं, यह सोद्देश्य संजीदगी है, जो सत्य को सुपाच्य रूप देती है. नामवर सिंह की कृतियों में क़लम ख़ुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृथ्वीराज रासो की भाषा, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद और इतिहास और आलोचना शामिल हैं. उन्हें उत्कृष्ट रचनाओं के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली का शलाका सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान भी मिला.

हाल में राजकमल प्रकाशन ने नामवर सिंह की प्रारंभिक रचनाओं की एक किताब प्रकाशित की है, जिसका नाम है प्रारम्भिक रचनाएं नामवर सिंह. इसके पहले खंड में कविताएं, दूसरे में विविध विधाओं की गद्य रचनाएं और तीसरे में बक़लम ख़ुद के निबंधों को शामिल किया गया है. उनकी कविताओं में भाव भी है, ग़ज़ब का प्रवाह भी. देखिए–

नभ के नीले सूनेपन में
हैं टूट रहे बरसे बादर
जाने क्यों टूट रहा है तन
बन में चिड़ियों के चलने से
हैं टूट रहे पत्ते चरमर
जाने क्यों टूट रहा है मन
घर के बरतन की खन–खन में
हैं टूट रहे दुपहर के स्वर
जाने कैसा लगता जीवन

नामवर सिंह सबसे पहले कवि हैं. शुरुआती साहित्य जीवन में उन्होंने कविताएं ही ज़्यादा रचीं, लेकिन बहुत कम कविताएं ही प्रकाशित हो पाईं. ख़ास बात यह है कि उनकी छंद पर अच्छी पकड़ थी. उनकी कविता नहीं बीतती सांझ की कुछ पंक्तियां देखिए–

दिन बीता, पर नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ
नहीं बीतती, नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ
ढलता–ढलता दिन दृग की कोरों से ढुलक न पाए
मुक्त कुंतले! व्योम मौन मुझ पर तुम–सा ही छाया
मन में निशि है किंतु नयन से नहीं
बीतती सांझ

उन्हें प्रकृति से भी बेहद प्रेम है, इसलिए उनकी रचनाओं में प्रकृति के कई मनोहारी रूप देखने को मिलते हैं. उनकी कविता हरित फौवारों सरीखे धान को लीजिए, जो उन्होंने धान के खेत को देखकर रची.

हरित फौवारों सरीखे धान
हाशिये–सी विंध्य–मालाएं
नम्र कंधों पर झुकीं तुम प्राण
सप्तवर्णी कैश फैलाए
जोत का जल पोंछती–सी छांह
धूप में रह–रहकर उभर आए
स्वप्न के चिथड़े नयन–तल आह
इस तरह क्यों पोंछते जाएं?

उनकी कविताओं में एक अलग तरह का आकर्षण है. पाठकों को वे इसलिए भी पसंद आती हैं, क्योंकि इनमें कहीं न कहीं उनकी ख़ुद की अनुभूतियों की झलक होती है. किताब के संपादक भारत यायावर भूमिका में लिखते हैं कि नामवर सिंह की भाषा में सफ़ाई और निखार होते हुए भी जहां–तहां छायावादी झलक है. क्लिष्ट–कल्पनाओं को भी उनकी कविताओं में देखा जा सकता है. त्रिलोचन शास्त्री ने जिस भाषा–शैली और अनोखे अंदाज़ में नामवर सिंह की रचनाओं की कविताई विशेषताओं को रेखांकित किया है, वह अपूर्व है, बेमिसाल है. काव्य की तरह गद्य लेखन में भी नामवर सिंह अपनी अलग ही छाप छोड़ते हैं. उनकी प्रारंभिक रचनाओं में कहानी की कहानी भी है, जिसमें उन्होंने खरपत्तू नामक चरित्र का प्रभावी शब्द चरित्र पेश किया है. इसी तरह दार्जिलिंग की एक झलक में उन्होंने काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया है. दरअसल, नामवर सिंह की प्रारंभिक रचनाओं का अपना अलग ही महत्व है. उनकी रचनाओं में कच्चापन नहीं मिलता. इसका कारण यह है कि विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने सघन साहित्य–साधना की थी. उनकी स्मरणशक्ति लाजवाब थी. बौद्धिक ओजस्विता से वह भरे हुए थे. इसीलिए बहुत कम उम्र में ही वह एक बौद्धिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं. बहरहाल, यह किताब नामवर जी के कृतित्व को पेश करती है. हिंदी साहित्य के शोधार्थियों के लिए यह बेहद उपयोगी किताब है.■

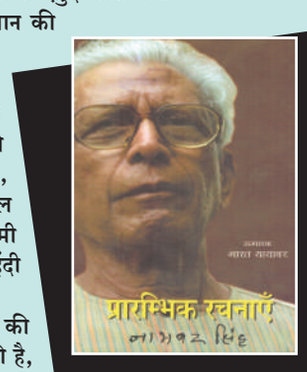

समीक्ष्य कृति : प्रारंभिक रचनाएं
संपादक : भारत यायावर
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
क़ीमत : 450 रुपये

हिंदी पत्रकारिता के शलाका पुरुष

पंडित कमलापति त्रिपाठी

जाने माने मूर्धन्य पत्रकार और राजनेता पंडित कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को बढ़ावा दिया था, कैसे? जानने के लिए पढ़िए.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

सत्तर वर्षों तक पंडित कमलापति त्रिपाठी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर लगातार चमकते रहे. विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता के शलाका पुरुष के रूप में सदैव याद किया जाएगा. पंडित जी की सर्जक चेतना के कारण महादेवी वर्मा ने उन्हें अजातशत्रु की उपाधि दी थी और कहा था कि त्रिपाठी जी हमारी बिरादरी (लेखकों) के थे, राजनीति ने उन्हें हमसे उधार में ले लिया था. वस्तुत: जिस युग में त्रिपाठी जी हुए, उसका यही युगधर्म था. उनके इसी कथन की पुष्टि करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा कि पंडित जी का व्यक्तित्व मूलत: कवि का व्यक्तित्व है, साहित्य का व्यक्तित्व है, मगर जिस युग में वह जन्मे, वह स्वतंत्रता के यज्ञ का युग था, उस समय जिसके पास दुर्लभ शक्ति थी, वह उसी की आहूति बनती थी. हेमवती नंदन बहुगुणा ने पंडित जी के संदर्भ में कहा कि इस युग में पंडित जी की लेखनी ने हज़ारों युवकों को आंदोलित कर स्वतंत्रता संघर्ष में पड़ने की प्रेरणा दी. उनके संदर्भ में श्री शंकर शुक्ल ने लिखा कि जिस प्रकार पराड़कर जी राष्ट्रीय युग के व्याख्याता, समीक्षक और संदेशवाहक थे, कमलापति जी ने भी अपनी लेखनी से इसी महान दायित्व का सफल निर्वहन किया है.

वह 1932 में वाराणसी से प्रकाशित होने वाले आज दैनिक में पराड़कर जी के अधीन तीन महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करके उप संपादक बन गए. पराड़कर जी के साथ राष्ट्रीय जागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन में आज के माध्यम से त्रिपाठी जी ने एक ऐतिहासिक योगदान किया. उनके इस योगदान को वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीशंकर दास ने इस तरह परिभाषित किया, पंडित कमलापति त्रिपाठी ने उन ऐतिहासिक दिनों में बड़े ही प्रभावपूर्ण संपादकीय लेख लिखे, जो विदेशी शासन के विरुद्ध अग्नि वर्षा तो करते ही थे, साथ ही जनसामान्य में स्वाधीनता के लिए सर्वस्व समर्पित करने की भावना भी भरते थे, जिसका निष्कर्ष यह है कि पंडित जी ने अपनी लेखनी के दौरान स्वाधीनता आंदोलन को खड़ा किया और जनता जनार्दन में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव भी जगाया.

1943 में पंडित पराड़कर जी आज छोड़कर दैनिक संसार में चले गए और पंडित त्रिपाठी जी आज के प्रधान संपादक बने और अंग्रेजों के कुशासन का भंडाभोड़ करते रहे. फिर वह भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जेल गए. 1945 में जेल से आने के बाद उन्होंने संसार में बतौर संपादक कार्य किया. उन्होंने ग्राम संसार, आंधी और युगधार आदि प्रकाशनों का संपादन किया. उनके समय में दैनिक संसार के माध्यम से भारतीय संविधान का देश में सबसे पहले संपूर्ण हिंदी रूपांतर प्रकाशित किया गया.

फिर 1952 में वह मंत्री बने. वह जन्म से राष्ट्रभक्त थे, किंतु आचार्य कृपलानी के संपर्क ने उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी. गांधी जी के आह्वान पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े. जेल में उन्होंने बेचन शर्मा उग्र जी के साथ हस्तलिखित साप्ताहिक पत्रिका कारागार का प्रकाशन किया. उग्र जी के प्रभाव में आकर उन्होंने औरंगाबाद स्थित मुहल्ले में लक्ष्मी गोपाल पुस्तकालय की स्थापना की और अपने सहयोगी युवा साथियों के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका उग्र का प्रकाशन किया. उन्होंने गांधी जी के निर्देश पर देश की पहली खादी संस्था श्री गांधी आश्रम की नींव रखी.

उनके संदर्भ में श्री शंकर शुक्ल ने लिखा कि जिस प्रकार पराड़कर जी राष्ट्रीय युग के व्याख्याता, समीक्षक और संदेशवाहक थे, कमलापति जी ने भी अपनी लेखनी से उसी महान दायित्व का सफल निर्वहन किया. वह दरअसल, हिंदी प्रेमी थे और इसीलिए उन्होंने रेलवे में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया.

वह धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे. जब 1987 में विश्व हिंदू परिषद ने रामजन्म भूमि के शिलान्यास की राजनीति शुरू की, तो पंडित जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर गिरने वाला प्रथम फावड़ा मेरी गर्दन पर गिरेगा. उन्होंने अपने जीवन के अवसानकाल में भारतीय राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध एक प्रखर राष्ट्रीय बहस की शुरुआत की.

काशी के इस महायोद्धा को आज पूरा देश नमन करता है. उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रभावित होकर सोनिया गांधी ने पंडित कमलापति त्रिपाठी शताब्दी को वर्ष भर मनाने की घोषणा की थी. पंडित जी हिंदी पत्रकारिता के शलाका पुरुष, धर्मनिरपेक्षता के प्राण एवं मानवता के प्रहरी के रूप में युगों–युगों तक जाने और माने जाएंगे.■

किताब मिली

पुस्तक	लेखक	प्रकाशक	मूल्य
दर दर गंगे	अभय मिश्रा, पंकज रामेन्दु	पेंगुइन	199 रुपये

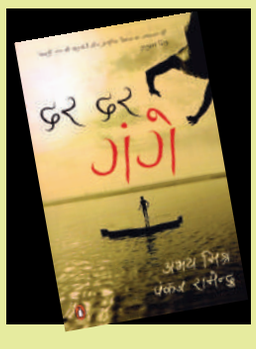

यह गंगा की यात्रा की कहानी है, जो गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक पहुंचती है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

सून नोन ने कहा कि नेक्सस 4 में क्वॉलकॉम स्नै पड्रैगन एस 4 प्रो प्रोसेसर दिया गया है.

महिन्द्रा वेरिटो वाइब

बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी नई वेरिटो आगाती 5 जून को भारतीय बाज़ार में पेश की जाएगी. ग़ौरतलब है कि कंपनी ने इस कार का निर्माता सब 4 मीटर के आधार पर किया है, जिसके कारण इस कार पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि कार की क़ीमत कम से कम रहेगी.

देश की प्रमुख एसयूवी वाहन निर्माता कंपनी महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने भारतीय बाज़ार में अपनी शानदार सिडान कार वेरिटो के नए कॉम्पैक्ट अवतार को पेश करने की योजना बनाई है. कंपनी ने अपनी इस नई कार को वाइब नाम दिया है. बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी नई वेरिटो आगाती 5 जून को भारतीय बाज़ार में पेश की जाएगी. ग़ौरतलब है कि कंपनी ने इस कार का निर्माता सब 4 मीटर के आधार पर किया है, जिसके कारण इस कार पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि कार की क़ीमत कम से कम रहेगी.

कंपनी ने इस कार में 1.5 लीटर की क्षमता डीसीआई इंजन का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, कंपनी ने इस कार का डिजाइन ख़ुद अपने इन हाउस रिसर्च सेंटर पर ही किया है. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने इस बात की जानकारी दी है कि इस कार में प्रयुक्त डीजल इंजन 20 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करेगा. वैसे इस कार में रेनाल्ट का शानदार इंजन प्रयोग किया गया है. हालांकि अभी इस कार के पेट्रोल संस्करण के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, यानी कि फ़िलहाल कंपनी इस वेरिटो वाइब के डीजल संस्करण को ही बाज़ार में पेश करेगी. ■

नई सीबी ट्रिगर

कंपनी ने अपनी इस नई सीबी ट्रिगर में 150 सीसी की क्षमता वाले सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि बाइक को 14.14 पीएस, 8500 आरपीएम की शक्ति प्रदान करता है.

जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने भारतीय बाज़ार में अपने वाहनों की विशाल रेंज में एक और इज़ाफ़ा किया है. हाल ही में कंपनी ने अपने ड्रीम सीरीज के बाद नियो को पेश किया था. इस बार होंडा ने अपने बेहतरीन कम्यूटर बाइक सीबी ट्रिगर को पेश किया है. बाज़ार में होंडा सीबी ट्रिगर की शुरुआती कीमत 67,384 रुपये तय की गई है. कंपनी ने अपनी इस नई सीबी ट्रिगर में 150 सीसी की क्षमता वाले सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि बाइक को 14.14 पीएस, 8500 आरपीएम की शक्ति प्रदान करता है. हेवी सीसी की इंजन क्षमता होने के बावजूद कंपनी ने इस बाइक के माइलेज को बेहद ही शानदार रखा है. इसमें एक लीटर इंधन में 60 किलोमीटर तक का सफर करने में सक्षम है. इस बाइक को अपने लोकप्रिय बाइक यूनिकॉर्न की तर्ज पर ही तैयार किया गया है. इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स का प्रयोग भी किया गया है. इसमें कम्बाइंड ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया है. कम्बाइंड ब्रेक सिस्टम आगे और पीछे दोनों ही पहियों में लगे डिस्क ब्रेक के साथ कार्य करता है. इसमें मोनो शॉक, एलईडी, टेल लाइट, डिजीटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का प्रयोग किया गया है. इसमें मेंटेनेंस फ्री बैटरी और विस्कोस एअर फिल्टर को शामिल किया है, जिससे कि आपको बैटरी की मेंटेनेंस की चिंता ही नहीं रहेगी. ■

पी51 स्मार्टफोन

पैनासोनिक ने भारत में पी51 के ग्लोबल लॉन्च के साथ ही स्मार्टफोन मार्केट में दोबारा एंट्री की है. इस फोन की क़ीमत 26,990 रुपये है. 1280 गुणा 720 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 295पीपीआई पिक्सल डेंसिटी के साथ 5 इंच स्क्रीन वाला यह फोन एंड्रॉयड जेलीबीन पर चलता है. असाही ड्रैगनट्रेल स्क्रैचप्रूफ और डैमेजप्रूफ ग्लास के ज़रिए टचस्क्रीन की सेफ्टी को बढ़ाया गया है.

फोन में पीछे की तरफ़ 8 मेगापिक्सल कैमरा और 1.3 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है. इसमें 4 जीबी की इंटरनल मेमोरी है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड के ज़रिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह ड्युल सिम फोन है, जिसकी मोटाई महज़ 85 एमएम है और वज़न 135 ग्राम. इसमें 1.2 गीगाहट्र्ज़ का क्वॉड कोर प्रोसेसर और हाई डेफिनेशन आईपीएस डिस्प्ले भी है. पी51 रीटेल स्टोर्स में उपलब्ध है. कंपनी इसके बाद जल्द ही 7000 रुपये की रेंज से शुरू होने वाले मोबाइल फोन लाएगी, जिसकी रेंज 35,000 रुपये तक होगी. ■

म्यूजिक ए88

इस फोन पर एम-लाइव कॉन्टेंट स्टोर से अनलिमिटेड गाने फ्री डाउनलोड किए जा सकते हैं. 150 गाने और 50 प्रीमियम विडियोज़ इस फोन पर प्रीलोडेड मिलेंगे.

माइक्रोमैक्स ने कैनवस म्यूजिक ए88 नाम से एंड्रॉयड पर चलने वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. फोन की क़ीमत 8,499 रुपये रखी गई है. फोन में कंपनी ने सबसे अधिक म्यूज़िक एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पर रहा है. माइक्रोमैक्स इस फोन के साथ ऑडियो ब्रैंड जेबीएल का टेम्पो हेडसेट भी दे रही है. इस फोन पर एम-लाइव कॉन्टेंट स्टोर से अनलिमिटेड गाने फ्री डाउनलोड किए जा सकते हैं. 150 गाने और 50 प्रीमियम विडियोज़ इस फोन पर प्रीलोडेड मिलेंगे. फोन में 1 गीगाहट्र्ज़ मीडियाटेक ड्युल-कोर प्रोसेसर और 512 एमबी की रैम है. ड्युल सिम वाले इस फोन में 480गुणा854 पिक्सल वाला 4.5 इंच का डिस्प्ले है. यह एंड्रॉयड 4.1 यानी जेलीबीन पर चलता है.

इस फोन में पीछे की तरफ़ ड्युल एलसीडी के साथ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है. आगे की तरफ़ वीजीए कैमरा है. इसमें 4 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड के ज़रिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 1800एमएच बैटरी है, जोकि काले और सफेद रंग में उपलब्ध है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्रोमा 3जी टैबलेट

इस साल कंपनी ने दीवाली तक हाई-एंड रेफ्रिजरेटर लॉन्च करने की योजना भी बनाई है. क्रोमा ब्रैंड के स्मार्टफोन पहले ही लॉन्च कर दिए गए हैं.

टाटा ग्रुप की कंपनी इनफिनिटी ने हाल ही में 3जी-इनबिल्ड टैबलेट लॉन्च करने की योजना बनाई है. इसकी कीमत 9,990 रुपए होगी. कंपनी अपने प्राइवेट लेबल आइटम्स का एक्सपैंशन करना चाहती है.

इस साल कंपनी ने दीवाली तक हाई-एंड रेफ्रिजरेटर लॉन्च करने की योजना भी बनाई है. क्रोमा ब्रैंड के स्मार्टफोन पहले ही लॉन्च कर दिए गए हैं. वह इसे चीन से सोर्स करती है. इनफिनिटी रीटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ अजीत जोशी ने कहा, हम प्राइवेट लेवल में अपनी ऑफरिंग्स बढ़ा रहे हैं. हम आने वाले दिनों में और कई प्रॉडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं. कंपनी चीन और ताइवान से टैबलेट को सोर्स करेगी. ग़ौरतलब है कि कंपनी अभी क्रोमा-ब्रैंडेड 2जी टैबलेट्स बेचती है, जिसकी कीमत 6,990 रुपए है. ■

नेक्सस 4 स्मार्टफोन

स्मार्टफोन मार्केट में एलजी ने गूगल के साथ मिलकर नया नेक्सस 4जी स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. नेक्सस 4 गूगल के सबसे नए स्मार्टफोनों में से एक है. 4.7 इंच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ नेक्सस 4 में कई नए फीचरों को शामिल किया गया है. यह फोन देखने में एलजी के ऑप्टिमस से थोड़ा मिलता जुलता है. पहली बार गूगल ने फोन भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया है.

नए फोन को लॉन्च करते हुए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्ट मि. सून नोन ने कहा कि नेक्सस 4 में क्वॉलकॉम स्नै पड्रैगन एस 4 प्रो प्रोसेसर दिया गया है. इसकी मदद से फोन में 3डी ग्राफिक लगाया गया है. यानी यूजर फोन में हाईडिफिनेशन गेम और वीडियो दोनों बड़े आराम से देख सकते हैं. साथ में 2 जीबी रैम भी दी गई है, जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाती है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

फिक्सिंग की फांस में फंसे ये जेंटल खिलाड़ी

टीम, देश और फैंस के साथ दग़ाबाज़ी?

फिक्सिंग के आरोप में कुछ क्रिकेट खिलाड़ी जेल की हवा खा रहे हैं. इस जेंटलमैन खेल में फिक्सिंग का खेल पुराना है. कई बार इस खेल पर फिक्सिंग का दाग़ लग चुका है. आख़िर खिलाड़ी टीम, देश और फैंस के साथ क्यों दग़ाबाज़ी कर रहे हैं? कहीं यह अब सेक्स, सट्टा और ब्लैकमेलिंग का खेल बनकर तो नहीं रह गया है?

धीरेंद्र शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

मैदान में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज़ एस श्रीसंत गेंदबाज़ी कर रहे हैं और बल्लेबाज़ उनके हर ओवर में खुलकर रन बना रहे हैं. दर्शक सोच रहा है कि आख़िर श्रीसंत इतनी ढीली गेंद क्यों फेंक रहा है? दर्शकों को शायद नहीं मालूम कि श्रीसंत इन ढीली गेंदों के लिए पहले ही लाखों की मोटी रक़म और कॉलगर्ल्स की सेवाएं ले चुके हैं. ऐसा सिर्फ़ श्रीसंत ही नहीं, बल्कि राजस्थान रॉयल्स के दो और गेंदबाज़ अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण भी कर चुके हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि ये तीनों गेंदबाज़ अपनी टीम के लिए खेलने की बजाय बुकीज के लिए खेल रहे थे और उनके करोड़ों के वारे-न्यारे भी करा रहे थे. दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों राजस्थान रॉयल्स के तीन गेंदबाज़ों श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण समेत 11 बुकीज पकड़े हैं और इसीलिए अभी आईपीएल में खेल रहे 40 और खिलाड़ी शक के दायरे में हैं. ये तीनों खिलाड़ी ब्लैकबेरी मैसेंजर, वाट्सअप और वीचौट के ज़रिए बुकीज के संपर्क में रहते थे. श्रीसंत फिक्सिंग के आरोप में न सिर्फ़ इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं, बल्कि केरल सरकार ने राज्य में ग़रीब बच्चों के लिए चलाई जा रही अपनी योजना करुण्या के विज्ञापन से उनका नाम हटा दिया है.

कभी टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ रहे श्रीसंत को 2012 में राजस्थान रॉयल्स ने चार लाख डॉलर (करीब 2.40 करोड़ रुपये) में ख़रीदा था. बहुत पहले श्रीसंत और उसका दोस्त जीजू जनार्दन साथ-साथ केरल के एर्नाकुलम क्लब के लिए तेज़ गेंदबाज़ी किया करते थे. श्रीसंत तो टीम इंडिया के लिए खेलने लगे, लेकिन जीजू रणजी तक भी नहीं पहुंच पाया और वह सट्टेबाज़ बन गया. इसी जीजू ने श्रीसंत को स्पॉट फिक्सिंग के लिए तैयार किया. हरियाणा का अजीत चंदीला कभी दिल्ली में होने वाले क्लब मैचों में खेलकर महज़ 1400-2000 रुपये कमाता था, लेकिन आईपीएल में खेलने पर उसके साथी खिलाड़ियों ने कहा कि वह प्रतिभाशाली की बजाय जुगाड़ू था. इसके संबंध बड़े खिलाड़ियों से थे. बुकीज खिलाड़ियों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरकीब का इस्तेमाल कर रहे थे. खिलाड़ियों को पैसा और लड़कियां मुहैया कराई जा रही थीं. श्रीसंत ने तीन बार लड़कियों की सेवाएं ली थीं, अजीत चंदीला तो हर बार बुकीज से पैसों की अपेक्षा लड़कियों की फ़रमाइश ज़्यादा करता था. चंदीला ने क़रीब 13-14 बार लड़कियों की सेवाएं ली थीं. अंकित चव्हाण इस मामले में साफ़ रहा और उसने बुकीज से कभी लड़कियों की मांग नहीं की. इसके अलावा, खिलाड़ी अपनी अय्याशी के लिए जो भी मांग करते थे, बुकीज उसे पूरा करते थे. फिक्सिंग में फंसे अजीत चंदीला ने बुकीज के क्रेडिट कार्ड से ढाई लाख की दो जींस और दो लाख की एक घड़ी ली थी. अगर खिलाड़ी इन सब सेवाओं को लेने के बाद उनके मन मुताबिक़ नहीं खेलते थे, तो उन्हें दाऊद के नाम की धमकी भी दी जाती थी. खिलाड़ियों को पूरी तरह से अपने क़ाबू में करने के लिए उनका लड़कियों के साथ एमएमएस बनाने की योजना थी, ताकि उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जा सके.

नई बात नहीं है फिक्सिंग

क्रिकेट में फिक्सिंग कोई नई बात नहीं है. पिछले कुछ दशकों से क्रिकेट में बड़े पैमाने पर पैसा आने लगा, तो धीरे-धीरे फिक्सिंग का धंधा भी पनपने लगा. वर्ष 2002 में भी दिल्ली पुलिस ने ही क्रिकेट में हो रहे फिक्सिंग का पर्दाफ़ाश किया था. इस समय दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन कप्तान हेंसी क्रोन्ये और एक बुकी के बीच हुई फोन पर बातचीत को दिल्ली पुलिस ने ट्रेस किया था. इस फोन टेप से ख़ुलासा हुआ कि क्रोन्ये ने मैच हारने के लिए बुकी से पैसे लिए थे. बाद में इस मामले में जांच होने के बाद क्रोन्ये ने मैच हारने की बात क़बूली. हालांकि जांच में क्रोन्ये ने फिक्सिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर सलीम मलिक, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन और अजेय जडेजा का नाम लिया. जडेजा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया और इन दोनों खिलाड़ियों के क्रिकेट के सभी स्वरूपों में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

इस बार भी दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट में फिक्सिंग के जाल को सुलझाने की कोशिश की है. पुलिस ने ख़ुलासा किया कि श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण ने एक-एक ओवर के लिए 40 से 60 लाख रुपये में सौदा किया था और आधी रक़म पहले ही ले ली थी. बीसीसीआई द्वारा निलंबित कर दिए गए इन तीनों खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साज़िश) का मामला दर्ज किया है. राजस्थान रॉयल्स टीम का एक पूर्व खिलाड़ी अमित सिंह इस स्पॉट फिक्सिंग का मास्टरमाइंड है. अमित आईपीएल के पिछले सीजन में कई मैच खेल चुका था. इस बार जब उसका चयन टीम में नहीं हुआ, तो वह बुकीज से मिलकर फिक्सिंग करने लगा. दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले इसी का फोन सर्विलांस पर लगाया था और इसके बाद क़रीब 50 और फोनों को सर्विलांस पर लगाया गया.

डी कंपनी के इशारे पर चलता है फिक्सिंग का खेल?

पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सट्टेबाज़ी के इस खेल को अंडरवर्ल्ड सरगना और डी कंपनी के मुखिया दाऊद इब्राहीम के इशारों पर ही चलाया जा रहा है. खिलाड़ियों से सीधा संपर्क दाऊद इब्राहीम के लोग नहीं करते. भारत में मौजूद डी कंपनी के एजेंट बड़े सट्टेबाज़ इस काम में ऐसे फिक्सरों की तलाश करते हैं, जो खिलाड़ियों को इस काम के लिए तैयार कर सकें. इस काम के लिए दाऊद इब्राहीम का छोटा भाई अनीस इब्राहीम और छोटा शकील मुख्य तौर पर 12 बड़े बुकीज को निर्देश देते थे. इनमें सुनील अभिचंदानी उर्फ़ सुनील दुबई इन सब बुकीज का सरगना है. माना जाता है कि पिछले आईपीएल और विश्व कप के दौरान दाऊद इब्राहीम ने अरबों रुपये की कमाई की थी. आईपीएल के इस सीजन में 40 हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक का सट्टा लगा हुआ है. क्रिकेट में करोड़ों रुपये के इस अवैध कारोबार में छोटे खिलाड़ी आसानी से फंस जाते हैं. इसकी वजह है आईपीएल. आईपीएल की टीम में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को जहां 10 से 12 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, वहीं घरेलू खिलाड़ी को 10 से 30 लाख रुपये मिलते हैं. पैसों के इस भारी अंतर का फ़ायदा बुकीज उठाते हैं और छोटे खिलाड़ी को अपने जाल में फंसा लेते हैं. इस बारे में दिल्ली के एक बुकी का कहना है कि आईपीएल में पैसों की बारिश से खिलाड़ी बौरा जाते हैं और दो महीने के इस खेल में वे करोड़ों रुपये कूटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. इस धंधे में कई नामी खिलाड़ी भी शामिल हैं. श्रीसंत जैसे तो छोटे प्यादे हैं. बुकीज ऐसे खिलाड़ियों को भी फंसाते हैं, जिनका करियर ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुका है. सट्टेबाज़ों की योजना तो इस पूरे आईपीएल को फिक्स करने की थी, मगर कुछ खिलाड़ियों के ऐन वक़्त पर मना करने से यह योजना फेल हो गई. सट्टेबाज़ों ने आईपीएल में अपना दबदबा इस तरह बना रखा था कि फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों के पास इस प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले ही हवाला के ज़रिये पैसा पहुंच गया था. क्रिकेटर अजीत चंदीला की पत्नी ने तो अपने पति से फोन करके पूछा भी था कि अभी तो आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ और यह लाखों रुपया कहां से आ गया? इस पर अजीत ने जवाब दिया कि इस संबंध में बाद में बात करेंगे. पुलिस द्वारा टेप की गई बातचीत से पता चलता है कि अजीत चंदीला और अंकित दरअसल, मैच फिक्सिंग के लिए ही खेल रहे थे और अजीत दूसरे खिलाड़ियों को बुकीज के लिए फंसाने का काम करता था. अब पुलिस की क़ैद में तीनों खिलाड़ी उस समय को कोस रहे हैं, जब उन्होंने बुकीज के प्रस्तावों को स्वीकारा था. इन्हीं प्रस्तावों के कारण ये खिलाड़ी जल्दी ही लखपति तो बन गए, मगर इसके साथ इन पर ऐसा बदनुमा दाग़ लग गया है कि अब ये सार्वजनिक रूप से कहीं नज़र नहीं आएंगे. इनका क्रिकेट करियर भी यहीं समाप्त हो गया है. आईपीएल के पिछले साल के सीजन में भी पांच खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे और उन पर महज़ प्रतिबंध लगा कर छोड़ दिया गया था. फिक्सिंग के कलंक से क्रिकेट को बचाने के लिए उस घटना से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोई सबक़ नहीं लिया था. इसी का परिणाम है कि इस सीजन में यह घटना हुई.

इन खिलाड़ियों और फिक्सिंग के बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पल-पल पलट रहा है. पहले बीसीसीआई कहती है कि हम खिलाड़ियों को दंडित करेंगे और फिक्सिंग को रोकेंगे. बाद में बयान आता है कि हम फिक्सिंग को रोक पाने में असमर्थ हैं और यह पुलिस का काम है. सट्टेबाज़ी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत का सट्टा बाज़ार क़रीब तीन लाख करोड़ का है और यह लगातार बढ़ रहा है. ज़्यादातर सट्टेबाज़ी अंडरवर्ल्ड माफ़ियाओं द्वारा संचालित होती है. अंडरवर्ल्ड से जुड़ने के कारण खिलाड़ियों को धमकियां भी मिलती हैं.

क्या है स्पॉट फिक्सिंग?

पूरे मैच को फिक्स कर इसके परिणाम को बदलने को मैच फिक्सिंग कहते हैं और मैच के दौरान कुछ गेंदों पर निर्धारित रन देने, वाइड, फुलटॉस, नो बॉल देने और बल्लेबाज़ के आउट होने या किसी गेंद पर रन न बनाने को स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं. मैच फिक्सिंग की बजाय स्पॉट फिक्सिंग ज़्यादा आसान होती है. स्पॉट फिक्सिंग में हर गेंद के साथ दाव लगाने का रेट बदल जाता है. ■

फंदे में फंसे कई और जेंटलमैन

आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले का पर्दाफ़ाश होने के बाद अब तक दो दर्जन से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस के अनुसार, कुछ और जेंटलमैन खिलाड़ी तथा कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं. वैसे, अभिनेता विंदू दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद फिक्सिंग के फंदे में कई बड़े जेंटलमैन के नाम जुड़ गए हैं. सूत्रों के अनुसार, विंदू का चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक के काफ़ी क़रीबी रिश्तेदार के साथ गहरा संबंध है. फोन कॉल डिटेल्स से भी पता चल जाता है कि सीएसके के मालिक के रिश्तेदार ने एक-दूसरे से कई बार बातें की हैं. विंदू ने विराट, भज्जी और मनप्रीत का भी नाम लिया है. क्रिकेटर और बुकी बाबू राव के साथ फिल्म अभिनेताओं और क्रिकेट खिलाड़ियों के कई फोटो आने से भी पुलिस जांच का दायरा और बढ़ गया है. उधर, पाकिस्तान के विवादास्पद क्रिकेट अंपायर असद राउफ के आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग में नाम आने पर आईसीसी ने इंग्लैंड में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच अधिकारियों के पैनल से उनका नाम हटा दिया है. इतना ही नहीं, स्पॉट फिक्सिंग में शक के घेरे में आए बीसीसीआई चीफ के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर भी पुलिस की नज़र है. पुलिस का मानना है कि स्पॉट फिक्सिंग में गुरुनाथ की भी भूमिका हो सकती है. ■

कैसे चलता है बुकीज का धंधा?

मैदान से दूर सुरक्षित जगहों पर बैठे बुकीज की पकड़ स्टेडियम के वीआईपी लाउंज से लेकर खिलाड़ियों के स्टाफ तक होती है. इसके बाद दुबई से तय होता है कि हरेक गेंद पर दाव लगाने के लिए क्या भाव होगा. दुबई से भाव निश्चित होने के बाद वह मुंबई होते हुए दिल्ली तक आता है और इसके बाद बुकीज के मज़बूत नेटवर्क के ज़रिए यह भाव पूरे भारत की गली-गली तक फैल जाता है. इस खेल में तीन तरह के बुकी होते हैं-बड़ा वाला, बीच वाला और छोटा बुकी. बड़ा व छोटा बुकी एक दूसरे को नहीं जानते हैं और बीच वाला दोनों के बीच मध्यस्थ का काम करता है. बड़ा बुकी जब भाव खोलता है, तो बीच वाला ही इसे छोटे बुकियों तक पहुंचाता है. भाव लगाने के दौरान हर बात की रिकॉर्डिंग की जाती है, ताकि बाद में हारने वाले अपनी बात से मुकर न जाएं. स्पॉट फिक्सिंग के इस खेल में बुकीज अपने जाल में सबसे ज़्यादा गेंदबाज़ों को फंसाते हैं, क्योंकि गेंदबाज़ जब चाहे नोबॉल, वाइड बॉल और फुलटॉस फेंक सकते हैं. बल्लेबाज़ों के लिए स्पॉट फिक्सिंग करना आसान नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि वे स्पॉट फिक्सिंग में शामिल नहीं हो सकते. बल्लेबाज़ बुकीज से कम रन बनाने का सौदा तो कर सकते हैं, लेकिन इनका सौदा सामने वाले गेंदबाज़ और क्षेत्ररक्षक पर ज़्यादा निर्भर रहता है. स्पॉट फिक्सिंग के अभी तक जो मामले सामने आए हैं, उनमें गेंदबाज़ ही शामिल रहे हैं. इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच के दौरान मैच फिक्सिंग में पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ मुहम्मद आसिफ़, मुहम्मद आमेर और बल्लेबाज़ सलमान बट का नाम आया था. इंग्लिश काउंटी में स्पॉट फिक्सिंग में पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया का नाम शामिल था. पिछले साल के आइपीएल-5 में स्पॉट फिक्सिंग में गेंदबाज़ टीवी सुधींद्र और शलभ श्रीवास्तव थे. ■

फिक्सिंग का काला कारनामा

- 1998-शेन वार्न और मार्क वा ने स्वीकार किया था कि श्रीलंका में खेले गए सिंगर कप के दौरान मौसम और पिच की जानकारी सट्टेबाज़ को बेची थी.
- अप्रैल 2000 में क्रोन्ये ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने भारत में खेली गई वनडे सीरीज के दौरान अहम सूचनाएं 10 से 15 हज़ार डॉलर में बेची थीं.
- मई 2000- फिक्सिंग के आरोप में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मलिक मुहम्मद क़यूम और गेंदबाज़ अताइर रहमान आजीवन प्रतिबंध.
- नवंबर 2000- फिक्सिंग के दोषी पाए गए अज़हरुद्दीन, जबकि अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और भारतीय टीम के पूर्व फीजियो अली ईरानी के संबंध सट्टेबाज़ों से होने की पुष्टि की गई.
- दिसंबर 2000- फिक्सिंग के कारण अज़हरुद्दीन और अजय शर्मा पर आजीवन प्रतिबंध.
- अगस्त 2004- फिक्सिंग के कारण केन्या के पूर्व कप्तान मॉरिश ओडेंबे पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया.
- मई 2008 - फिक्सिंग के आरोप के कारण मैरियन सैमुअल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया.
- अगस्त 2010- लॉड्र्स टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग में पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान सलमान बट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ़ फंसे.
- फरवरी 2011- स्पॉट फिक्सिंग करने के दोषी पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान सलमान बट्ट पर 10 साल, मोहम्मद आमिर पर पांच साल और मोहम्मद आसिफ़ पर 7 साल के लिए बैन लगाया गया.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

03 जून–09 जून 2013

सलीम खान बॉलीवुड केस्क्रिप्ट राइटर हैं. उन्होंने शुरू शुरू में शम्मी कपूर के साथ कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया.

परिवारवाद से दूर नहीं बॉलीवुड?

प्रियंका तिवारी feedback@chauthiduniya.com

वैसे तो परिवारवाद हर क्षेत्र में है, लेकिन भारत की राजनीति और फिल्मों में परिवारवाद का काफी बोलबाला है. फिल्म इंडस्ट्री दरअसल, रचनात्मकता का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब यह क्षेत्र भी परिवारवाद से दूर नहीं है. एक तरफ देश की राजनीति कुछ परिवारों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जैसे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, पटनायक, अब्दुल्ला, पायलट, संगमा जैसे राजनेता परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फिल्मों में कपूर, कुमार, बच्चन, भट्ट, चोपड़ा, जौहर और खान पीढ़ी दर पीढ़ी इस विरासत को बखूबी संभाल रहे हैं. कौन हैं वे खानदानी लोग, आइए जानते हैं...

बॉलीवुड में राज करने वाले कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इंडस्ट्री में राज करते आ रहे हैं. कपूर खानदान का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह परिवार इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों से ही अस्तित्व में है. परिवार के मुखिया पृथ्वीराज कपूर ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री में क़दम रखा. वे न केवल एक अभिनेता, बल्कि निर्देशक और निर्माता भी थे. बाद में उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई. राजकपूर भी अपने पिता की तरह अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे. उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया. नेहरूवादी सामाजिक विचारधारा से प्रभावित राजकपूर ने प्रेम कहानियों को मादक ढंग से पर्दे पर पेश किया, जिसे बाद के निर्देशकों ने भी अपनाया. दरअसल, उनकी फिल्में असल जिंदगी से जुड़ी होती थीं और अपनी ज्यादातर फिल्मों के मुख्य नायक वे खुद होते थे. वह चार्ली चैपलिन से काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए उनकी अभिनय में चार्ली चैपलिन का काफी प्रभाव होता था.

राजकपूर के दो भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर भी अच्छे अभिनेता साबित हुए. शम्मी कपूर ने अभिनेत्री गीता बाली से तो, शशि कपूर ने ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से शादी की. आगे चलकर राजकपूर के बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर ने अपना खानदानी विरासत संभाला. हालांकि राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने कुछ अच्छी फिल्में ज़रूर की, लेकिन वह सफल नहीं हुए. उन्होंने अभिनेत्री बबीता से शादी की. राज कपूर के बाक़ी दोनों बेटों में ऋषि कपूर और राजीव कपूर में ऋषि की बाल सुलभ अभिनय को सभी ने खूब पसंद किया. ऋषि की शादी अभिनेत्री नीतू सिंह से हुई. वहीं उनके तीसरे बेटे राजीव कपूर ने कुल 13 फिल्मों में अभिनय किया. राज कपूर निर्देशित उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली रही. राजीव कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म प्रेमग्रंथ उनकी एकमात्र हिट फिल्म थी.

शशि कपूर के तीन बच्चे करण, कुणाल और संजना ने भी अभिनय में हाथ आजमाया, लेकिन वे अंतत: सफल नहीं हो पाए. संजना कपूर आजकल पृथ्वी थिएटर की बागडोर संभाल रही हैं. हालांकि कपूर खानदान में लड़कियों का फिल्मों में आने पर प्रतिबंध था, लेकिन इस परंपरा को रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा ने तोड़ा. वह अपने समय की अच्छी अभिनेत्री थीं. बाद में उस परिवार की दूसरी बेटी करीना भी बेहतरीन अभिनेत्री साबित हुईं. इन दिनों ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर बॉलीवुड में छाए हुए हैं.

जावेद अख्तर और आजमी परिवार भी बॉलीवुड में काफ़ी समय से सक्रिय हैं. गीतकार जावेद अख्तर की शादी पहले हनी इरानी से हुई थी. उनके दो बच्चे हैं जोया और फरहान. जावेद अख्तर के पिता जानेसार अख्तर इंडस्ट्री का जाना माना नाम था. वहीं जावेद अख्तर की पत्नी की बहन डेजी इरानी भी फिल्म अभिनेत्री हैं. बॉलीवुड के मशहूर आइकॉन फराह खान और साजिद खान हनी इरानी और डेजी इरानी के भांजा-भांजी हैं. यहां यह भी बता दें कि जावेद और डेजी की शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई. डेजी से अलग होने के बाद उन्होंने शबाना आजमी से शादी की. शबाना आजमी की भांजी फरहा और तब्बू भी अभिनेत्री हैं. फरहा ने बालीवुड में कुछ ही फिल्में की, लेकिन उनकी बहन तब्बू ज्यादा सफल रहीं और वह आज बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ को कौन नहीं जानता, लेकिन उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था. दरअसल, उन्होंने खुद मेहनत कर के अपनी पहचान बनाई. बाद में अभिनेत्री जया भादुरी के प्रेम में पड़ गए. शहंशाह और जया की शादी हो

बॉलीवुड में राज करने वाले कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इंडस्ट्री में राज करते आ रहे हैं. कपूर खानदान का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह परिवार इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों से ही अस्तित्व में है.

गई. उनके इकलौते बेटे अभिषेक ने भी पिता के रास्ते पर चलते हुए फिल्म को ही करियर के रूप में चुना. हालांकि सिर पर पिता का हाथ होने के बाद भी अभिषेक कुछ खास नहीं कर सके. और तो और, अपने बेटे के करियर ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए पिता अमिताभ ने उनके साथ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी. अभिषेक ने अंतत: अभिनेत्री ऐश्वर्या से शादी कर ली.

भट्ट कैंप में आपको अभिनेता, अभिनेत्री एवं निर्माता और निर्देशक सभी मिल जाएंगे. महेश और मुकेश भट्ट के पिता नानाभाई भट्ट फिल्म निर्देशक थे. महेश भट्ट और किरण भट्ट की बेटी पूजा भट्ट अपने समय की अच्छी अभिनेत्री थीं, अब वह निर्देशन में उतर गई हैं. वहीं महेश भट्ट की दूसरी पत्नी सोनी राजदान अभिनेत्री हैं और अब उन दोनों की बेटी आलिया ने भी फिल्मों में कदम रख दिया है. यही नहीं, अभिनेता इमरान हाशमी भी महेश भट्ट के भांजे हैं. वहीं बॉलीवुड डायरेक्टर मोहित सूरी और विजय भट्ट भी महेश भट्ट के भांजे हैं. विजय भट्ट के भतीजे विक्रम भट्ट भी निर्देशक हैं. बॉलीवुड की एक और फैमिली देओल्स भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं. धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में कदम रखा और खूब नाम और शोहरत कमाया, तो उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी भी पिता के रास्ते पर चल पड़े. धर्मेंद्र ने ऐक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी की. उनकी बेटी ऐशा देओल ने भी फिल्मों में अपनी किस्तम आजमाई. अभिनेता अभय देओल भी सनी के भतीजे हैं. वहीं सनी के बेटे करण देओल भी जल्द ही फिल्मों एंट्री करने वाले हैं. आमिर खान के परिवार की जड़ें बॉलीवुड में काफ़ी गहरी हैं. उनका परिवार मोशन पिक्चर्स में काफी समय से सक्रिय रहा. उनके पिता ताहिर हुसैन फिल्म निर्माता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे. चाचा नासिर हुसैन एक फिल्म निर्माता होने के साथ ही निर्देशक भी थे. आमिर के भाई फैजल ने न केवल कुछ फिल्मों में अभिनय किया, बल्कि कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया, लेकिन सफल नहीं हो सके. आमिर ने दूसरी शादी किरण राव से की. किरण डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं. उन्होंने स्वतंत्र रूप से फिल्मों का निर्माण भी किया है.

चोपड़ा-जौहर परिवार फिल्म जगत से एक अरसे से जुड़े हुए हैं. बलदेव राज चोपड़ा ने बीआर फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का निर्माण किया, जिसे आजकल निर्देशक रवि चोपड़ा देख रहे हैं. बलदेव राज के छोटे भाई यश राज फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती हैं. हर अभिनेता और अभिनेत्री का यही सपना होता है कि वह यशराज प्रोडक्शन के साथ काम करे. यश के बेटे आदित्य चोपड़ा अब अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं. वहीं यश चोपड़ा के भाई विनोद चोपड़ा ने भी अपने बेटे विधु विनोद चोपड़ा के साथ परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया. विधु विनोद चोपड़ा की बहन की शादी यश जौहर से हुई है. यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन का निर्माण किया. इसे आजकल यश जौहर के बेटे करण जौहर देख रहे हैं.

सलीम खान बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर हैं. उन्होंने शुरू शुरू में शम्मी कपूर के साथ कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया. उनकी अंतिम फिल्म है तीसरी मंजिल. उनके तीन बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल खान हैं. सलीम ने दूसरी शादी डांसर हेलेन से की. उनके पुत्रों में सबसे बड़े सलमान बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, जबकि बाकी दोनों भाई फिल्मों में अभिनय करने के साथ ही परदे के पीछे प्रोडक्शन और निर्देशन का काम संभाल रहे हैं. उन्होंने कई अच्छी फिल्में भी दी हैं. वहीं सलमान की बहन अलवीरा के पति अतुल अग्निहोत्री भी अभिनय के क्षेत्र में कुछ ख़ास सफलता नहीं मिलने के कारण अब फिल्म निर्माण में लग गए हैं. सलीम के बेटे अरबाज ने अभिनेत्री और डांसर मलाइका अरोड़ा से शादी की. अभिनेत्री अमृता अरोड़ा मलाइका की बहन हैं. सच तो यह है कि इस परिवार में कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक और आइटम गर्ल सभी हैं.

मुखर्जी परिवार में कई अच्छी अभिनेत्रियां भी हुई हैं. रतन बाई अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रहीं. उनकी बेटी शोभना समर्थ भी एक बेहतरीन अभिनेत्री थीं. शोभना समर्थ की दो बेटियां नूतन और तनुजा भी मशहूर अभिनेत्रियां रहीं. नूतन के बेटे मोहनीश बहल अभिनेता हैं, वहीं तनुजा की दो बेटियां काजोल और तनीशा ने भी अभिनय में किस्मत आजमाई. काजोल एक जानी पहचानी अदाकारा हैं, जबकि तनीशा कुछ ख़ास नहीं कर पाईं. अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी काजोल की कजन सिस्टर हैं. रानी की बहन शर्बानी ने भी कुछ फिल्मों में काम किया. रानी का नाम यशराज चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ जोड़ा जाता है. वहीं काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से शादी की. अजय भी फिल्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता बॉलीवुड में स्टंटमैन थे, वहीं उनकी मां वीना देवगन ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था. बॉलीवुड में एक और कपूर फैमिली है, प्रोड्यूसर सुरिंद्र कपूर. इनके तीन बेटे हैं बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर तीनों ही बॉलीवुड में काम कर रहे हैं. बोनी कपूर ने अभिनेत्री श्रीदेवी से शादी की है. श्रीदेवी और बोनी की बेटी जाह्नवी को जल्द ही बॉलीवुड में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. वहीं अनिल कपूर की दोनों बेटियां भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं. उनकी बेटी सोनम अभिनेत्री हैं, वहीं उनकी दूसरी बेटी रिया प्रोड्यूसर हैं. बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना के बेटे अर्जुन ने फिल्म निर्माण भी किया है और अब अभिनय भी कर रहे हैं.

इन परिवारों के अलावा, कई और परिवार हैं, जो कई पीढ़ियों से बॉलीवुड में राज कर रही हैं. इनमें आनंद, बड़जात्या, दत्त, खन्ना, चोपड़ा, सेन, ओबेराय खानदान शामिल हैं. अगर सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे, तो इसे कबूल करने में हमें दिक्कत ही नहीं होगी कि बॉलीवुड में भी खानदानी विरासत की परंपरा पिछले 70 साल से चली आ रही है. और आगे भी चलती रहेगी. ■

रति से लोग डरते हैं!

रति पांडेय, यानी छोटे परदे की हिटलर दीदी. रति पांडेय टेलीविजन दुनिया का जाना पहचाना नाम है. उन्हें कामयाबी मिली शोप ओपेरा मिले जब हम तुम से. इन दिनों वह जीटीवी पर चांदनी चौक की हिटलर दीदी के रोल में दिख रही हैं. उनका जन्म असम में हुआ था. जन्म के सात साल बाद उनका परिवार पटना चला गया. उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है. एक यात्रा के दौरान उन पर निर्देशक अजय सिंह की नज़र पड़ी. अजय ने उन्हें एक शो शादी स्ट्रीट में नंदिनी के रोल के लिए चुन लिया, लेकिन दुर्भाग्य से यह शो पूरा नहीं हो पाया. रति बताती हैं कि मैं पहले हमेशा सोचती थी कि मैं किसी बॉस के अंडर में काम नहीं करूंगी. दरअसल, बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं पायलट बनूं. साइंटिस्ट तो मैं बन नहीं सकती थी, क्योंकि मैथ्स और साइंस में मुझे कम इंटरेस्ट था. इन विषयों में मार्क्स काफी कम आते थे. मेरी रुची शुरू से आर्ट्स में थी. मैं स्कूल और कॉलेज के दिनों में डांस शो और इवेंट्स ऑर्गनाइज करती थी. उन दिनों फिल्म काई पो चे फेम सुशांत सिंह राजपूत की बहन मेरी क्लासमेट थी. दरअसल, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और हम दोनों खूब मस्ती करते थे. यही वजह है कि आज मैं यहां हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अभिनेत्री बनूंगी. जब मेरे पास हिटलर दीदी के रोल का ऑफर आया, तो मैंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह लीड रोल था, जो एक महिला पात्र पर आधारित था. इसमें मेरा रोल सीरियस तरह के किरदार का है, जबकि मैं असल जीवन में हंसती मुस्कराती रहती हूं. हालांकि कुछ ही दिनों में मैंने इस रोल के साथ तारतम्यता बैठा ली थी. सच तो यह है कि लोग असल जीवन में भी मुझसे अब डरते हैं.

एडरॉल मनो चिकित्सा संबंधी एक शक्तिवर्धक दवा है और उस दवा के कारण 26 वर्षीय लोहान का वजन लगभग पांच पाउंड बढ़ गया है. हालांकि वह फिट रहने के लिए लगातार व्यायाम भी कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका वेट बढ़ ही रहा है.

परेशानियां पीछा नहीं छोड़तीं

अभिनेत्री लिंडसे लोहान ने मात्र तीन साल की उम्र से एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने शुरुआत में फोर्ड, केवीन क्लीन, पिज्जा हट के लिए मॉडलिंग की. जब बड़ी हुईं, तो उनका भविष्य काफी उज्ज्वल रहा, लेकिन बाद में अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर अक्सर ही वह मीडिया की सुर्खियों में बनी रहीं. उनके दोस्तों का कहना है कि लिंडसे के जीवन से परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. दरअसल, आजकल वह परेशान हैं अपने बढ़ते वजन के कारण. इन दिनों लोहान का इलाज चल रहा है. उन्हें दिए जाने वाली दवाओं की सूची में से एडेरॉल नाम की दवा जब से हटा दी गई, तब से उनका वजन लगातार बढ़ रहा है.

गौरतलब है कि एडेरॉल मनो चिकित्सा संबंधी एक शक्तिवर्धक दवा है और उस दवा के कारण 26 वर्षीय लोहान का वजन लगभग पांच पाउंड बढ़ गया है. हालांकि वह फिट रहने के लिए लगातार व्यायाम भी कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका वेट बढ़ ही रहा है. इससे पहले वर्ष 2004, 2005 और 2006 में कई बार उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए और उन्हें चोटें भी आईं.

18 जनवरी, 2007 को लोहान वंडरलैंड सेंटर पुनर्वास में भर्ती हुईं. तब उन्होंने बयान जारी किया था कि अपनी सेहत का खयाल रखने का उन्होंने निर्णय लिया है. वहां से आने के कुछ ही समय बाद नशे की हालत में गाड़ी चला कर उन्होंने एक्सीडेंट कर लिया. दो दिनों बाद लिंडसे प्रोमिसेज ट्रीटमेंट सेंटर में दाखिल हुईं, जहां उन्होंने 45 दिन बिताए. उनके करीबी लोगों का कहना है कि लिंडसे एक बहुत ही इमोशनल और खुशमिजाज इंसान हैं, लेकिन भावानात्मक रूप से वह काफी कमजोर हैं. ■

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

03 जून–09 जून 2013

www.chauthiduniya.com

सारण का चितौड़गढ़

फ़तह की लड़ाई ?

लालू प्रसाद अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि केवल राजपूत, यादव और मुसलमान वोटरों से काम नहीं चलेगा. इसलिए हरसंभव कोशिश की जा रही है कि हर हालत में भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों को भी रिझाया जाए. जानकार बताते हैं कि इन्हीं वोटों पर महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट तय होगा. लेकिन कैसे ?

सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

सारण का चितौड़गढ़, यानी महाराजगंज लोकसभा में जीत का परचम लहराने के लिए मैदान तैयार है और सेनाएं सज चुकी हैं. एक तरफ़ सत्ता के रथ पर सवार जदयू प्रत्याशी पीके शाही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ़ उन्हें ललकारने में लगे हैं, राजद के प्रभुनाथ सिंह. कांग्रेस के जितेंद्र स्वामी तीसरा कोण बनाने की कोशिश में हैं. जिस दिन महाराजगंज उपचुनाव का ऐलान हुआ, उसी दिन यह साफ़ हो गया कि प्रभुनाथ सिंह को केवल पीके शाही से नहीं, बल्कि पूरी नीतीश सरकार से लड़ाई लड़नी है. इसलिए प्रभुनाथ सिंह ने भी बिना समय गवाए यह ऐलान कर दिया कि वह मर्द की तरह चुनाव लड़ेंगे और यहां की जनता भारी मतों से उन्हें जीता कर दिल्ली भेजेगी. उधर, पीके शाही भी यही दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के विकास का जादू यहां सिर चढ़ कर बोलेगा और यहां की जनता जात-पात और धर्म-संप्रदाय से आगे बढ़कर मजबूत बिहार के लिए वोट करेगी. जितेंद्र स्वामी को अपने पिता स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के नाम का भरोसा है. लोकसभा चुनाव की आहट के बीच शायद यह उपचुनाव जनता का मिजाज भांपने का सबसे अच्छा ज़रिया नेताओं को लग रहा है. इसलिए यह उपचुनाव एक सामान्य चुनाव न होकर हर एक दल और हर एक नेता के लिए एक तरह से जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है. हर दल यहां जीत दर्ज करा के यह संदेश देना चाहती है कि जनता उसके साथ है और जब भी लोकसभा के चुनाव हुए, तो जनता उनके दल के प्रत्याशी को ही विजयमाला पहनाएगी. इस नज़रिए से यह उपचुनाव बहुत ही ख़ास है. लगभग ढाई लाख राजपूत मतदाता वाले क्षेत्र से भूमिहार प्रत्याशी पीके शाही को उतार कर नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला है. भूमिहार मतदाताओं की संख्या यहां लगभग सवा लाख बताई जा रही है. यादव और मुसलमान मतदाता यहां डेढ़-डेढ़ लाख और ब्राह्मण लगभग एक लाख हैं. अतिपिछड़ा वोटों की संख्या यहां बहुत है. बदली हुई दलीय स्थिति में अगर प्रभुनाथ सिंह को यादव और मुसलमान वोटों का थोक में फ़ायदा होता दिख रहा है, तो वही दूसरी ओर पीके शाही को भूमिहार और ब्राह्मण वोटों का फ़ायदा हो रहा है. गौरतलब है कि पिछले चुनाव में प्रभुनाथ सिंह जदयू में थे, तो उमाशंकर सिंह राजद में थे. कांग्रेस से तब तारकेश्वर सिंह ने चुनाव लड़ा था. इस समय कांटे की लड़ाई में प्रभुनाथ सिंह मामूली वोट से हार गए थे, लेकिन तब से अब तक महाराजगंज में हालात काफ़ी बदल गए हैं. उमाशंकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे तथा प्रभुनाथ सिंह राजद में आ चुके हैं. जितेंद्र स्वामी ने कांग्रेस का झंडा थाम लिया है. महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को समझने वाले जानकार बताते हैं कि आख़िरी चरण में यह लड़ाई जदयू और राजद के बीच रह जाएगी. पीके शाही ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है और इस लिहाज से यह उनका पहला चुनाव है, जबकि प्रभुनाथ सिंह यहां से तीन बार सांसद रह चुके हैं. महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बनावट पर गौर करें, तो इस लोकसभा क्षेत्र में तरैया, बनियापुर, मांझी, एकमा, महाराजगंज और गोरेयाकोठी छह विधान सभा क्षेत्र हैं. चार विधायक राजपूत हैं, जबकि दो भूमिहार हैं. वहीं तीन विधानसभा क्षेत्र मांझी, महाराजगंज और एकमा जेडीयू के पास है, जबकि तरैया और गोरैयाकोठी बीजेपी और बनियापुर राजद के क़ब्ज़े में है. वर्तमान में बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके अनुज केदारनाथ सिंह राजद के विधायक हैं.

वैसे महाराजगंज का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है, क्योंकि यह समाजवादियों का गढ़ रहा है. इस क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक बार और भारत सरकार के पूर्व मंत्री रामबहादुर सिंह ने दो बार प्रतिनिधित्व किया है. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. यहां वर्ष 1971 एवं 1977 को छोड़कर 1952 से 1985 तक संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया है. वर्ष 1952 एवं 1957 में महेंद्र नाथ सिंह, 1962 में कृष्णकांत सिंह, 1967 में मृत्युंजय प्रसाद सिन्हा, 1980 एवं 1985 में कृष्ण प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी. वहीं वर्ष 1971 में संसोपा के रामदेव सिंह ने जीत दर्ज कर कांग्रेस लहर को समाप्त किया था. यहीं नहीं उन्होंने जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वर्ष 1977 में भी जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार पताका फहराया था, लेकिन 1980 एवं 1985 के चुनाव में कांग्रेस के कृष्ण प्रताप सिंह इस जीत को रोकने में सफ़ल हो गए. महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए, तो यहां संपन्न हुए चुनाव में वर्ष 1967 में कायस्थ उम्मीदवार मृत्युंजय प्रसाद सिन्हा को छोड़कर सदैव भूमिहार एवं राजपूत जाति के प्रत्याशियों की ही जीत दर्ज हुई है. 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के उम्मीदवार चंद्रशेखर इस सीट से चुनाव जीते थे.

वहीं 1990 के उपचुनाव में इसी दल के रामबहादुर सिंह विजयी हुए थे, जबकि 1991 के चुनाव में जनता दल की प्रत्याशी गिरिजा देवी जीती थीं. 1996 के चुनाव में पुन: रामबहादुर सिंह जीत दर्ज करने में सफल हो गए. वर्ष 1998 से 2004 तक जदयू के प्रभुनाथ सिंह की लगातार जीत हुई, जिसमें समता पार्टी के टिकट पर 1998 एवं 1999 में प्रभुनाथ सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह को पराजित किया था, जबकि 2004 में जदयू प्रत्याशी के रूप में प्रभुनाथ सिंह ने महाराजगंज के पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र एवं राजद के जितेंद्र स्वामी को 46464 मतों से हराया था. फिर वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में राजद के उमाशंकर सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया. इस लिहाज से यह सीट राजद की है और यही वजह है कि लालू प्रसाद ने यहां पार्टी की जीत बरक़रार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. यादव और मुसलमान वोटरों का स्वाभाविक झुकाव प्रभुनाथ सिंह के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यह अच्छी तरह जानते हैं कि केवल राजपूत, यादव और मुसलमान वोटरों से काम नहीं चलेगा. इसलिए हरसंभव कोशिश हो रही है कि किसी भी हालत में भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों को रिझाया जाए. जानकार भी बताते हैं कि इन्हीं वोटों पर महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट तय होगा. चूंकि प्रभुनाथ सिंह को अगर यादवों और मुसलमानों के अतिरिक्त वोटों का फ़ायदा हो सकता है, तो इस अंतर को अतिपिछड़ा वोटों से जदयू आसानी से कम कर सकता है. इसलिए असली लड़ाई भूमिहार और ब्राह्मण वोटों को लेकर ही हो रही है. लालू प्रसाद के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि बह्मेश्वर मुखिया के पुत्र इंदूभूषण सिंह इस चुनाव में जनता से यह पूछने वाले हैं कि आख़िर मुखिया जी की हत्या के लिए कौन ज़िम्मेदार है? वह यह भी सवाल करेंगे कि पीके शाही ने भूमिहार समाज के लिए अब तक क्या किया है? अगर मुखिया जी के पुत्र इस चुनाव को लेकर गंभीर हो गए, तो तय है कि भूमिहार समाज के वोटों में बंटवारा हो जाएगा. इस स्थिति को जदयू के रणनीतिकार किसी भी क़ीमत पर टालना चाहते हैं. नाराज़ चल रहे सांसद ललन सिंह और नीतीश कुमार एक मंच पर लखी सराय में दिखाई दिए. इसे डैमेज को कम करने की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है. ब्राह्मणों में फूट न हो, इसके लिए जदयू ने इस बिरादरी के नेताओं की बड़ी फौज मैदान में उतारी है. इस सब के बीच यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भाजपाई यहां जदयू को ज़मीनी स्तर पर कितना सहयोग करते हैं. चूंकि बिना इस मदद के सारण के चितौड़गढ़ पर क़ब्ज़ा करने की जदयू की ख्वाहिश पूरा होना बहुत मुश्किल है. ■

– साथ में चंद्र प्रकाश राज

ललन कांटा बोएंगे या निकालेंगे!

ललन सिंह और नीतीश कुमार तीन साल बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एकसाथ दिखें. तीन साल के इस वनवास को ललन सिंह ने ग़लतफ़हमी का परिणाम बताया, तो वहीं नीतीश कुमार ने यह कहा कि घर के लोग कितने दिन रूठ कर अलग रहेंगे. ललन सिंह ने भरी सभा में बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने नीतीश कुमार की ईमानदारी और उनकी कर्मठता पर कभी भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया. मैंने तो हमेशा उनकी राहों में आने वाले कांटे को हटाया है. कुछ ग़लतफ़हमियां हो गई थीं, लेकिन आगे यह नहीं होगा. जो कांटे नीतीश कुमार के रास्ते में आएंगे, उसे हटाने का प्रयास मैं करूंगा. हालांकि लेकिन ललन सिंह के इतना कह देने से बात ख़त्म नहीं हो गई. माना जा रहा है कि आज जदयू के अंदर वे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जो तीन साल से ललन सिंह को बुरा-भला कह रहे थे. ऐसे नेताओं को लग रहा है कि ललन सिंह पार्टी में फिर एक बार अपनी पुरानी हैसियत में आ गए, तो उनका क्या होगा.

सवाल यह है कि ललन सिंह ने किसान महापंचायत में जो सवाल उठाए थे, इसका जवाब क्या है? मसलन भूमि सुधार बिल, भ्रष्टाचार और निरंकुश अफसरशाही. इसके अलावा, ललन सिंह के वापस आने से उन नेताओं को ख़ासी मायूसी हाथ लगी है, जो मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना

देख रहे थे. पीके शाही और विजय कुमार चौधरी सरीखे नेताओं की अब पार्टी और सरकार में क्या हैसियत रहेगी, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादा परेशान जदयू के कुछ पिछड़े और अतिपिछड़े नेता हैं, जो कि ललन सिंह के वापस आने को सही क़दम नहीं मान रहे हैं. उनकी राय है कि ललन सिंह के जाने के बाद पिछड़ों और अतिपिछड़ों में एक सकारात्मक संदेश गया था, लेकिन इस नए घटनाक्रम से हालात बदल जाने की उम्मीद है. उन्हें इस बात की संभावना काफ़ी कम लग रही है कि ललन सिंह भूमिहारों का कुछ वोट पार्टी को दिला पाएंगे. उनका यह भी मानना है कि ललन सिंह की लोकसभा टिकट मिलना ज़रूर पक्का हो गया.

जानकारों का मानना है कि ललन सिंह के पास वापस लौटने के अलावा, कोई और विकल्प नहीं था. दिग्विजय सिंह के निधन के बाद नीतीश विरोध का आंदोलन काफ़ी ठंडा पड़ गया था. किसान महापंचायत में जुटे नेता बिखर गए थे. वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को अपनी ज़मीनी हैसियत का भी अंदाज़ा हो गया. कोई नया विकल्प न बनता देख ललन सिंह के लिए कोई और रास्ता नहीं था. लोकसभा में मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए नीतीश कुमार का हाथ थामना ललन सिंह की मजबूरी हो गई थी. दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार को भी दिल्ली की राजनीति को चमकाने के लिए ललन सिंह की दरक़ार थी. इधर, दो सालों में कांग्रेस के बड़े नेताओं से ललन सिंह ने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं. इसलिए नीतीश कुमार को लगता है कि चुनाव से पहले या बाद में ललन सिंह दिल्ली की राजनीति में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर भाजपा से रिश्ता टूटा, तो नए राजनीतिक समीकरण में गुणा भाग करने में ललन सिंह कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है. जदयू के कुछ नेता बताते हैं कि ललन सिंह ने चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार को क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी उनके लिए दरियादिली दिखाई गई. इससे क्या पार्टी में अनुशासनहीनता को बढ़ावा नहीं मिलेगा? ललन सिंह अगर सही हैं, तो फिर प्रेम कुमार मणि, रामजीवन सिंह, पीके सिन्हा, शंभू श्रीवास्तव, उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु आदि नेताओं का क्या कसूर है. इसलिए कहीं ऐसा न हो कि ललन सिंह नीतीश कुमार की राह में आने वाले कांटे को निकालें कम, बोएं ज़्यादा. ■

आरोप तो यह भी है कि नियोजन पत्र वितरण के दिन भी जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नियोजन संचिका में हेर-फेर किया जा रहा था.

» एक नज़र «

नहीं रहीं, अन्ना की सिपाही

अन्ना हजारे की समर्थक और बिहार में अन्ना आंदोलन को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाने वाली अर्चना अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उनके अचानक निधन से अन्ना के सहयोगी एवं सामाजिक संगठनों के लोग हतप्रभ हैं. पटना में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में संजय सिसोदिया, राधेश्याम यादव, ममता पांडेय सुषमा जी, हरि कुमार, अभय कुमार, राजू, राम उदय सिंह, चंद्रभूषण, आनंद, महबूब आलम अंसारी, आलोक कुमार, सुधा सिंह राठौर समेत कुछ और वरिष्ठ नागरिक हैं.

श्रीराम कथा का समापन

जगत जननी मां जानकी की पावन प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा का समापन जानकी नौमी को हो गया. नौ दिनों तक पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य श्रीरामभद्राचार्य ने हज़ारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को कथामृत का पान कराया. इस दौरान उन्होंने सीता जन्मस्थली को संपूर्ण संसार में अद्वितीय स्थान की संज्ञा दी. जगतगुरु ने ऐतिहासिक सीता कुंड की रक्षा के लिए आम लोगों से अपील करते हुए यह कहा कि कुंड के पानी से असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति महज चंद दिनों में ही रोग मुक्त हो सकते हैं. कथा समापन के मौक़े पर बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल, कथा यज्ञ के यजमान जानकी नंदन पांडेय, पूर्व सांसद नवल किशोर राय एवं मंजू देवी समेत हजारों श्रद्धालू मौजूद थे.

प्रेक्षागृह का शिलान्यास

सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी नौमी के पावन अवसर पर भव्य सीता प्रेक्षागृह के निर्माण का शिलान्यास किया गया. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अवसर पर जगतगुरु रामानंदाचार्य श्रीरामभद्राचार्य, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल, पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू, जदयू विधायक गुड्डी देवी, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, डीएम डॉ. प्रतिमा, जदयू नेता राजेश चौधरी समेत कुछ और लोग भी मौजूद थे. तक़रीबन पौने 3 करोड़ की लागत से होने वाले इस निर्माण के शिलान्यास के मौक़े पर जगतगुरु ने बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू को बधाई दी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने की दिशा में पहल की जानी चाहिए, ताकि अगले साल कथा पंडाल की बजाए नव निर्मित प्रेक्षागृह में कथा संभव हो सके.

मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन

सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित ऐतिहासिक सीता कुंड के पश्चिमी भाग में बालरूप सीता मंदिर निर्माण को लेकर जानकी नौमी को जगतगुरु ने शिला पूजन की. वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न कार्यक्रम में मंदिर के महंत कौशल किशोर दास, कथा यज्ञ के यजमान जानकी नंदन पांडेय, जदयू विधायक गुड्डी देवी, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, राजेश चौधरी, कामेश्वर प्रसाद सिंह, राधे श्याम मिश्रा, मनोज कुमार सिंह, नागेंद्र प्रसाद, दिनेशचंद्र द्विवेदी, त्रिपुरारी प्रसाद सिंह और धनुशधारी सिंह के अलावा, कई अन्य थे. विधिवत शिलापूजन के उपरांत तत्काल दर्जनों श्रद्धालु मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग को लेकर आगे आए. नतीजतन महज चंद मिनटों में क़रीब 10 लाख रुपये से अधिक की राशि निर्माण कार्य के लिए दिए जाने की घोषणा कर दी गई. मौक़े पर जगतगुरु ने भरोसा दिलाया कि कुल प्राप्त राशि का दो गुणा वे अपनी ओर से मंदिर निर्माण कार्य में देंगे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया

डीएम के ख़िलाफ़ आंदोलन की धमकी दी

ज़िला परिषद शिक्षक नियोजन को लेकर नियोजन पत्र वितरण के अंतिम दिन भी दर्जनों अभ्यर्थियों को निराश लौटना पड़ा, जबकि चंद दिन पहले ही अभ्यर्थियों ने डीएम से अनियमितता की शिकायत की थी. अभ्यर्थी संगीता कुमारी, पंकज बिहारी, आभाष रंजन, जितेंद्र, प्रेमानंद भारती, दिनेश कुमार एवं अभिषेक रंजन ने बताया कि अधिकारियों की मनमानी के कारण अंतिम दिन भी नियोजन पत्र वितरित नहीं किया गया. अगर इसी प्रकार लापरवाही बरती गई तो शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.

मनेंद्र कुमार feedback@chauthiduniya.com

शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर सैकड़ों युवक नियोजन को लेकर खगड़िया में कई महीनों से परेशान हैं. कभी अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा धरना-प्रदर्शन दिया जाता है, तो कभी प्रशिक्षित अभ्यर्थी की बहाली में अनियमितता की शिकायत की जाती है. इन सारे कारनामों पर सरकार सिर्फ़ शिकायत सुन रही है, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति के वायदे यहां अब तक खोखले साबित हुए हैं. आरोप तो यह भी है कि नियोजन पत्र वितरण के दिन भी जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नियोजन संचिका में हेर-फेर किया जा रहा था. ज़िला परिषद शिक्षक नियोजन को लेकर नियोजन पत्र वितरण के अंतिम दिन भी दर्जनों अभ्यर्थियों को निराश लौटना पड़ा, जबकि चंद दिन पहले ही अभ्यर्थियों ने डीएम से अनियमितता की शिकायत की थी. अभ्यर्थी संगीता कुमारी, पंकज बिहारी, आभाष रंजन, जितेंद्र, प्रेमानंद भारती, दिनेश कुमार एवं अभिषेक रंजन ने बताया कि अधिकारियों की मनमानी के कारण अंतिम दिन भी नियोजन पत्र वितरित नहीं किया गया. अगर इसी प्रकार लापरवाही बरती गई तो शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.

ज़िला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव 13 मई को नियोजन पत्र वितरण को लेकर जब ज़िला परिषद कार्यालय पहुंची, तो दर्जनों अभ्यर्थी नियोजन पत्र लेने के लिए वहां जमा थे, लेकिन कार्यालय में कोई भी नहीं था. अध्यक्ष ने जब संचिका खोजी, तो पता चला कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कर्मी सुरेंद्र कुमार फाइल लेकर समाहरणालय गया है. उन्होंने डिस्पैच फाइल मांगी, जो नहीं मिली. इस पर मामला काफ़ी गर्म होने लगा. ठीक इसके बाद सदर विधायक पूनम देवी यादव एवं पूर्व विधायक रणवीर यादव ज़िला पंचायत कार्यालय पहुंचे, तो स्थिति देखकर भौंचक्के रह गए. सभी जनप्रतिनिधि आनन-फानन में समाहरणालय पहुंच गए. उस समय डीएम के कक्ष में वरीय उपसमाहर्ता आनंद प्रकाश, ज़िला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू राम, पंचायती राज पदाधिकारी सियाराम सिंह सहित कई पदाधिकारी बैठक कर रहे थे, लेकिन उक्त जनप्रतिनिधि के पहुंचते ही नियोजन पत्र की संचिका मांगने को लेकर बहस छिड़ गई. दरअसल, यह बात पदाधिकारी को नागवार गुजरी, इससे स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बन गई. कुछ देर बाद डीडीसी सुरेश चौधरी और डीएम सैयद परवेज आलम ने मामले को शांत करवाया तथा नियोजन पत्र की संचिका ज़िला पंचायत अध्यक्ष को वापस लौटा दी गई. इसके बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन इस तू-तू-मैं-मैं की स्थिति में लोगों की भीड़ जमा हो गई. बहरहाल, इस मामले को ज़िला प्रशासन अपनी ओर से दबा रहा है तथा इस सवाल को लेकर प्रशासन बोलने से कतरा भी रहा है.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आख़िर नियम के ख़िलाफ़ क्यों डीएम के यहां फाइल भेजी गई, जबकि नियमानुसार ज़िला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी होते हैं. इस कारण डीडीसी को यह अधिकार है कि नियोजन से संबंधित संचिका की वह जांच करें. इस मामले में डीएम को आधिकारिक रूप से संचिका को अपने पास लाने के लिए लिखित आदेश देना होता है, जो नहीं दिया गया. ज़िला पंचायत अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव का कहना है कि बिना मुझे किसी तरह की सूचना दिए ज़िला परिषद कार्यालय से संचिका बाहर भिजवा दी गई. संचिका में सूची पूरी तरह तैयार थी, फिर किस मंशा से उसे लाया गया था, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वितरण के दिन डीएम के निर्देश पर चोरी से और फ़र्ज़ी तरीक़े से संचिका में हेर-फेर किया जा रहा था, जो डीएम के अधिकार में नहीं था.

वहीं दूसरी ओर यादव ने कहा कि वरीय उपसमाहर्ता आनंद प्रकाश एवं ज़िला पंचायती राज पदाधिकरी सियाराम सिंह नियोजन इकाई के सदस्य नहीं हैं, तो वे सूची में क्यों हेरा-फेरी कर रहे थे. इन सभी पदाधिकारियों की मंशा ग़लत थी, क्योंकि मैं पारदर्शिता के साथ बहाली करना चाहती हूं. उन्होंने कहा कि यदि बासा ने आंदोलन की धमकी दी है, तो हम सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पूरे बिहार में शिक्षा माफिया पदाधिकारी के ख़िलाफ़ आंदोलन करेंगे. वहीं पूर्व विधायक रणवीर यादव ने कहा कि ज़िला परिषद एक ऑटोनॉमस बॉडी है. ऐसे में डीएम फाइल मांगने वाले कौन होते हैं. तमाम घटनाक्रम के आलोक में खगड़िया ज़िला बासा इकाई ने बैठक कर ज़िला पंचायत अध्यक्ष कृष्णा देवी यादव, विधायक पूनम देवी यादव एवं पूर्व विधायक रणवीर यादव द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा डालने और वरीय उपसमाहर्ता आनंद प्रकाश के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण घटना की तीव्र भर्त्सना की है. निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष एवं विधायक द्वारा बुलाई गई किसी प्रकार की बैठक या कार्यक्रम में वे शामिल नहीं होंगे. घटना के मद्देनज़र आनंद प्रकाश को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अविलंब अंगरक्षक बहाल करने तथा सभी पदाधिकारियों को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने की मांग जिलाधिकारी, आयुक्त, केंद्रीय इकाई बासा एवं अध्यक्ष कर्मचारी यूनियन से की है. वहीं बैठक में बासा के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि यदि 15 दिनों के अंदर दोषियों के ख़िलाफ़ विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती है, तो ज़िला इकाई खगड़िया सामूहिक अवकाश पर चली जाएगी. बैठक में डीडीसी सुरेश चौधरी, वरीय उपसमाहर्ता सुशील कुमार, राजेश कुमार, प्रतिभा कुमारी, आनंद प्रकाश, गौतम पासवान, एसडीओ सुशील कुमार, गोगरी एसडीओ जनार्दन कुमार, डीसीएलआर पुष्पेश कुमार, मो. शाहजहां एवं डीटीओ मनोज कुमार उपस्थित थे. उक्त तमाम घटना के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने भी आंदोलन करने की धमकी दी है. इधर, सदर विधायक पूनम देवी यादव का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के अधिकारों का हनन वह किसी भी क़ीमत पर माफ़ नहीं करेंगे. यहां भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध अनवरत जारी रहेगा. इस संबंध में डीएम सैयद परवेज आलम का कहना है कि कार्यालय में हुई घटना की जांच कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.■

किसका चलेगा सिक्का कीर्ति या संजय?

मिथिलांचल की राजनीति में कीर्ति झा आज़ाद एनडीए के सुपरस्टार रहेंगे या फिर भाजपा से जदयू में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ख़ासमख़ास संजय झा के हाथों में राजनीतिक कमान रहेगी. यह वह सवाल है, जो इन दिनों इस इलाक़े में बहस का एक नया मुद्दा बनकर उभरा है. कयास यही लगाया जा रहा है कि इस इलाक़े में आख़िर किसकी चलेगी?

मिथिलांचल

कीर्ति आजाद ने मिथिलावासियों के प्रति मुख्यमंत्री की संजीदगी को ढकोसला क़रार दिया है. उन्होंने आक्रोश में कहा, सच यही है कि मुख्यमंत्री सही मायने में बिहार के सबसे पिछड़े इलाक़े में शामिल मिथिला का विकास नहीं चाहते हैं. अगर उनके मन में इस क्षेत्र के विकास के प्रति संजीदगी होती, तो वह धारा 371 के तहत स्पेशल प्रोविजन में इस इलाक़े को शामिल करा चुके होते. यह विधि सम्मत भी है और आसान भी, लेकिन ऐसा वह नहीं करा रहे.

सरोज सिंह feedback@chauthiduniya.com

कीर्ति झा और संजय झा दोनों ही पहले भाजपा में थे, इसलिए चाहकर भी संजय झा कीर्ति झा के कारण अपनी नहीं चला पा रहे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. नीतीश कुमार का वरदहस्त होने की वजह से मिथिलांचल में उनकी बात काटने की हिम्मत अब किसी में नहीं है. दरअसल, सारा प्रशासनिक अमला यहां संजय झा के इशारों पर काम कर रहा है. बस यही बात कीर्ति झा को पच नहीं रही है. अपने पिता के समय से ही कीर्ति झा का इस इलाक़े में दबदबा रहा है. क्रिकेटर के साथ ही साथ एक नेता के तौर पर भी मिथिलांचल में उनकी एक ख़ास पहचान है, लेकिन संजय झा के सामने आ जाने से मिथिलांचल के सारे समीकरण अब बदल गए हैं. कीर्ति को ख़तरा अपने लोकसभा की टिकट पर भी दिख रहा है. इसलिए पिछले दिनों सेवा यात्रा के दौरान कीर्ति झा आजाद ने जो तेवर दिखाए, वह इसी पृष्ठभूमि में उभरी हताशा का परिणाम कहा जा रहा है. भले ही कीर्ति जन समस्याओं का मामला उठा रहे हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि दरअसल, वह अपनी राजनीतिक पकड़ को इस इलाक़े में किसी भी क़ीमत पर कमजोर होता नहीं देखना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने नीतीश की सेवा यात्रा को हवाई यात्रा कह डाला. संजय झा का इस इलाक़े में बढ़ता क़द उन्हें परेशान कर रहा है. यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इधर एक इशारा करते हैं और उधर बिहार में टकराव शुरू हो जाता है. गुजरात के राजनांद गांव की एक सभा में नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर जमकर वार किए. उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं, जो दावा करते हैं कि वह जनता के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वह जनता के बीच बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं. जनता उनसे वापस लौटने को कहती है और उन पर पत्थर भी फेंके जाते हैं. इधर, नरेंद्र मोदी का भाषण ख़त्म हुआ और उधर दरभंगा से भाजपा सांसद कीर्ति झा आजाद ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि मुख्यमंत्री ने मुझे दरभंगा में समीक्षा बैठक में बोलने ही नहीं दिया. अगर समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं रखेंगे, तो फिर ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि वे अपनी बात कहां रखेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा हेलिकॉप्टर यात्रा बनकर रह गई है. अफसर निरंकुश हो गए हैं और सरकार ज़मीनी सच्चाई देखना ही नहीं चाहती है.

कीर्ति आजाद ने मिथिलावासियों के प्रति मुख्यमंत्री की संजीदगी को ढकोसला क़रार दिया है. उन्होंने आक्रोश में कहा, सच यही है कि मुख्यमंत्री सही मायने में बिहार के सबसे पिछड़े इलाक़े में शामिल मिथिला का विकास नहीं चाहते हैं. अगर उनके मन में इस क्षेत्र के विकास के प्रति संजीदगी होती, तो वह धारा 371 के तहत स्पेशल प्रोविजन में इस इलाक़े को शामिल करा चुके होते. यह विधि सम्मत भी है और आसान भी, लेकिन ऐसा वह नहीं करा रहे. सिर्फ अपने भाषण में मिथिलावासियों की बदहाली को लेकर दर्द बयां करते हैं. भारतीय संविधान में धारा 371 में स्पेशल प्रोविजन की व्यवस्था है. इसके तहत किसी राज्य के सबसे पिछड़े इलाक़े के विकास के लिए केंद्र सरकार पैकेज देती है. इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश सरीखे राज्य के क्षेत्र शामिल हैं. मुख्यमंत्री अपने भाषण में अक्सर कहते हैं कि देश का विकास बिहार के बिना तथा सूबे का विकास मिथिला के बिना संभव ही नहीं है. यह सच भी है, लेकिन इसके लिए उन्हें विशेष प्रावधान में मिथिला को शामिल करवाने की कोशिश करनी चाहिए. विशेष राज्य का दर्जा तो बाद का विषय है. दूसरी ओर जदयू नेता इन बयानों के बाद एकदम आगबबूला हो गए.

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इस तरह का आरोप लगाने से पहले भाजपा सांसद को पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए. बिहार में ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लोगों के जबरदस्त गुस्से का आरोप लगाने के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद को ख़ुद में झांकना इसलिए चाहिए, क्योंकि वह गठबंधन के नेता हैं. आख़िर वह मिथिलांचल की उपेक्षा का आरोप किस सेंस के तहत लगा रहे हैं. लोकसभा का चुनाव आने वाला है. ऐसे में गठबंधन में हो रही खिच-खिच से जनता के बीच ग़लत संदेश जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इसका नुक़सान गठबंधन को ही होगा. मामले की नजाकत को देखते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कीर्ति झा आजाद के बयानों को सुनकर मैं हैरान हूं. मैं जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने वाला इंसान हूं. यह ग़लत है, क्योंकि किसी को भी कोई बात कहने से मना नहीं किया गया. एक ही बात को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है. इसे महज संयोग कहिए या फिर किसी रणनीति का हिस्सा कि नरेंद्र मोदी समर्थक भाजपा सांसदों को नीतीश कुमार की सेवा यात्रा पसंद नहीं आ रही है. अभी पिछले दिनों पूर्णिया के भाजपा सांसद उदय सिंह सेवा यात्रा को लेकर इतने आहत हुए कि उन्होंने प्रशासनिक अमले के ख़िलाफ़ शिकायत करने की बात तक कह डाली. उनका आरोप है कि स्थानीय प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें इस यात्रा में बुलाया तक नहीं गया. उनका कहना था कि सांसद होने के नाते मेरा हक़ बनता है कि मैं अपनी बात इस दौरान होने वाली समीक्षा बैठकों में रखूं, पर आश्चर्य! मुझे बुलाया ही नहीं गया. कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि मुझे बुलाया तो गया, लेकिन नीतीश कुमार ने मुझे अपनी बात कहने नहीं दी और मुझे चुप करा दिया गया.

गौरतलब है कि कीर्ति आजाद और उदय सिंह दोनों सांसद नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं और यह हम सभी भलीभांति जानते भी हैं. दूसरी तरफ संजय झा और नीतीश कुमार के रिश्तों के बारे में भी हम सभी जानते हैं और यह बात किसी से किसी छिपी भी नहीं है. लालू प्रसाद ने जब अपनी परिवर्तन रैली में संजय झा को एलसिसियन कह दिया, तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि संजय झा बहुत अच्छे इंसान हैं. इन सब बातों से कीर्ति झा की पीड़ा बढ़नी स्वाभाविक है. मामला मिथिलांचल की राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने का है. अब देखना यह है कि दोनों झा में कौन किसे पछाड़ कर आगे निकल जाता है.■

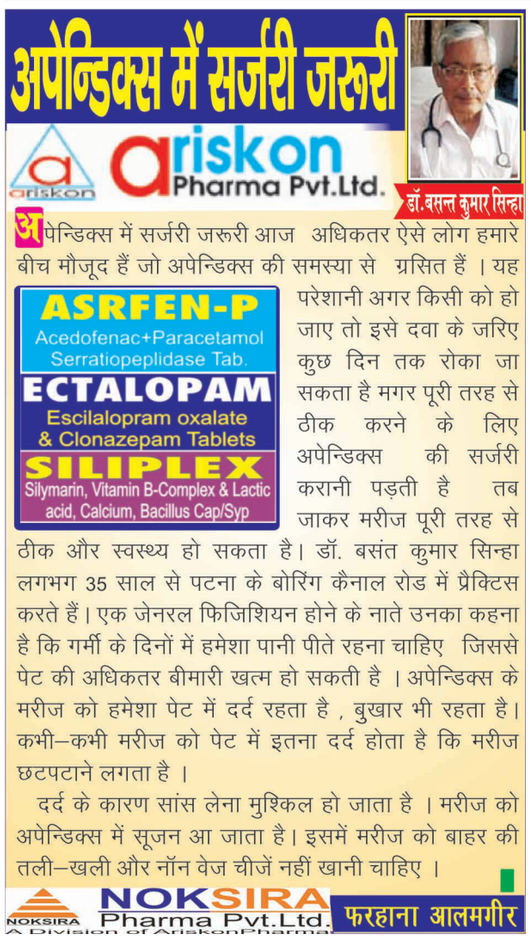

बक्सर में शिक्षक नियोजन पर ग्रहण!

सुशासन की कलई खुली

बक्सर में शिक्षक नियोजन पर ग्रहण लग गया है. नियोजन से पहले ही भ्रष्टचार और धांधली के मामले ने सुशासन की पोल खोल दी है. क्या है अंदर की बात?

जयमंगल पांडेय feedback@chauthiduniya.com

बक्सर ज़िले के कई प्रखंडों में आपसी विवाद के कारण शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर अब ग्रहण लगने की संभावना प्रबल हो गई है. नियोजन से पहले ही फ़र्ज़ीवाड़ा तथा भ्रष्टाचार का मामला उजागर होते ही नियोजन की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया है. नियोजन इकाई के सदस्यों के बीच आपसी खींचातानी शुरू हो गई है, इसलिए कई प्रखंडों का अंतिम मेधासूची पर प्रखंड प्रमुखों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दी है. ज़िले के सिमरी, राजपुर, बह्मपुर आदि प्रखंडों में नियोजन समिति के अध्यक्ष सह प्रमुख तथा सचिव सह बीडीओ के बीच आपसी विवाद तथा आरोप–प्रत्यारोप के मामले की ख़बर ज़िला प्रशासन तक पहुंच गई है. इस विवाद के कारण नियोजन प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया है. सिमरी प्रखंड में मेधासूची बनाने के साथ ही नियोजन रिकॉर्ड को रहस्यमय ढंग से ग़ायब कर दिया गया. इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड प्रमुख एक दूसरे पर काग़ज़ात ग़ायब करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन द्वारा जांच कराने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला.

प्रमुख प्रमिला देवी का आरोप है कि मेधासूची मे 90 लोगों का नाम ग़लत तरीक़े से दर्ज कर धांधली की गई है. उन लोगों का नाम हटाने पर वह अड़ी हुई हैं. डीएम से लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन बीडीओ ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है. लगातार बढ़ते विवाद तथा सूची पर प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने के बाद सिमरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नियोजन के लिए ज़िला प्रशासन से मार्ग दर्शन की मांग की है. इसी प्रकार राजपुर प्रखंड में बीडीओ तथा प्रमुख के बीच शिक्षक नियोजन पूर्व का विवाद और मुखर हो गया है. वहां मेधासूची बनाने के लिए अंकों में नंबर वाले आवेदकों को ग़लत ढंग से नंबर बढ़ा कर मेधासूची में उनका नाम दर्ज कर दिया गया. विवाद के बाद जांच प्रक्रिया चली और अंकों के हेराफेरी का मामला उजागर

प्रमुख प्रमिला देवी का आरोप है कि मेधासूची मे 90 लोगों का नाम ग़लत तरीक़े से दर्ज कर धांधली की गई है. उन लोगों का नाम हटाने पर वह अड़ी हुई हैं. डीएम से लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन बीडीओ ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है. लगातार बढ़ते विवाद तथा सूची पर प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने के बाद सिमरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नियोजन के लिए ज़िला प्रशासन से मार्ग दर्शन की मांग की है.

हो गया. अभी भी कई प्रकार की धांधली के आरोप लगते जा रहे हैं. ब्रह्मपुर प्रखंड में मेधासूची बनने के बाद प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर तो कर दिया गया, लेकिन अंतिम सूची को लेकर प्रमुख तथा बीडीओ में ठन गई. प्रखंड प्रमुख रामबाबू चौधरी ने बैठक की सूचना नहीं देने तथा मनमानी का आरोप लगाया, जबकि बीडीओ डॉ. वीरेंद्र कुमार प्रभाकर का इस मामले में कहना है कि हर बैठक में लिखित सूचना दी जाती रही है. सूची बनाने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है. इसलिए पहली के बाद दूसरी सूची कैसे ग़लत हो सकती है. इसी प्रकार बक्सर ज़िले के पांच प्रखंडों का विवाद सतह पर आ गया है. जाहिर है कि शिक्षा विभाग द्वारा तय तिथि पर शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना क्षीण हो गई है. नियोजन इकाइयों के विवाद पर शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से दिशा–निर्देश मांगा है, लेकिन नियोजन से पूर्व भ्रष्टाचार तथा धांधली के इस खेल में सुशासन सरकार की कलई भी खुल गई. ■

» एक नज़र «

सीता कुंड की परिक्रमा

सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम और रजत द्धार जानकी मंदिर सीतामढ़ी समेत ज़िले में जानकी नौमी के अवसर पर बहुत उत्साह का माहौल रहा. हर तरफ परंपरागत सोहर और बधैया गूंजती रही. जानकी मंदिर प्रांगण में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्साहपूर्वक जानकी जन्मोत्सव मनाया गया. वहीं दूसरी ओर पुनौराधाम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ऐतिहासिक सीता कुंड का विधि पूर्वक परिक्रमा कर अपनी श्रद्धा का इजहार किया. महंत कौशल किशोर दास के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पुरुष और महिलाओं के अलावा, बच्चों की टोली भी शामिल थी. *– चौथी दुनिया ब्यूरो*

कांग्रेस कार्यालय में शहादत दिवस

सीतामढ़ी: पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 21 मई को शहर स्थित ज़िला कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की शहादत दिवस मनाई गई. मौक़े पर आयोजित रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन ज़िला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला ने की. शुक्ला ने कहा कि देश की एकता व अखंडता की ख़ातिर अपने प्राणों की आहूति देने वाले राजीव गांधी की शहादत सदियों तक याद किया जाएगा. मौक़े पर पार्टी के उपाध्यक्ष सीताराम झा, भुवनेश्वरी मिश्र, सत्येंद्र कुमार तिवारी, मो. असद, पूर्व प्रत्याशी मो परवेज आलम अंसारी, नगर अध्यक्ष सीमा गुप्ता, वीरेंद्र कुशवाहा, अंजारुल हक़ तौहिद, ज्वाला, मो. शम्स शाहनवाज समेत कुछ और वरिष्ठ लोग उपस्थित थे. *– ब्रजेश*

स्टेशन मास्टर को तीन पुरस्कार

सीतामढ़ी के दरभंगा–नरकटिया गंज रेलखंड के जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर संजीव कुमार की बेहतर कार्य के लिए अब तक तीन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं. पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के परिचालन प्रबंधक ने उन्हें वर्ष 2012–13 में बेहतर कार्य को लेकर योग्यता प्रमाण पत्र और दो हज़ार रुपये नगद राशि से पुरस्कृत किया. इसी वित्तीय वर्ष में समस्तीपुर के वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक ने पुरस्कृत किया है. वर्ष 2012 में मालगाड़ी में गर्म धुरा पकड़ने को लेकर बतौर पुरस्कार 15 सौ रुपये नगद विभागीय स्तर पर दिया गया है. *– गोविंद कुमार*

विधायक पर आरोप

चतरा विधानसभा के वर्तमान विधायक जनार्दन पासवान को जनता ने जीत दिलाया था. वह झारखंड में रिकॉर्ड मत से जीतने वाले विधायक बन गये थे, लेकिन जनता क्या जानती थी कि वही तारणहार एक दिन कलंकित हो जाएंगे. झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2012 में हुआ, इसमें विधायकों से नोट के बदले वोट लिया गया. इस खेल में सीबीआई ने झारखंड के 22 विधायक–सांसद जांच के दायरे में आए हैं. इनमें चतरा के राजद विधायक जनार्दन पासवान भी थे. उन पर चार्जशीट सभी ने दायर किया जाना बिल्कुल तय है. जनता हैरान है कि जिसे विकासशील पुरुष मानकर सभी ने भारी मतों से जीत दिलाई, उनका दामन कलंकित है!

वृहद भूमि घोटाले का ख़ुलासा

हंटरगंज प्रखंड के खुटिकेवाल खुर्द में भू–हदबंदी मामले में व्यापक स्तर पर की गई जालसाजी से न्यायालय द्वारा अर्जित की जा चुकी भूमि को बचाने का एक सनसनीखेज घोटाला प्रकाश में आया है. इसका ख़ुलासा रामस्वरूप सिंह के द्वारा किया गया है. 1975–85 ई. के बीच चले इस मामले से संबंधित मूल दस्तावेजों को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इस मामले में आरंभ में तीन भू–स्वामी भाईयों द्वारा अलग–अलग जमा किए गए रिटर्नों के आधार पर लगभग 100 एकड़ भूमि अधिशेष पाकर न्यायालय ने भूमिहीनों को दे दिया था, लेकिन भू स्वामियों ने जाली दस्तावेजों का फ़ायदा उठाकर न्यायालय को गुमराह किया तथा अधिशेष भूमि को बचा लिया है. *– अमरेंद्र प्रताप सिंह*

दहशत में हैं व्यवसायी

रामगढ़वा सीमावर्ती क्षेत्र के व्यवसायी इन दिनों दहशत में जी रहे हैं. रंगदारों द्वारा कभी उनसे रंगदारी मांग ली जाती है और न देने पर उन्हें अपनी जान तक गवानी पड़ती है. बीते दिनों स्थानीय थाने से महज दो किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज रोड में आमोदेई गांव निवासी नुरुल्लाह हाफिज के चिमनी के मुंसी तथा भलुवहिया गांव निवासी जंगबहादुर हाजरा को एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल से गोली मार दी और तत्काल भाग निकले. घटना के तक़रीबन एक घंटे तक स्थानीय पुलिस न तो घटनास्थल पर पहुंच पाई थी और न ही अस्पताल पहुंचकर परिजनों का बयान ले पाई थी.■ *– डीएन कुशवाहा*

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

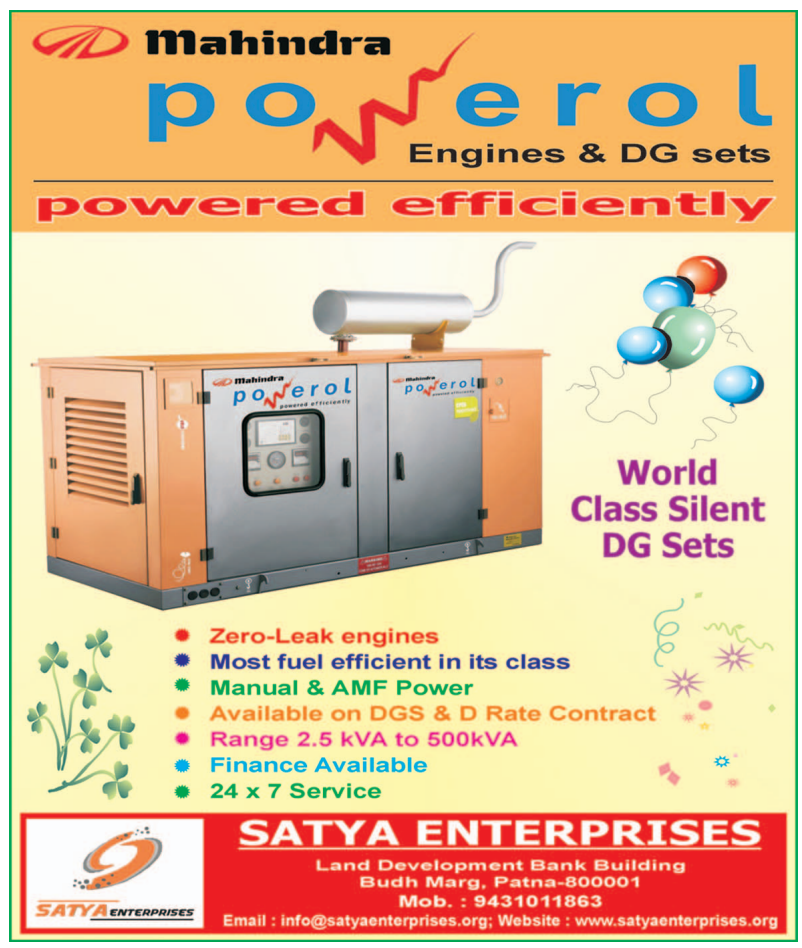

भाजपा और जदयू के बीच आई कड़वाहट के कारण फेरबदल के मामले में भाजपा सांसदों और विधायकों की आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनी गई.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

निजी स्कूलों के निजी नियम

12वीं की पढ़ाई ठेके पर?

अनेक निजी स्कूलों ने तमाम क़ायदे-क़ानून को दरकिनार करते हुए पढ़ाई को ही ठेके पर दे दिया है. ऐसे में अभिभावक क्या करें?

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

बिहार के नामी-गिरामी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में यदि आप अपने बच्चों का 12वीं में नामांकन करा रहे हैं, तो सोच-समझ कर करें, नहीं तो धोखा भी हो सकता है. दरअसल, इन दिनों सीबीएसई से 12वीं की पढ़ाई के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों में 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल की ओर से कोई भी शिक्षक नहीं रखे जा रहे हैं. बिहार के प्रसिद्ध निजी स्कूलों ने 12वीं की पढ़ाई का जिम्मा पूरी तरह से कोचिंग संस्थानों को सौंप दिया है, भले ही कोचिंग शिक्षकों में काबिलियत हो या नहीं! सरकारी स्कूलों में जब ठेके पर शिक्षकों की बहाली होने लगी, तो राज्य के प्रसिद्ध निजी स्कूलों ने भी अपने यहां 12वीं की पढ़ाई का जिम्मा पूरी तरह से ठेके पर दे दिया. गौरतलब है कि ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों का नामांकन कराने वाले अभिभावकों को भी यह पता नहीं होता है कि उनके बच्चे किसी कोचिंग के शिक्षक से पढ़ रहे हैं या स्कूल के शिक्षक से. नियमत: 12वीं की पढ़ाई के लिए सीबीएसई की ओर से उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाती है, जो सीबीएसई के सारे मानदंड को पूरा करते हैं. पूर्ण फैकल्टी (प्रशिक्षित शिक्षकों) की पर्याप्त संख्या, क्लास रूम की पर्याप्त संख्या, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री आदि की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ अन्य कर्मियों को भी सीबीएसई मानक के अनुसार होना ज़रूरी है. मालूम हो कि सीबीएसई की क्राइटेरिया को पूरा करने वाले स्कूलों को ही 12वीं की पढ़ाई की अनुमति दी जाती है. स्कूलों को इस पूरी व्यवस्था पर काफ़ी बड़ी राशि ख़र्च करनी पड़ती है. हालांकि यह भी सच है कि ख़र्च से अधिक राशि नामांकन के समय ही अभिभावकों से वसूल ली जाती है. अब राज्य के चर्चित स्कूलों ने 12वीं की पढ़ाई के लिए अपना पैटर्न बदल लिया है. सीबीएससी से ऐसे निजी स्कूल काग़ज़ी कार्रवाई पूरी कर मान्यता प्राप्त कर लेते हैं और 12वीं की पढ़ाई के लिए किसी कोचिंग संस्थान से संपर्क कर पूरा ज़िम्मा ही उसे सौंप देते हैं. इसके एवज में उक्त कोचिंग संस्थान को स्कूल की ओर से प्रति महीने एक निश्चित राशि दी जाती है, जबकि अभिभावकों को यही ग़लतफ़हमी होती है कि मेरा बच्चा नामी-गिरामी स्कूल में पढ़ रहा है. फ़िलहाल गया में क्रेन मेमोरियल स्कूल तथा नाजरेथ एकेडमी अच्छे स्कूल की श्रेणी में आते हैं. उल्लेखनीय है कि इन दोनों स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना गया शहर में स्टेटस सिंबल माना जाता है. नाजरेथ एकेडमी ने 12वीं की पढ़ाई का ज़िम्मा स्पार्क नाम की संस्था को सौंप दिया है. स्पार्क के शिक्षक ही नाजरेथ एकेडमी में जाकर 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं. हालांकि क्रेन मेमोरियल स्कूल ने इस मामले में विकल्प दिया है. अभिभावकों को यह छूट है कि वे अपने बच्चों को स्पार्क के शिक्षक से पढ़ाएं या फिर स्कूल के शिक्षक से. इसी प्रकार पटना में संत माइकल, संत जेवियर, लोयला तथा नेट्रोडम जैसे स्कूलों ने भी अपने यहां 12वीं की पढ़ाई के लिए स्पार्क को रखा है. अपने यहां फैकल्टी रखने की ज़हमत उठाना इन स्कूलों ने छोड़ दिया है, जबकि अभिभावकों से 12वीं में नामांकन के लिए फॉर्म बेचने से लेकर नामांकन कराने और शिक्षण शुल्क से लेकर अन्य शुल्क के नाम पर बड़ी राशि वसूली जाती है. स्पार्क के कोऑर्डिनेटर ने इस संबंध में पूछे जाने पर बताया कि उपयुक्त स्कूलों के अलावा दरभंगा के चार बड़े स्कूलों के साथ मसौढ़ी, बाढ़ तथा अन्य स्थानों पर स्थित सीबीएसई की मान्यता प्राप्त स्कूलों में हमारी संस्था 12वीं के छात्र-छात्राओं को पढ़ाने का कार्य कर रही है. इसके बदले स्कूल की ओर से प्रति महीने निश्चित राशि मिल जाती है. इस मामले पर मगध अभिभावक फोरम के मदन कुमार तिवारी ने बच्चों तथा उनके अभिभावकों से धोखाधड़ी करने वाले ऐसे निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की मांग सीबीएसई से की है. उन्होंने कहा है कि यदि ज़रूरत पड़ी, तो इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाख़िल की जाएगी. उन्होंने बताया कि शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में आती है. केंद्र या राज्य दोनों सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है. शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए नियम बने हुए हैं, जिसके तहत ग़ैर लाभकारी संस्था को ही शैक्षणिक संस्थानों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है. कोचिंग संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना न सिर्फ़ शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए बने क़ानून एवं नियम की अवलेहना है, बल्कि ग़ैर लाभकारी संस्था द्वारा संचालन करने वाले प्रावधान का उल्लंघन भी है, क्योंकि कोचिंग संस्थान अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं.■

तबादलों से उठे कई सवाल!

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. माना जा रहा है कि यह राजनीति से प्रेरित है. क्या है पर्दे के पीछे का सच?

नीरज/कुलभूषण feedback@chauthiduniya.com

प्रशासनिक फेरबदल वैसे तो सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन सीमांचल की राजनीति में हालिया फेरबदल, ख़ासकर कुछ बड़े तबादलों ने कुछ सवाल पैदा कर दिए हैं. और इसीलिए नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा और जदयू में आई खटास का असर इस फेरबदल में साफ़ दिखाई दे रहा है. भाजपा और जदयू के बीच आई कड़वाहट के कारण फेरबदल के मामले में भाजपा सांसदों और विधायकों की आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनी गई. पूर्णिया सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाते हैं. वेदना प्रदर्शन के बाद जदयू विधायक लेशी सिंह सांसद के विरोध में उतर आई. पिछले दिनों नीतीश कुमार के पूर्णिया दौरे के क्रम में धमदाहा में सरकारी योजनाओं के शिलान्यास से पूर्णिया सांसद उदय सिंह को दूर ही रखा गया. यहां तक कि शिलापट्ट में भी सांसद का नाम दर्ज नहीं हुआ, जिसे पूर्णिया सांसद सरकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन मान रहे हैं और ज़िला प्रशासन पर प्रोटोकॉल के मामले को लेकर मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं.

दरअसल, वहीं विधान पार्षद सह राज्य खाद्य निगम के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सुशील मोदी के क़रीबी माने जाते हैं. 12 मई को सुशील मोदी अररिया के रानीगंज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए. इसी क्रम में राज्य सभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के साथ किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित दिलीप जायसवाल के आवास पर विश्राम करने गए थे. दूसरी तरफ़ पूर्णिया के सरसी में जदयू विधायक लेसी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सुशील मोदी का स्वागत किया, जिसे आम लोग नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश के बीच जारी राजनीतिक लड़ाई के नज़रिए से देख रहे हैं. पुलिस महक़मे के फेरबदल में अररिया के पुलिस अधीक्षक का तबादला राजभवन कर दिया गया.

वहीं अख्तर हुसैन को अररिया पुलिस अधीक्षक की ज़िम्मेदारी दी गई और कटिहार के पुलिस अधीक्षक किम शर्मा को पूर्णिया भेजा गया, और असगर इमाम को कटिहार का पुलिस अधीक्षक बनाया गया. पुलिस महक़मे में इस फेरबदल से सीमांचल में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है. अररिया, कटिहार में जहां एक ओर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, डकैती और लूटपाट जैसी वारदातों में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूर्णिया के रूपौली के जद(यू) विधायक बीमा भारती के पीए की भी हत्या कर दी गई. पुलिस महक़मे में अररिया के पुलिस अधीक्षक शिवदीप लांडे के स्थानांतरण ने सीमांचल के लोगों को चौंका दिया और आम जनविरोध स्वरूप सड़क पर उतर आए. मालूम हो कि शिवदीप लांडे को भजनपुरा कांड के उपरांत अशांत हुए अररिया को शांत करने के लिए भेजा गया था. एक प्रेस वार्तालाप के दौरान पूर्णिया सांसद उदय सिंह ने शिवदीप लांडे की काफ़ी प्रशंसा की थी. उन्होंने पूर्णिया बायपास पर चल रहे अवैध बेरियर को उखाड़ फेंका. उनके निर्देश के तहत पूर्णिया में नक़ली डीटीओ ऑफिस, नक़ली खाद और अवैध शराब फैक्ट्री के मामले से संबंधित जांच को आगे बढ़ाया गया. गौरतलब है कि बायपास बेरियर को जहां जिलाधिकारी एन सरवन कुमार जायज ठहरा रहे थे, वहीं पुलिस अधीक्षक लांडे एनएचआई के पत्रों का हवाला देकर उसे अवैध ठहरा रहे थे, जिसमें सरकार की बदनामी भी हुई. कटिहार प्रभार के दौरान लांडे ने झारखंड से आने वाले अवैध गिट्टी से लदे ट्रकों को जब्त किया और राजस्व चोरी के कई मामलों को पकड़ा. हालांकि ठाकुरगंज के जद(यू) विधायक नौसाद आलम एवं किशनगंज के जदयू के वरिष्ठ नेता इलियास रहमानी का कहना है कि प्रशासनिक फेरबदल सरकार द्वारा क़ानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से किया गया है. हमारी पार्टी किशनगंज समेत अन्य सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. भाजपा के लोग बता रहे हैं कि यह फेरबदल चुनावी है और नरेंद्र मोदी समर्थक नेताओं को नीचा दिखाने के लिए किया गया है. वरना, लांडे जैसे अधिकारी का तबादला किसी भी हालत में नहीं होता. ■

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

03 जून-09 जून 2013

www.chauthiduniya.com

माया के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपये का घपला

बसपा के वफ़ादार ही निकले सभी घोटालेबाज़

उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा सूबा है, जहां सरकार की प्राथमिकता लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की बजाय मूर्तियों और स्मारक बनाने की है. प्रदेश में जब बसपा सत्ता में होती है, तब आंबेडकर और मायावती की मूर्तियों के नाम पर करोड़ों रुपये ख़र्च होते हैं और जब सपा की सरकार बनती है, तो डॉ लोहिया चौक-चौराहों पर नज़र आने लगते हैं. इस बुतपरस्ती की वजह से आम जनता से जुड़ीं समस्याएं गौण हो जाती हैं और शुरू हो जाती है इसे लेकर गंदी सियासत.

संजय सक्सेना

feedback@chauthiduniya.com

बसपा प्रमुख मायावती ने कुछ ऐसे संतों और महापुरुषों को समाज में सम्मान दिलाने का काम किया था, जो किन्हीं कारणवश वह प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर सके थे, जिसके वे असल में हक़दार थे. ऐसे ज्ञानियों, समाज सुधारकों, दलित चिंतकों और संत-महात्माओं ने दलित कुल में जन्म लेकर न केवल अपने समाज, बल्कि अन्य बिरादरी के लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया था. हालांकि देश में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था के चलते वह ताउम्र सम्मान के लिए तरसते रहे. बसपा प्रमुख मायावती चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और चारों बार उन्होंने इस दिशा में काफ़ी काम किया. इन महापुरुषों के प्रति माया का लगाव ही था, जो उन महानुभावों के नाम पर होने वाले निर्माण कार्यों को माया के ड्रीम प्रोजक्ट्स के नाम से जाना गया. मायावती ने सत्ता में रहते अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी अपने सबसे क़रीबी और वफादार नेताओं को सौंपी थी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वैसा काम उनके वफ़ादारों ने नहीं किया. यही कारण था कि स्मारकों के निर्माण के दौरान माया के वफ़ादारों ने जनता के पैसों की जमकर लूट मचाई. चाहे पत्थरों की ख़रीद का मामला हो या उसे तराशने का काम, सबमें उन वफ़ादारों ने घोटाला किया.

इस बात का पता उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन के महरोत्रा की जांच में चला, तो लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए. बसपा सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दिकी और बाबू सिंह कुशवाहा की कृपा से लखनऊ और नोएडा में बने स्मारकों में 14 अरब 88 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया, लेकिन माया को इसकी भनक तक नहीं लगी. सिद्दिकी और कुशवाहा के अलावा, इस महाघोटाले में कई विधायकों और अधिकारियों के शामिल होने की बात भी सामने आई है. लोकायुक्त ने इन लोगों को दोषी करार देते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. प्रदेश में इतने बड़े घोटाले का खुलासा होते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया. इसे लेकर भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं. हालांकि यह और बात है कि लोकायुक्त को स्मारकों के घोटालों की जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के ख़िलाफ़ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. बात अगर पूरे ख़र्चे की करें, तो स्मारकों के निर्माण के लिए 42,76,83,43,000 रुपये जारी किए गए थे और उनमें से 41,48,54,80,000 रुपये ख़र्च किए गए. शेष 1,28,28,59,000 रुपये वापस कर दिए गए. स्मारकों के निर्माण पर ख़र्च की गई कुल राशि का लगभग 34 फ़ीसदी ज़्यादा ख़र्च करके सरकार को 14,10,50,63,200 रुपये का चूना लगाया गया. लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में इच्छा ज़ाहिर की है कि सभी दोषियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई जाए. इसके अलावा, उन्होंने कुछ नेताओं और सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से घोटाले की रक़म वापस कराने के लिए उचित कदम उठाने की बात भी कही है. वैसे बाबू सिंह कुशवाहा को भ्रष्टाचार के चलते मायावती पहले ही बसपा से निकाल चुकी हैं, लेकिन नसीमुद्दीन का नाम स्मारक घोटाले में आना उनके लिए एक बड़ा आघात ज़रूर है.

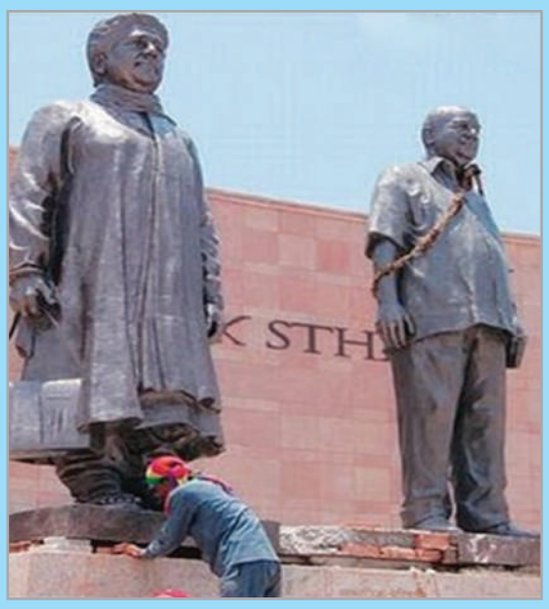

यहां यह बता देना ज़रूरी है कि बसपा के लिए स्मारक घोटाला आगामी चुनाव में गले की हड्डी बन सकता है. इस बात का अहसास अब मायावती को भी होने लगा है. इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि बसपा राज में पूरी तरह लूटतंत्र स्थापित हो गया था. इस महालूट में मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों से लेकर बसपा के कई नेता और विधायक भी शामिल थे. वहीं आम जनता जब अपनी फ़रियाद लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जाते थे, तो उनके चाटुकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते थे, लेकिन सपा सरकार में ऐसा नहीं है, यहां आम जनता के लिए मुख्यमंत्री का दरबार हमेशा खुला रहता है. सपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती प्रतिमाएं लगाने में मशगूल थीं, क्योंकि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं था. बसपाराज में जनता के हितों पर डाका डाला गया और सरकारी ख़जाने की खुली लूट मची. उसकी पोल अब दिन-ब-दिन खुलती ही रही है और साथ ही साथ क़ानून का शिकंजा बसपा नेताओं पर कसता जा रहा है. उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने खिलेश सरकार पर बसपाकाल के घोटालों को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्मारक घोटाला साबित होने के बाद दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने राजनीतिक फ़ायदा-नुक़सान को भूल कर अखिलेश यादव से तत्काल ठोस कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं कांग्रेस चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए. कांग्रेस नेता सुबोध श्रीवास्तव का आरोप है कि बसपा राज में जनता के पैसे को पानी की तरह उल्टी-सीधी योजनाओं पर बहा दिया गया, लेकिन अब हक़ीक़त सामने आ रही है. उनके अनुसार, बग़ैर मुख्यमंत्री की सहमति से इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी की भी कुछ ऐसी ही राय है. वह चाहते हैं कि माया राज के समय हुए सभी सौदों और ड्रीम प्रोजेक्ट्स जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जांच सलीके से हो, ताकि जनता को पता चल सके कि उसके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद स्मारक घोटाले में शामिल आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जनता का भरोसा क़ायम रखते हुए भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड देना चाहिए.

बहरहाल, माया राज के घोटालों से सरकार को आर्थिक नुक़सान तो हुआ ही, साथ ही कई लोग मौत के मुंह में भी चले गए. माया राज में हुए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के घोटाले में दो सीएमओ मारे गए, जबकि एक डिप्टी सीएमओ की जेल के अंदर रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. बसपा के कई पूर्व मंत्री भी इस समय जेल की हवा खा रहे हैं. सतर्कता विभाग की जांच में 9 बसपा मंत्री फंस रहे हैं. उम्मीद है कि तीन पूर्व मंत्रियों की जांच पूरी कर उनके ख़िलाफ़ भी आरोप-पत्र दाख़िल करने और पांच पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की अनुमति मिलने की देर है. हालांकि एक पूर्व बसपा मंत्री के ख़िलाफ़ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी गई है. इस मामले में बसपा के जो माननीय फंसे हैं, उनके नाम हैं पूर्व शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी, सहकारिता मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दिकी, पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय और पूर्व लघु उद्योग मंत्री चंद्रदेव राम यादव. इन मंत्रियों के ख़िलाफ़ तमाम साक्ष्य मिले हैं.

बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर के ख़िलाफ़ भी तमाम मामलों की जांच अब अंतिम दौर में है. पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, बादशाह सिंह और चंद्रदेवराम लैकफेड घोटाले के कारण जेल में बंद हैं. नसीमुद्दीन सिद्दिकी शहंशाहों की तरह शाहख़र्ची दिखाते रहे हैं. पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह भी बुरी तरह जांच में घिरे हुए हैं. रामअचल राजभर की संपत्ति पांच साल के भीतर एक करोड़ से दस अरब तक पहुंच गई है. इन मंत्रियों के नाते रिश्तेदार भी ज़मीन और धन की लूट में शामिल पाए गए हैं. बात स्मारक घोटाले की जांच आगे बढ़ने की करें, तो उसे लेकर सबकी नज़रें राज्य सरकार पर लगी हैं. लोकायुक्त ने सरकार से स्मारक जांच सीबीआई को देने या फिर ऐसी कोई एसआइटी (विषेश पुलिस बल) गठित करने की सिफ़ारिश की है, जो सरकार से मुक्त हो. ऐसे में प्रदेश की सपा सरकार क्या फ़ैसली लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. ■

दिल्ली में यूपी से दस गुना अपराधः मुलायम

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र पूरे देश की निगाहें समाजवादी पार्टी की ओर लगी हुई हैं. उनके मुताबिक़, केंद्र में भाजपा और कांग्रेस की नहीं, बल्कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और यह तभी संभव है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी ताक़त के रूप में उभरेगी. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने यह बातें लखनऊ में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कही. मुलायम में अपनी सरकार की तारीफ़ करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ जो वादे किए गए थे, उनमें से अधिकांश पूरे किए जा चुके हैं. समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. सपा प्रमुख ने इस मौक़े पर कहा कि उनकी सरकार में किसानों, बुनकरों, छात्राओं और बेरोज़गार युवाओं को फ़ायदा मिल रहा है. उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग क़ानून-व्यवस्था के नाम पर अखिलेश सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें कम से कम दिल्ली और मुंबई के आपराधिक आंकड़ों पर ग़ौर करना चाहिए.

चौथी दुनिया

आईएससी परीक्षा में सत्येश शंकर अवस्थी ने सर्वोच्च 97.25 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय का मान बढ़ाया.

चौथी दुनिया

दोनों ने एक-दूसरे पर लाठी से जबर्दस्त हमला कर दिया. दोनों ने दौड़-दौड़कर एक-दूसरे पर लाठियां भांजी और तब तक वे दोनों शांत नहीं हुए, जब तक दोनों लहूलुहान होकर पस्त नहीं हो गए.

उत्तराखंड में अन्ना को मिला भारी जनसमर्थन

जनतंत्र यात्रा को हर जगह काफ़ी जनसमर्थन मिला. लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना नहीं आंधी है, देश का नया गांधी है, अन्ना का साथ देंगे, ज़रूरत पड़ी, तो जान भी देंगे जैसे नारों से समूचा पहाड़ गूंज रहा था.

समाजसेवी कार्यकर्ता अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा बीते 14 मई को धर्मनगरी ऋषिकेश से देश में व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार के साथ शुरू हुई. जनतंत्र यात्रा को हर जगह काफ़ी जनसमर्थन मिला.

लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना नहीं आंधी है, देश का नया गांधी है , अन्ना आया परिवर्तन की लहर लाया, अन्ना का साथ देंगे, ज़रूरत पड़ी, तो जान भी देंगे जैसे नारों से समूचा पहाड़ गूंज रहा था. इस दौरान अन्ना को देखने और सुनने के लिए महिला, पुरुष, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घंटों इंतज़ार करते साफ़ देखे गए . इन शहर-कस्बों में पहले भी राष्ट्रीय स्तर के न जाने कितने बड़े नेता पहुंचे होंगे, लेकिन उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है. हालांकि अन्ना की यह जनतंत्र यात्रा पूरी तरह जन आधारित है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री ने किया मुंबई में यूपी भवन का लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों मुंबई में उत्तर प्रदेश भवन के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुंबई में अतिथि गृह होने से उत्तर प्रदेश के लोगों को यहां आने के बाद होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी और सरकार से संबंधित कार्यों को संपादित करने वालों को इधर-उधर नहीं रहना पड़ेगा. ग़ौरतलब है कि इस भवन के बन जाने से उत्तर प्रदेश से कैंसर के इलाज़ के लिए आने वाले मरीजों के साथ-साथ यहां प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा.

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा-पत्र में शामिल की गई योजनाओं और वादों को तेज़ी से पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लैपटॉप वितरण के साथ-साथ मुस्लिम ग़रीब छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने या उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है. उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याण कारी योजनाओं की नकल अब दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने भी शुरु कर दी है.

मुख्यमंत्री अखिलेश ने बताया कि इस भवन के निर्माण का सपना नेताजी मुलायम सिंह यादव ने देखा था, इसलिए वर्ष 1995 में जब वे मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने मुंबई में अतिथि गृह बनवाने का निर्णय लिया. आज 18 वर्षों बाद यह कार्य पूरा हुआ है. इस दौरान दूसरी पार्टी की सरकारों ने इस परियोजना के महत्व को नहीं समझा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक धुरी है और उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता भी मुंबई से ही पूरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में राज्य का अपना अतिथि गृह होने से लाभ मिलेगा. उत्तर प्रदेश में उत्पादों और आर्थिक गतिविधियों को विश्व के व्यापक फलक पर पहचान दिलाने में मुंबई एक माध्यम हो सकती है. उन्होंने कहा कि नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 2003 में बनी सरकार ने मुंबई में अतिथि गृह के निर्माण की वित्तीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपने संसाधनों द्वारा अतिथि गृह के निर्माण की पहल की. उनके अनुसार, वर्ष 2012 में प्रदेश में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद योजना की शेष धनराशि स्वीकृत कर अतिथि गृह का निर्माण पूरा कराया गया. इस अतिथि गृह के निर्माण में 32.34 करोड़ रुपये की लागत आई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहा है, ऐसे में प्रदेश शीघ्र ही गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देगा. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि गुजरात सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है, जबकि सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है.

अखिलेश ने बताया कि इस भवन के निर्माण का सपना नेताजी मुलायम सिंह यादव ने देखा था, इसलिए वर्ष 1995 में जब वे मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने मुंबई में अतिथि गृह बनवाने का निर्णय लिया. आज 18 वर्षों बाद यह कार्य पूरा हुआ है.

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता है कि महाराष्ट्र में उनका विस्तार हो. उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा न मिले. मुख्यमंत्री ने बताया कि निमेष कमेटी की सिफ़ारिशों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कैंसर के मरीज़ों को उत्तर प्रदेश में ही आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए ज़मीन की व्यवस्था की जा चुकी है.

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह, श्रम राज्यमंत्री शाहिद मंजूर, संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुणा कोरी, मनोरंजन कर राज्यमंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राम आसरे विश्वकर्मा, विधायक महाराष्ट्र अबू आसिम आज़मी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग, सचिव मुख्यमंत्री एवं सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग अनीता सिंह, मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, लोकगायक मनोज तिवारी, राजू श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कहीं उक्रांद का अस्तित्व ही न मिट जाए

आसान होता है मुर्दों का खड़ा हो जाना, लेकिन ख़तरनाक होता है सपनों का मर जाना. पाश की ये पंक्तियां इन दिनों उत्तराखंड क्रांति दल के लिए मुफ़ीद साबित हो रही हैं. पृथक राज्य के गठन में निर्णायक भूमिका निभाने वाली उक्रांद राज्य बनने के बाद अपनी नीतियों को छोड़ सत्ता की चाटुकारिता में मशगूल हो गई. आख़िर किन वजहों से पतन की ओर बढ़ रही है यह पार्टी, पढ़िए इस रिपोर्ट में...

जबर सिंह वर्मा
feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड क्रांति दल का नाम आते ही जेहन में एक ऐसे संगठन की छवि उभरती है, जिसने राज्य आंदोलन का झंडा बुलंद कर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना अहम योगदान दिया. 25 जुलाई, 1979 में गठित उक्रांद का राज्य गठन से पहले गौरवमयी इतिहास रहा है. राज्य आंदोलन की चिंगारी को भड़का कर शोला बनाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जैसे दिग्गजों की इस पार्टी में ऐसे नेताओं का प्रवेश हो गया है कि इनकी वजह से आज यह पार्टी रसातल में चली गई है. किसी जमाने में कोदूं-झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे जैसे क्रांतिकारी नारे को भुलाकर मौजूदा उक्रांद नेताओं ने सत्ताधारी दलों की चापलूसी में अपनी ऊर्जा गवां रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि नए राज्य बनने और उसके बाद हुए चुनावों में उक्रांद को बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली. महज तीन विधायकों के सहारे ही यह पार्टी ज़िंदा है. राज्य आंदोलन के दौरान और उत्तराखंड बनने के बाद राष्ट्रीय पार्टियों को लगातार पहाड़ विरोधी बताने के बावजूद पार्टी नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी के लिए हमेशा बैशाखी का काम ही किया है. उसके नेता पहाड़ से लेकर मैदान तक कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर सके. उक्रांद दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं में भी अपनी पैठ नहीं जमा सका. वहीं राज्य गठन के बाद बसपा लगातार तीसरे स्थान पर बनी हुई है. बेहद ख़राब दौर से गुजरने के बावजूद बसपा के तीन विधायकों ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की. इतने विधायक उक्रांद को उसके अच्छे दौर में बमुश्किल मिल पाए थे. अगर हालात नहीं बदले और उक्रांद ने अपनी सांगठनिक क्षमता को मज़बूत नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं, जब सूबे की सियासत में इसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा.

टिहरी लोकसभा उपचुनाव में भी पार्टी नेताओं का यह दोहरा चरित्र सामने आया. सरकार में शामिल होने के बावजूद उक्रांद ने अपने अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार को इस चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, लेकिन हैरानी की बात, तो यह थी कि सरकार में शामिल मंत्री प्रीतम सिंह पंवार अपने ही अध्यक्ष के चुनाव प्रचार में एक दिन भी नहीं गए. इतना ही नहीं, पंवार के विधानसभा क्षेत्र से पार्टी को सबसे कम वोट पड़े.

प्रदेश में अब तक बनी तीन सरकारों में दो उक्रांद के सहारे चलीं. पार्टी पहले भाजपा और अब कांग्रेस को समर्थन दे रही है. पिछले दो चुनावों में पार्टी के जो नेता जीत कर आए, वे सत्ताधारी पार्टियों के चापलूस बनकर रह गए, जबकि संगठन में रहे नेताओं ने दोनों ही मर्तबा सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले रखा. इससे सरकार और संगठन में शामिल नेताओं में हर बार जबरदस्त मतभेद पैदा हुए और इसलिए उनके बीच कई धड़े बन गए.

पूर्व बीजेपी सरकार में उक्रांद कोटे से मंत्री बने दिवाकर भट्ट और विधायक ओम गोपाल रावत सरकार की गणेश परिक्रमा करते रहे. हालांकि पार्टी को उनका यह सत्ता मोह रास नहीं आया और उन्हें दल से निष्कासित कर दिया गया. इस तक़रार से पार्टी टूटी और दिवाकर गुट ने उत्तराखंड जनक्रांति दल बना लिया. उसी तरह पार्टी के दूसरे नेताओं शक्तिशैल कपरवाण ने उक्रांद डेमोक्रेटिक और ललित बिष्ट का उक्रांद एकता का गठन किया.

पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उक्रांद के एकमात्र प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार यमुनोत्री विधानसभा से चुनकर आए, तो पार्टी ने कांग्रेस की लंगड़ी सरकार को समर्थन दिया और पंवार कैबिनेट मंत्री बन गए. हालांकि दिवाकर और रावत के सत्ता प्रेम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले प्रीतम पंवार इस बार ख़ुद कांग्रेस सरकार में मंत्री बने बैठे हैं. इससे जनता में यह संदेश जा रहा है कि उक्रांद लगातार सरकार में रहकर एक तरफ मलाई काट रही है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरकर सरकार के ख़िलाफ़ गुर्रा भी रही है.

टिहरी लोकसभा उपचुनाव में भी पार्टी नेताओं का यह दोहरा चरित्र सामने आया. सरकार में शामिल होने के बावजूद उक्रांद ने अपने अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार को इस चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, लेकिन हैरानी की बात, तो यह थी कि सरकार में शामिल मंत्री प्रीतम सिंह पंवार अपने ही अध्यक्ष के चुनाव प्रचार में एक दिन भी नहीं गए. इतना ही नहीं, पंवार के विधानसभा क्षेत्र से पार्टी को सबसे कम वोट पड़े. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा के समर्थन में खड़ा कर रखा था. इससे यही ज़ाहिर होता है कि पंवार ने अपने अध्यक्ष को बेहद चतुराई से ठिकाने लगाया.

ग़ौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह पवार को टिहरी संसदीय सीट में सात हज़ार वोट भी नहीं मिले. उन्होंने अपनी जमानत तो गंवाई ही, रक्षा मोर्चा जैसे नए और आधारहीन माने जाने वाले क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी से भी पिछड़ कर अपनी और संगठन की साख को बट्टा लगा दिया. इस बार के बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन सरकार में शामिल उनके एकमात्र मंत्री ने सरकार से बाहर निकलने से साफ़ इंकार कर दिया. पार्टी की समस्या यह थी कि वह पंवार को निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में नुक़सान अंततः उक्रांद को ही होना था. हालांकि, बात ज्यादा आगे बढ़ी, तो त्रिवेंद्र पंवार ने अपने इस एकमात्र विधायक को भी पार्टी निष्काषित कर दिया. इसके अलावा, पार्टी संरक्षक काशी सिंह ऐरी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन, इससे भी उक्रांद एक बार फिर टूट की कगार पर पहुंच गई है।

उक्रांद से बर्ख़ास्त काशी सिंह ऐरी ने, नेतृत्व परिवर्तन की मुहिम छेड़ते हुए अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार से सलाह-मशविरा किए बग़ैर 20 और 21 मई को देहरादून में दो दिवसीय पार्टी महाधिवेशन बुला लिया. इस अधिवेशन में बहुमत होने का दावा करते हुए पंवार को हटाकर ऐरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया. हालांकि, इस महाविधवेशन को असंवैधानिक बताते हुए त्रिवेंद्र सिंह पवार कह रहे हैं कि महाधिवेशन में कोरम तक पूरा नहीं किया गया. ऐरी के बुलाए इस महाधिवेशन से दूर रहे पंवार और उनके समर्थक नई कार्यकारिणी का विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि उसके ख़िलाफ़ निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करने की तैयारी चल रही है. देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय को लेकर भी इन दोनों गुटों में खींचतान चल रही है. ऐरी गुट ने कार्यालय पर क़ब्ज़ा कर लिया है, जबकि पंवार अपने समर्थकों के साथ कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं. ऐसे हालात में अब उक्रांद का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फ़ैसला तो निर्वाचन आयोग ही करेगा, लेकिन इस घटनाक्रम से संगठन एक बार फिर टूट की क़गार पर पहुंच चुका है. अगर ऐसा हुआ, तो उक्रांद से टूट कर कोई नई पार्टी बनेगी.

उल्लेखनीय है कि कई खेमों में बंट चुके उक्रांद का राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक विधायक चुनकर आना और बाग़ी धड़ों के बनाए दलों का हाशिए पर जाना इस बात का प्रमाण है कि राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्रीय दल के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इस बार एक सीट जो पार्टी के खाते में आई थी, उसे भी वह लगभग गंवा चुकी है. पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के कई दिग्गज़ नेता कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने टिक भी नहीं पाए. लोकसभा उपचुनाव में पार्टी अध्यक्ष को मिली क़रारी शिकस्त यह बताने के लिए काफ़ी है कि आगामी चुनावों में उक्रांद प्रत्याशियों को एक-एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा. ऐसे में वह दिन दूर नहीं, जब उत्तराखंड में तीसरी सियासी ताक़त बनने का सपना देख रही उक्रांद का अस्तित्व ही मिट जाएगा. ■

स्कॉलर्स होम के मेधावी छात्र हुए सम्मानित

आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में नाम दर्ज कराने वाले स्कॉलर्स होम, गोमती नगर, लखनऊ के विद्यार्थियों को पिछले दिनों स्कूल प्रांगण में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया. पिछले साल की तरह इस वर्ष भी अपनी योग्यता और लगन के बल पर स्कॉलर्स होम के 67 छात्र-छात्राओं ने बारहवीं(आईएससी) और दसवीं(आईसीएसई) की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल को एक बार फिर गौरवान्वित किया. इस मौक़े पर प्रधानाचार्य सरिता जायसवाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्द्धन करते हुए उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी.

आईएससी परीक्षा में सत्येश शंकर अवस्थी ने सर्वोच्च 97.25 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय का मान बढ़ाया. वहीं विद्यालय में दूसरा स्थान पाने वाले मयंक रजानी ने 96.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. समर्थ शुक्ला 94.25, आशुतोश विक्रम सिंह 93.75 और दीर्घा जोशी को 90 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए. उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और अध्यापकों को दिया. छात्रों ने बातचीत में बताया कि उनकी इच्छा राजनीति में जाने की नहीं है, बल्कि वे उच्च शिक्षा हासिल कर इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं. आईसीएसई परीक्षा में स्कॉलर्स होम की रुचि मिश्रा ने गणित विषय में शत-प्रतिशत 100 अंक हासिल कर विशिष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया. छात्र-छात्राओं को आईएससी और आईसीएसई परीक्षा में बड़ी सफलता दिलाकर स्कॉलर्स होम ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. ■

उत्तराखंड/ ख़बरें

अब वनों में आग कम लगेगी

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आग लगने का सबसे बड़ा कारण चीड़ के पत्ते ही हैं. अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण यह पल भर में जंगलों को ख़ाक करने की क्षमता रखती है.

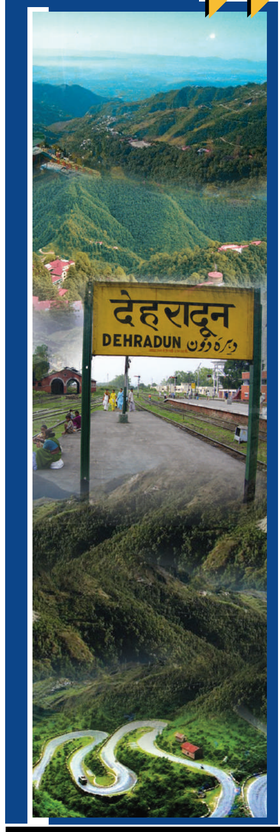

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

जंगलों को बचाने में चीड़ के पत्ते संग्रहण योजना धीरे-धीरे फ़ायदेमंद साबित हो रही है. एक वर्ष के दौरान इस योजना का सीधा लाभ वनों में दिखा है. आग की घटनाओं में कमी आने का एक बड़ा कारण यह है कि जंगलों से चीड़े के पत्तों को हटाया जा रहा है. इससे प्रदेश वासियों को दोहरा लाभ हो रहा है, क्योंकि उन्हें चीड़ के पत्तों से आमदनी भी हो रही है.

फ़िलहाल चीड़ का उपयोग कोयला बनाने में किया जाता है और भविष्य में राज्य के सभी ज़िलों में इसे संग्रहित कर बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा. ग़ौरतलब है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आग लगने का सबसे बड़ा कारण चीड़ के पत्ते ही हैं. दरअसल, अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण यह पल भर में जंगलों को ख़ाक करने की क्षमता रखती है. प्रमुख वन संरक्षक डॉ. आरबीएस रावत ने इस बाबत दो साल पहले एक रूपरेखा बनाई थी. पिछले साल 15000 कुंतल चीड़ के पत्तों का संग्रहण कर कोयला बनाया गया. चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र में इसकी मदद से 120 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट बन रहा है. इतना ही नहीं, उत्तरकाशी क्षेत्र में सोनाप्सी कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू पर भी दस्तख़त हो चुका है.■

जगजीत की स्मृति में रक्तदान को प्रोत्साहन

मिथिलेश लखनवी ने जगजीत सिंह का प्रसिद्ध भजन हे राम, हे राम गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. उसके बाद मिर्ज़ा ग़ालिब की गजल आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक सुनाकर उन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस मौक़े पर कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर एम के गुप्ता सह प्रायोजक घर होटल हरदोई के अध्यक्ष ज्ञान वर्धन अग्रवाल आदि गणमान्य लोग मौजूद थे.

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ के संत गाडगे सभागार में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा गोमती नगर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम जगजीत सिंह के नाम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मिथिलेश लखनवी और उनके साथियों सुभाष शर्मा (तबला), गुंजन मैसी (की बोर्ड), अतुल श्रीवास्तव (ऑक्टोपैड), राकेश आर्या (गिटार) और निशा सिंह (गायिका) ने जगजीत सिंह की ग़ज़लें सुनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. मिथिलेश लखनवी ने जगजीत सिंह का प्रसिद्ध भजन हे राम, हे राम गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. उसके बाद मिर्ज़ा ग़ालिब की गजल आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक सुनाकर उन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस मौक़े पर कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर एम के गुप्ता सह प्रायोजक घर होटल हरदोई के अध्यक्ष ज्ञान वर्धन अग्रवाल आदि गणमान्य लोग मौजूद थे. ट्रस्ट की प्रबंध न्यासी डॉ. रूपल अग्रवाल ने वहां आए अतिथियों, फ़नकारों और श्रोताओं का स्वागत किया. इस मौक़े पर उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए हमें रक्तदान कर समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. कार्यक्रम के संचालक हसन काज़मी थे.

इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रीता बहुगुणा जोशी, विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष यूपीसीसी, विशिष्ट अतिथि नावेद सिद्दिकी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डीपी बोरा, पंकज बोरा, चेयरमैन बीआईएमएस, डॉ. नीरज बोरा पूर्व अध्यक्ष, यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि जगजीत सिंह विश्व प्रसिद्ध फ़नकार थे. उनके असामयिक निधन से संगीत जगत को काफ़ी क्षति हुई है.

इसलिए उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे रक्तदान की महत्ता को समझें और अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान ज़रूर करें, ताकि इससे किसी को नई ज़िंदगी मिल सके. नावेद सिद्दिकी ने भी रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया.■

अपनी लाठी अपना सिर

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम विसंगतियों से घिरी हुई है. यूपी पुलिस जनता की रक्षक बनकर रहे, इस बाबत क़ानून बेहद सख़्त बनाए गए हैं. हालांकि उन्हें इन क़ानूनों का पालन करने नहीं दिया जाता है. उनके लिए सही-ग़लत के बीच अब कोई अंतर नहीं रह गया है. वह सही करे या ग़लत दोनों ही दशाओं में उसके सिर पर ख़तरे की घंटी बजती रहती है. ऐसे हालात में वह सही दिशा में चलने की बजाय सभी को खुश करके चलते हैं. पुलिस विभाग में हर मुलाज़िम किसी न किसी के दबाव में रहता है. इतना ही नहीं, उस पर राजनीतिक दलों ख़ासकर सत्तारूढ दलों का, तो और भी दबाव रहता है.

ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस पूरी तरह दूध की धुली हुई है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि चाहे लोकशाही हो या नौकरशाही किसी ने भी पुलिस सुधार के कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं लिया है. कई बार पुलिस सुधार की बात पर कमेटियां भी बैठाई गईं, लेकिन सब ढाक के तीन पात ही सबित हुए. दरअसल, आज पुलिसकर्मी अजीब मनोदशा के बीच अपना काम कर रहे हैं. उनकी समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है. छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी उसे एड़ियां घिसनी पड़ती है. यही कारण है कि पुलिसकर्मियों अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम कभी हैवानियत के रूप में सामने आता है, तो कभी आपस में ही पुलिस वाले सिर फुटव्वल करने लगते हैं. ऐसा ही एक नज़ारा गत दिनों राजधानी लखनऊ में देखने को मिला. वीआईपी ड्यूटी में लगे पीएसी के जवान आपस में ही खून के प्यासे हो गए. दरअसल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उस वक्त अफ़रा-तफ़री मच गई, जब ड्यूटी में तैनात पीएसी के दो जवान आपस में ही भिड़ गए. ड्यूटी को लेकर दोनों जवानों में छिड़ी बहस कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. दोनों ने एक-दूसरे पर लाठी से जबर्दस्त हमला कर दिया. दोनों ने दौड़-दौड़कर एक-दूसरे पर लाठियां भांजी और तब तक वे दोनों शांत नहीं हुए, जब तक दोनों लहूलुहान होकर पस्त नहीं हो गए.

इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी कोई बीच-बचाव नहीं किया और लाइव मार-धाड़ देखने का आनंद लेर हे थे. बाद में दोनों को इलाज़ के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया. इस घटना के बाद आईजी क़ानून व्यवस्था राज कुमार विश्वकर्मा ने 10 वीं बटालियन पीएसी के दोनों जवान हेड कांस्टेबल मुकुंद चंद्र यादव और सुनील दीक्षित को निलंबित कर दिया गया.

हालांकि पीएसी के महानिदेशक अतुल कुमार इस घटना से काफी आहत दिखे. उनका कहना था कि अनुशासित फोर्स में मारपीट दंडनीय है. बहरहाल, पीएसी के दो जवानों के बीच मारपीट के बाद वर्दी की भूमिका पर भी बहस छिड़ गई है. कहा तो यह भी जा रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर वर्दी पहनकर मारपीट करने से पुलिस का इक़बाल ख़त्म हो रहा है.■

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

चौथी दुनिया ने राजधानी से सटे टिहरी जनपद की धनोल्टी तहसील में खुर्द-बुर्द की गई दलितों की कुछ ज़मीनों की जांच-पड़ताल की, तो इस संबंध में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

आपराधिक वारदातों से जनता हलकान

कठघरे में अखिलेश सरकार

विधानसभा चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि उसकी सरकार न केवल सूबे में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, बल्कि क़ानून-व्यवस्था भी और दुरुस्त करेगी, लेकिन अखिलेश सरकार इन दोनों मोर्चों पर नाक़ाम रही है. कितना खोखला साबित हुआ प्रदेश सरकार का दावा, पढ़िए इस रिपोर्ट में...

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अखिलेश सरकार के सवा साल के शासन में डीजीपी से लेकर सिपाहियों का तबादला कर दिया गया, लेकिन प्रदेश की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है. कुछ दिनों पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था में सुधार लाने का दावा ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उनके दावों की पोल उस वक्त खुल गई, जब सूबे में एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आने लगे. हालांकि, सपा प्रमुख मुलायम अब विकास की डींगें हांककर अखिलेश सरकार की तरफदारी कर रहे हैं. उनकी दलील है कि सपा सरकार में राज्य का काफ़ी विकास होने के कारण दूसरे प्रांत के लोग उनके विकास मॉडल को अपना रहे हैं. उनके मुताबिक़, क़ानून-व्यवस्था के नाम पर बेवजह उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करने वाले लोग दिल्ली और मुंबई का नाम क्यों नहीं लेते, जहां उत्तर प्रदेश के मुक़ाकले कई गुना ज़्यादा अपराध हो रहे हैं.

हालांकि, सरकार ने राज्य में क़ानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहरों, कस्बों और गांवों में अपराध नियंत्रण के लिए एक खाका ज़रूर खींचा है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. इतना ही नहीं, छेड़खानी, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न एवं हत्या आदि के मामले बेहिचक दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं.

पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार, ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित अवधि में पूरा कर चार्जशीट समय से कोर्ट में दाख़िल किए जाने और उसकी विवेचना में नई तकनीकी का उपयोग करने की बात कही गई है. शासन द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण किया गया है, ताकि ज़रूरत के मुताबिक़, इन प्रयोगशालाओं की सहायता ली जा सके. गृह विभाग से जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में हुई पुलिस कार्रवाई की जनपद और मंडल स्तर पर समीक्षा की जाए और महिला उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता के बयान धारा 164 सीआरपीसी में यथासंभव दर्ज कराए जाएं. इसके अलावा आवश्यकतानुसार, धारा 110 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए. ऐसे मामलों में भारी धनराशि के मुचलके भरवाए जाएं, ताकि पाबंदी की शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. हालांकि प्रशासन के इन दावों के बारे में जानकारों का कहना यही है कि आंकड़ों के लिहाज़ से भले ही उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों की तुलना में अपने को अच्छा माने, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं निकालना चाहिए कि प्रदेश में सबकुछ ठीक है.■

मुट्ठी भर पुलिसकर्मियों पर टिकी है क़ानून-व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था संभालने के लिए आईपीएस संवर्ग के 489 अफसरों की जगह सिर्फ 397 अधिकारी ही तैनात हैं. पीएसी की कई बटालियनों में सेनानायक नहीं है. विजिलेंस, ईओडब्ल्यू ,भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कई पद रिक्त हैं. पीपीएस से आईपीएस में प्रोन्नति 61 अधिकारियों के बाद भी अभी करीब सौ अधिकारियों की कमी है. अतीत में जाएं, तो प्रदेश को 2006 में आठ 2007 में छह, 2008 में पांच आईपीएस अधिकारियों की आमद हुई थी. आर्थिक अपराध के लिए एसआईटी और आतंकवाद निरोधी बलों एटीएस एवं एसटीएफ का गठन हुआ था. सी और डी कैडर के कर्मचारियों के लिए पुलिस सुधार आयोग के निर्देश हैं कि थानों का इंचार्ज केवल इंस्पेक्टरों को ही बनाया जाए, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टरों के 2274 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 616 पुलिस इंस्पेक्टर ही तैनात हैं. यानी प्रदेश में इंस्पेक्टरों के 73 फ़ीसदी पद खाली हैं. पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत लखनऊ, गाज़ीपुर और मुरादाबाद में प्रयोग शुरू कर दिया गया है, जिसे शीघ्र ही मेरठ में भी लागू किया जाएगा. इसके तहत पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर केस के बारे में जानकारी ले सकेगा. ■

फ़र्ज़ी रजिस्ट्री का मामला सामने आया

कैसे फंसी सवर्णों के चंगुल में दलितों की ज़मीन

इस मुल्क में ज़मींदारी प्रथा बेशक ख़त्म हो गई हो, लेकिन ज़ुल्म की इंतिहा जारी है. वर्षों पहले ताल्लुकेदारों को समय पर लगान न चुका पाने की वजह से ग़रीबों की ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थीं. आज़ादी मिली और ज़मींदारी उन्मूलन हुआ, लेकिन ऊंची जातियों की हनक और दलितों का शोषण बदस्तूर जारी है. एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड में प्रकाश आया है. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में...

जबर सिंह वर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड में सरकार और नौकरशाह ही ज़मीन बेचने और क़ब्ज़ाने के खेल में नहीं जुटे हैं, बल्कि गांव-कस्बों में रहने वाले स्थानीय दबंग भी शासन-प्रशासन का सान्निध्य पाकर दलितों की कृषि योग्य भूमि हथियाने में हुए जुटे हैं. ख़ासकर, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों से सटे गांवों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उनके निशाने पर हैं. स्थानीय दबंगों को न तो क़ानून का डर है और न ही समाज का. यही वजह है कि यहां के ज़्यादातर गांवों में एससी और एसटी की अधिकांश कृषि भूमि पर ऊंची जातियों के दबंगों का क़ब्ज़ा है. कई गांव तो ऐसे हैं, जहां अनुसूचित जाति के किसानों को सवर्ण बताकर उनकी ज़मीन सवर्णों ने अपने नाम करवा ली है.

चौथी दुनिया ने राजधानी से सटे टिहरी जनपद की धनोल्टी तहसील में खुर्द-बुर्द की गई दलितों की कुछ ज़मीनों की जांच-पड़ताल की, तो इस संबंध में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए. क़रीब 80 परिवारों और 300 से ज़्यादा आबादी वाले भटोली गांव में दलितों के चार परिवार पीढ़ियों से बसे हैं. सवर्णों की भांति उन्हें भी आज़ादी के बाद गांव में भूमि आवंटित हुई थी. दलित वर्ग के पदमू और पूरचंद के पास भी क़रीब 15-15 एकड़ ज़मीन थी. पहले यहां भू-माफियाओं की नज़र नहीं थी, तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही भटोली पर्यटन गांव घोषित हुआ, मानो इन दलित परिवारों पर कयामत का पहाड़ टूट पड़ा हो. ज़मीनों की बढ़ती क़ीमतें देख दबंगों ने नए-नए हथकंडे अपनाकर उनकी ज़मीनें हड़पनी शुरू कर दी. सवर्णों ने राजस्व विभाग के वकील, स्थानीय हल्का पटवारी, नायब तहसीलदार और रजिस्ट्रार से मिलकर दलितों की भूमि अपने नाम करने का रास्ता निकाला है.

नियमानुसार, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि किसी सवर्ण के नाम नहीं हो सकती. विशेष परिस्थितियों में ही ज़िलाधिकारी से स्वीकृति लेकर थोड़ी-बहुत ज़मीन सवर्ण ज़रूर ख़रीद सकते हैं. इसके लिए राजस्व विभाग से लेकर ग्राम पंचायत तक की कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती है. मालूम हो कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले और अब तक यही नियम लागू है, लेकिन सवर्णों ने इन झंझटों में पड़ने की बजाय शॉटकर्ट रास्ता निकाल लिया है. इस बाबत वे ज़िला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर कभी जबरन, तो कभी गुमराह करके दलितों से उनकी ज़मीन की रजिस्ट्रियां कराई हैं.

भटोली गांव के दलित पूरचंद के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जबकि लोक निर्माण विभाग के बेलदार पदमू की मृत्यु के बाद उसकी बहन खजानी देई को भी छला गया. वृद्ध खजानी अनपढ़ होने के साथ बोलने और सुनने में भी असमर्थ है. इसी का फ़ायदा 15 साल पहले गांव के सवर्ण गोपाल सिंह, पुत्र थापा ने उठाया. भाई की मौत के बाद ज़मीन खजानी के नाम करने के बहाने उसने क़रीब 5 बीघा ज़मीन खजानी देई से अपने नाम पर करा लिया. सभी सरकारी रिकॉर्ड छुपाकर रजिस्ट्री के समय खजानी देई को राजपूत (सवर्ण) बताया गया. हालांकि रजिस्ट्री के समय केवल तहसील से मिलने वाली खाता-खतौनी की ज़रूरत होती है, जिसमें एससी/एसटी की जाति दशाई गई होती है, लेकिन माफियाओं ने उसकी जाति भी कंप्यूटर से ग़ायब करा दी. रजिस्ट्रार कार्यालय में भूमि विक्रेता का जाति प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होता है, ताकि किसी दलित की ज़मीन धोखे से किसी सवर्ण के नाम न हो जाए. ख़रीदार गोपाल सिंह और उनके क़रीब एक दर्जन रिश्तेदारों ने भी कोर्ट में खजानी देई के सवर्ण होने का झूठा शपथ-पत्र दिया. रजिस्ट्री होने के कुछ दिनों बाद विक्रेता के गांव में राजस्व विभाग का कर्मचारी घोषणा-पत्र लेकर आता है, ताकि किसी को रजिस्ट्री पर आपत्ति हो, या गलत रजिस्ट्री हुई हो, तो म्यूटेशन से पूर्व आपत्ति दर्ज करा सकें. उसके बाद क्षेत्रीय पटवारी घोषणा-पत्र के साथ अपनी रिपोर्ट तहसील को भेजते हैं, लेकिन इस घोषणा- पत्र की भनक खजानी देई और उसके रिश्तेदारों को नहीं लगने दी गई. गोपाल सिंह ने अपने परिजनों के हस्ताक्षर करवाकर पटवारी की मिलीभगत से उसे तहसील कार्यालय भिजवा दिया. मज़ेदार बात यह है कि संबंधित पटवारी चौकी भटोली गांव में ही है और जिस समय धोखाधड़ी का यह खेल खेला गया, तब संबंधित पटवारी सुरेश लाल भी अनुसूचित जाति का ही था. हालांकि इस समय वह तहसीलदार बन चुके हैं. बावजूद इसके तत्कालीन पटवारी ने सवर्ण गोपाल सिंह के झूठे शपथ-पत्र और खजानी देई की ग़लत जाति दर्शाने जैसे पहलुओं को नज़रअंदाज़ कर एक झूठी रिपोर्ट बनाई. इतना ही नहीं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने भी बग़ैर जांच-पड़ताल किए उक्त ज़मीन का दाख़िल-ख़ारिज कर दिया.

पीड़िता खजानी देई ने चौथी दुनिया को बताया कि वर्ष 1992 में उसके भाई का निधन हुआ, तो गांव का ही गोपाल सिंह भू-स्वामित्व हस्तांतरण करने के नाम पर उसके साथ ज़िला मुख्यालय टिहरी आया था. उसने स्टांप पेपर्स पर यह कहते हुए मेरे अंगूठे लगवाए कि भू-स्वामित्व उनके नाम पर ट्रांसफर हो रहा है. दो साल पहले गांव के कुछ और लोग मेरे पास आए और अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने कहने लगे. उन्होंने ही पूर्व में गोपाल सिंह के नाम हुई मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री के बारे में बताया. तब मैं आश्चर्य में पड़ गई और तुरंत अपने बेटे को इस संबंध में बताया. उसने रिकार्ड रूम में कागज़ात खंगाले, तो सच्चाई सामने आ गई. उसके बाद मैंने ज़िलाधिकारी टिहरी से इसकी शिकायत भी की.

ठीक इसी तरह भटोली गांव के अनपढ़ पूरचंद को भी कागजों में राजपूत (सवर्ण) दर्शाकर और झूठे शपथ-पत्र देकर उसकी कई बीघा कृषि भूमि भटोली गांव के ही सवर्ण सबल सिंह, सूरत सिंह, पुत्र माडू सिंह, महिपाल सिंह, पुत्र अतर सिंह ने अपने नाम करवा ली. सबल सिंह, जयपाल सिंह, बलबीर सिंह, पुत्र खंकर सिंह उर्फ दलपति निवासी, ग्राम बनोगी ने भी पूरचंद की ज़मीन की रजिस्ट्री अपने पक्ष में कराई. इन दोनों दलित परिवारों की न केवल ज़मीनें हड़पी गईं, बल्कि उन्हें मारपीट कर गांव से खदेड़ भी दिया गया. गांव छोड़ने के बाद पूरचंद और उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसे और उनके दो बेटे सुमन और सरदार ढाबों में काम कर रहे हैं, जबकि खजानी देई पास के ही गांव में एक जर्जर मकान में रह रही है. ■

खजानी देई की फ़रियाद नहीं सुन रहा ज़िला प्रशासन

अपने गांव में दबंगों की दबंगई और सरकारी बाबुओं की कारगुजारियों का शिकार बनी भटोली गांव की वृद्ध खजानी देई को जैसे ही अपनी ज़मीन की ग़लत ढंग से हुई रजिस्ट्री का पता चला, तो वह फ़ौरन टिहरी की तत्कालीन ज़िलाधिकारी राधिका झा के पास पहुंची. डीएम ने तत्काल एसडीएम धनोल्टी को जांच के निर्देश दिए और एसडीएम ने नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय पटवारी से रिपोर्ट मांगी. 11 अक्टूबर, 2010 को ही क्षेत्रीय पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट तहसील कार्यालय को भेज दी, जिसमें लिखा गया है कि खजानी देई अनुसूचित जाति की महिला है और उसे तथ्य छुपाकर और ग़लत शपथ-पत्र देकर सवर्ण दर्शाकर भूमि की रजिस्ट्री करवाई गई है. रजिस्ट्री से पहले नियमानुसार, डीएम से भी अनुमति नहीं ली गई. पूरी रजिस्ट्री तथ्य छुपाकर और ग़लत ढंग से ही हुई है. ■

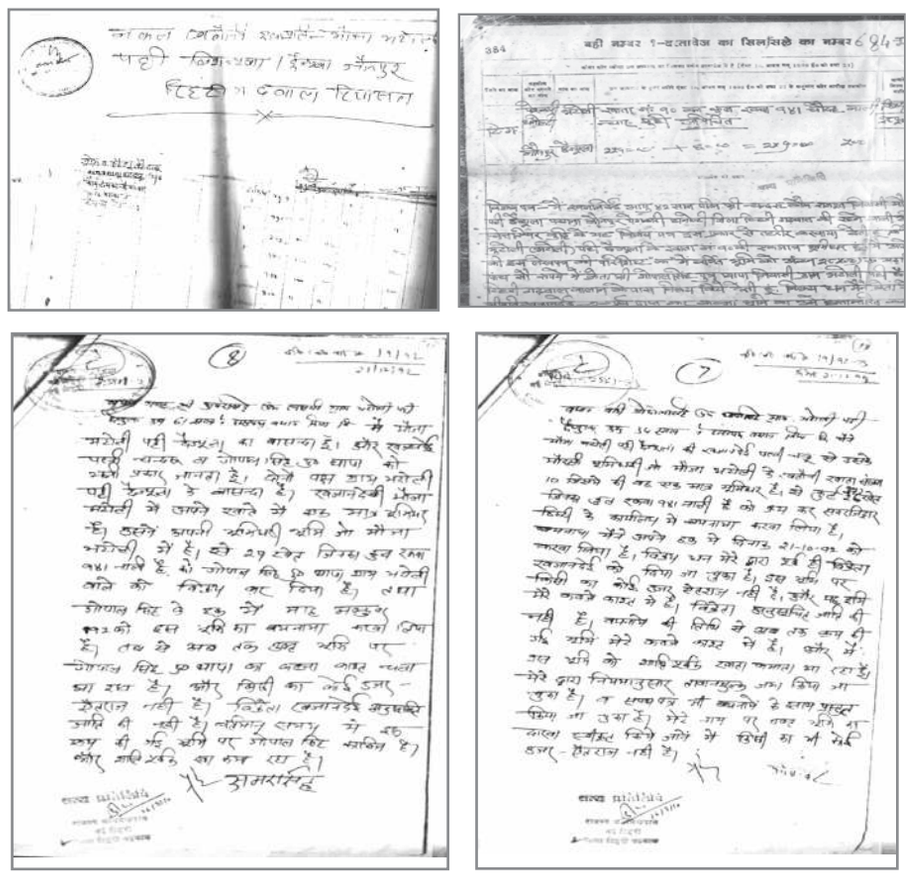

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366